



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224031
CG-DL-E-31122020-224031

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/ पौष 9, 1942

No. 380]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

(अंतिम जांच परिणाम)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

मामला सं. सीबीडी-07/2019

विषय: कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "स्टाइरिन बुटाडीन रबर" के आयातों के संबंध में सस्विडीरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 6/21/2019-डीजीटार.—यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (सस्विडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "सस्विडीरोधी नियमावली" अथवा "प्रतिकारी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मैसर्स इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड (आईएसआरपीएल) और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) (जिन्हें यहां आगे आवेदक भी कहा गया है) ने कोरिया गणराज्य (जिसे यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से स्टाइरिन

बुटाडीन रबर (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच शुरू करने के लिए अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया।

2. और जबकि, आवेदकों द्वारा दायर विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र के मद्देनजर, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संबद्ध सामानों के तथाकथित सब्सिडीकरण की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा सब्सिडीरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाती है और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 29 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/21/2019-डीजीटीआर द्वारा सब्सिडीरोधी जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले सब्सिडीरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने 09.10.2019 को कोरिया सरकार ("जीओके") को परामर्श के लिए निमंत्रण भेजा और उसके बाद 15.10.2019 को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोरिया सरकार को अनुमति देने और सब्सिडी संबंधी करार के अनुच्छेद 13 तथा प्रतिकारी उपायों के अनुसार परस्पर रूप से सहमत हल निकालने के उद्देश्य से निमंत्रण भेजा। तथापि, कोरिया सरकार ने परामर्श के लिए निमंत्रण का उत्तर नहीं दिया।
- ग. प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 29 अक्तूबर, 2019 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- घ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार ज्ञात आयातकों और अन्य हितवद्ध पक्षकारों को 29 अक्तूबर, 2019 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितवद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।
- ङ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी भेजी गई थी।
- छ. प्राधिकारी ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों, जिनमें सरकार द्वारा प्रतिकारयोग्य लाभ प्रदान किए जा सकते हैं, के संबंध में संगत तथ्य/सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी। कोरिया गणराज्य सरकार ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए जिन पर भी विचार किया गया है।
- ज. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को सब्सिडीरोधी जांच शुरू करने की सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार 40 दिन के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध देने का अवसर प्रदान किया:
 - i. मैसर्स कुम्हो पैट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
 - ii. मैसर्स एलजी केम. लिमिटेड
- झ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दिए अथवा उत्तर प्रस्तुत किए:
 - i. मैसर्स कुम्हो पैट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
 - ii. मैसर्स पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन लिमिटेड

- iii. मैसर्स एलजी कारपोरेशन लिमिटेड
 - iv. मैसर्स पंटोल लॉजिस्टिक्स कंपनी लिमिटेड
 - v. मैसर्स एसएंडआई कारपोरेशन लिमिटेड
 - vi. मैसर्स सीटेक कंपनी लिमिटेड
 - vii. मैसर्स सेवॉन कंपनी लिमिटेड
 - viii. मैसर्स एलजी केम. लिमिटेड
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं:
- i. मैसर्स जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - ii. मैसर्स बिरला टायर लिमिटेड
 - iii. मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड
 - iv. मैसर्स सीएट लिमिटेड
 - v. मैसर्स एमआरएफ लिमिटेड
 - vi. मैसर्स राल्सन (इंडिया) लिमिटेड
 - vii. मैसर्स पोद्दार टायर लिमिटेड
 - viii. मैसर्स ऑरियंटल रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - ix. मैसर्स हिंदुस्तान रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - x. मैसर्स अग्रवाल रबर लिमिटेड
 - xi. मैसर्स एक्सेल रबर प्राइवेट लिमिटेड
 - xii. मैसर्स टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - xiii. मैसर्स फोनिक्स कनवेयर बेल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - xiv. मैसर्स फोर्च इंडिया लिमिटेड
 - xv. मैसर्स गरबड़े वेस्टरेच लिमिटेड
 - xvi. मैसर्स पैरागाँन पॉलीमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड
 - xvii. मैसर्स ऑरियंटल रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - xviii. मैसर्स मिदास रबर प्राइवेट लिमिटेड
 - xix. मैसर्स सेम्परट्रांस निरलोन प्राइवेट लिमिटेड
 - xx. मैसर्स मैट्रो टायर्स लि.
 - xxi. मैसर्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - xxii. मैसर्स एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xxiii. मैसर्स गुडईयर इंडिया लिमिटेड
 - xxiv. मैसर्स ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ट. उपर्युक्त के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दायर किए:

- i. मैसर्स सीएट लिमिटेड
 - ii. मैसर्स एमआरएफ लिमिटेड
 - iii. मैसर्स जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - iv. मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड
- ठ. अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित हितवद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उत्तर देते हुए अनुरोध दायर किए: व
- i. मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
 - ii. ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- ड. आवेदकों और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे आवेदक अथवा अन्य हितवद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- ढ. जहां कहीं किसी हितवद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है।
- ण. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार व्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए हैं। प्राधिकारी ने लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- त. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 है। जांच की अवधि में 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा जांच की अवधि शामिल है।
- थ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(6) के अनुसार, 09 सितंबर, 2020 को हुई सुनवाई में सभी पक्षकारों को मौखिक रूप से विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, उन सभी को सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्ति विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें। पक्षकारों से विरोधी पक्षकारों के अगोपनीय रूपांतर साझा किए गए थे और उन्हें खंडन करने की छूट दी गई थी।
- द. आवेदकों द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। आवश्यक संशोधन के साथ सत्यापित सूचना पर ही, जहां कहीं लागू थी, पर विश्वास किया गया है।
- ध. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं विक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे यहां एनआईपी कहा गया है) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन से कम सब्सिडीरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- न. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहां भी संगत पाए गए, हल कर दिए गए हैं। जहां कहीं किसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा सूचना देने से इंकार किया गया है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्रकटन विवरण रिकार्ड किया है।
- प. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, इस अधिसूचना में सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण, जो वर्तमान अंतिम जांच परिणाम का आधार बनता है, 13 नवंबर, 2020 को हितवद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था। विभिन्न

हितवद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात विवरण पर अनुरोधों पर संगत मानी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की पुनरावृत्ति हैं। तथापि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात विवरणों की इस अंतिम जांच परिणाम में जांच की जा रही है।

- फ. प्राधिकारी ने उस सीमा तक हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों और दी गई सूचना पर विचार किया है, जहां तक वे साक्ष्यों से समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए हैं।
- व. इस अधिसूचना में *** किसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- भ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 70.82 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एसबीआर 1500 और एसबीआर 1700 सीरीज तक सीमित इमल्शन स्टाइरिन बुटाडीन रबर (जिसे यहां आगे "ई-एसबीआर" कहा गया है) है।

यह दो कारकों अर्थात् स्टाइरिन और बुटाडीन से तैयार किया जाता है। इन दो कारकों का पॉल्यूमराइजेशन दो प्रक्रियाओं अर्थात् सॉल्यूशन (एस-एसबीआर) से अथवा इमल्शन (ई-एसबीआर) के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एसबीआर तक सीमित है जो इमल्शन प्रक्रिया अर्थात् ई-एसबीआर से आता है।

इस उत्पाद का प्राथमिक प्रयोग टायरों और टायर रिट्रेड मिश्रणों के उत्पादन में होता है। ई-एसबीआर के प्रयोग के अन्य क्षेत्रों में हाउसवेयर मैट, ड्रेन बोर्ड ट्रेज, शू सोल और हील्स, च्युइंगम, फूड कंटेनर सीलेंट्स, टायर, कनवेयर बेल्ट्स, स्प्रोंज आर्टिकल्स, एडेथिक्स और कॉक्स, ऑटोमोबाइल मैट्स, ब्रेक और क्लच पैड्स, होज, वी-बेल्स, फ्लोरिंग, मिलिट्री टैंक पैड्स, हार्ड रबर बैटरी बॉक्स केसेस, एक्सट्रूडेड गार्स्केट, रबर

टॉयज, मोल्डेड रबर गुड्स, शू सोलिंग, केबिल इंसुलेशन एंड जैकेटिंग, फार्मास्युटिकल, सर्जिकल और सैनिटरी उत्पाद, फूड पैकेजिंग आदि शामिल हैं।

विचाराधीन उत्पाद उप-शीर्ष 400219 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद स्टाइरिन बुटाडीन रबर है। स्टाइरिन बुटाडीन रबर (एसबीआर) स्टाइरिन और बुटाडीन से तैयार किए गए सिंथेटिक रबरों के वर्ग को वर्णित करता है।
- ख. एसबीआर दो कारकों, स्टाइरिन और बुटाडीन से तैयार किया जाता है। इन दो कारकों का मिश्रण दो प्रक्रिया सॉल्यूशन (एस-एसबीआर) से अथवा इमल्शन (ई-एसबीआर) के रूप में पॉल्यूमराइज किया जाता है।
- ग. ई-एसबीआर का उत्पादन इमल्शन पॉल्यूमराइजेशन से किया जाता है जो फ्री रेडिकल्स से शुरू किया जाता है। रिएक्शन वेसेल विशिष्ट रूप से दो कारकों, फ्री रेडिकल जेनरेटर और चैन ट्रांसफर एजेंट, यथा अल्काइल मर्केप्टन, से विशिष्ट रूप से चार्ज किए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद ई-एसबीआर है।
- घ. अधिकतर एसबीआर टायरों के विनिर्माण में खपाया जाता है। इस प्रकार, एसबीआर के लिए मांग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग पर आधारित है।
- ङ. इमल्शन पॉल्यूमराइज्ड स्टाइरिन बुटाडीन रबर (ई-एसबीआर) विश्व में सबसे अधिक प्रयुक्त एक पॉलीमर है। एसबीआर की स्टाइरिन कंटेंट, पॉल्यूमराइजेशन और तापमान स्टेनिंग अथवा नॉन-स्टेनिंग एंटीऑक्सीडेंट, ऑयल एवं कार्बन ब्लैक मात्रा के आधार पर बहुत-सी किस्में हैं। इनमें प्रत्येक आधारभूत वर्गीकरणों में मूनीविस्कोसिटीज, कोगुलेशन टाइम्स,

इमल्शफायर टाइप, ऑयल लेवल और कार्बन ब्लैक टाइप्स तथा लेवल के संबंध में एसबीआर पॉलीमर की किस्में शामिल हैं। ई-एसबीआर के आधारभूत समूहों 1000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 हैं।

- च. एसबीआर 1500, 1700 और 1900 सीरीज का भारत में उत्पादन किया जाता है। निर्यातकों और उत्पादकों के पास एसबीआर 1500, 1700 और 1900 सीरीज का परस्पर परिवर्तनीय रूप से उत्पादन करने की क्षमता है। तथापि, घरेलू उद्योग 1900 सीरीज का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है और इसीलिए 1900 सीरीज को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।
- छ. विदेशी उत्पादक संभवतः एसबीआर 1500, 1700 और 1900 सीरीज का परस्पर परिवर्तनीय रूप से उत्पादन कर सकते हैं, याचिकाकर्ता एसबीआर 1900 सीरीज का उत्पादन नहीं कर सकते। न तो रिलायंस और न ही आईएसआरपीएल (संबद्ध सामानों के अन्य उत्पादक) एसबीआर 1900 सीरीज का उत्पादन कर सकते हैं। उनके द्वारा चालू किया गया संयंत्र एसबीआर 1900 सीरीज का उत्पादन नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, एसबीआर 1500 और 1700 के उपभोक्ता एसबीआर 1900 सीरीज के उत्पाद की खपत नहीं कर सकते।
- ज. एसबीआर के विभिन्न ग्रेडों की परस्पर परिवर्तनीयता दो विभिन्न सीरीज के तहत आने वाले ग्रेडों के बीच संभव है। उदाहरण के लिए, एसबीआर के 1712 ग्रेड को 1500 ग्रेड और यहां तक कि टायर ट्रीड अनुप्रयोग में भी 1500 तथा 1700 सीरीज के तहत आने वाले रबर के अन्य कई ग्रेडों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार, एसबीआर के 1502 ग्रेड को 1500 ग्रेड और विभिन्न अनुप्रयोगों में 1500 तथा 1700 सीरीज के तहत आने वाले रबर के अन्य कई ग्रेडों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- झ. वर्तमान याचिका एसबीआर 1500 सीरीज और एसबीआर 1700 सीरीज से संबंधित है। एसबीआर 1900 सीरीज को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशेष रूप से अलग किया गया है।
- ञ. विचाराधीन उत्पाद उप शीर्ष 400219 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। विचाराधीन उत्पाद का आयात 40021910, 40021990, 40021920, 40021930 और 40022000 किया गया है।
- ट. याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है और उन्हें हल किया गया है:
8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एसबीआर 1500 और एसबीआर 1700 सीरीज तक सीमित इमल्शन स्टाइरिन बुटाडीन रबर (जिसे यहां आगे "ई-एसबीआर" कहा गया है) है।
9. एसबीआर दो कारकों अर्थात् स्टाइरिन और बुटाडीन से तैयार किया जाता है। इन दो कारकों का पॉल्यूमराइजेशन दो प्रक्रियाओं अर्थात् सॉल्यूशन (एस-एसबीआर) से अथवा इमल्शन (ई-एसबीआर) के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद इमल्शन एसबीआर तक सीमित है। सॉल्यूशन एसबीआर वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर है।
10. एसबीआर का प्राथमिक प्रयोग टायरों और टायर रिट्रेड मिश्रणों के उत्पादन में होता है। ई-एसबीआर के प्रयोग के अन्य क्षेत्रों में हाउसवेयर मैट, ड्रेन बोर्ड ट्रेज, शू सोल और हील्स, च्युइंगम, फूड कंटेनर सीलेंट्स, टायर, कनवेयर बेल्ट्स, स्पोज आर्टिकल्स, एडेथिक्स और कॉक्स, ऑटोमोबाइल मैट्स, ब्रेक और क्लच पैड्स, होज, वी-बेल्स, फ्लोरिंग, मिलिट्री टैंक पैड्स, हार्ड रबर बैटरी बॉक्स केसेस, एक्सट्रूडेड गार्सकेट, रबर टॉयज, मोल्डेड रबर गुड्स, शू सोलिंग, केबिल इंसुलेशन एंड जैकेटिंग, फार्मास्युटिकल, सर्जिकल और सैनिटरी उत्पाद, फूड पैकेजिंग आदि शामिल हैं। तथापि, इस उत्पाद का प्रयोग पूर्व प्रभावी रूप से टायरों के उत्पादन में किया जाता है।

11. यह उत्पाद उप-शीर्ष 400219 के तहत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, इस उत्पाद के आयात सीमा शुल्क वर्गीकरण 400220 के तहत सूचित किए गए हैं। इन आयातों को वर्तमान निर्धारण के प्रयोजन के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण में शामिल किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

12. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- आवेदक विचाराधीन उत्पाद के एकमात्र उत्पादक हैं और इस प्रकार पूरा भारतीय उत्पादन उन्हीं का है।
 - आवेदकों ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
 - आवेदक न तो संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों अथवा निर्यातकों से संबद्ध हैं और न ही भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं।
 - आवेदन पत्र नियमावली की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के गठन और उसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किये हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. सस्मिडीरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:
- "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।"*
15. यह आवेदन पत्र भारत में संबद्ध सामानों के दोनों उत्पादकों अर्थात् मैसर्स इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड (आईएसआरपीएल) और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। आवेदकों ने घोषित किया कि न तो उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध उत्पाद के किसी आयातक/निर्यातक से संबद्ध हैं। आवेदकों द्वारा किए गए दावे में कोई विवाद नहीं है। आयात आंकड़े कोरिया गणराज्य से आवेदक कंपनियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं दर्शाते। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं और आवेदन पत्र नियमावली के नियम 6(3) के तहत आधार के मानदंड पूरा करता है।

ङ. विविध अनुरोध

ङ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

16. घरेलू उद्योग निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:
- सीवीडी मार्जिन में पाटन मार्जिन के असमान जांच की अवधि में वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। अतः सबसे हाल की अवधि में सीवीडी मामले में और सीवीडी मार्जिन के मद्देनजर किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।
 - जांच की शुरुआत के समय जांच की अवधि के क्षेत्र को शासित करने वाला कोई कानून अथवा नियम नहीं था। नियम पुस्तिका में केवल दिशा-निर्देशों का प्रावधान है।
 - पाटनरोधी जांच में उत्तरदाता उत्पादकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन की तुलना में कम था।
 - कोई भी आवेदक टायरों का विनिर्माण करने के व्यापार में नहीं लगा हुआ है जहां एसबीआर का प्रयोग पाया जाए, अतः कोई कैप्टिव खपत नहीं हो सकती।

- (v) हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित व्यापार सूचना पाटनरोधी जांचों में लागू है। इसका संदर्भ प्रतिकारी शुल्क में देना अनुपयुक्त है।

ड.2 अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोध

17. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- (i) जांच की शुरुआत और जांच की अवधि के अंत के बीच सात माह का अंतराल है। नियम पुस्तिका और नियम के अनुसार जांच की अवधि जांच की शुरुआत की तारीख को 6 माह से पुरानी नहीं हो सकती।
- (ii) पाटनरोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क साथ रखकर क्षति मार्जिन से अधिक नहीं हो सकते।
- (iii) आवेदकों ने प्रपत्र क से ठ, एसबीआर 1500 और एसबीआर 1700 के ग्रेडों से संबंधित आंकड़ों, सब्सिडी के लिए उल्लिखित रिपोर्ट, विनिर्माण प्रक्रिया, कच्ची सामग्री के नाम, कैप्टिव खपत, विक्री अथवा उत्पादन के दिवसों की संख्या के रूप में मालसूची, एनआईपी और आरएंडडी खर्चों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- (iv) गोपनीयता के लिए कारण दर्शाते हुए व्यापार सूचना के तहत अपेक्षित कोई औचित्य की तालिका याचिका के भाग के रूप में नहीं दी गई है।
- (v) घरेलू उद्योग के लिए यह अपेक्षित है कि वे आयात आंकड़ों के अपने गौण स्रोत की अगोपनीय प्रति उपलब्ध कराएं।
- (vi) याचिकाकर्ता विभिन्न मंचों पर जा रहा है और वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से पाटनरोधी तथा सीवीडी उपायों के रूप में अनुचित संरक्षण की मांग कर रहा है।
- (vii) घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के रूप में 2001 से संरक्षण प्राप्त कर रहा है जो कि अब भी चल रहा है और 2022 तक लागू है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. सूचना की गोपनीयता के संबंध में सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना (1) नियम 7 के उपनियमों (1), (2), (3) और (7), नियम 14 के उप नियम (2), नियम 17 के उपनियम (4) और नियम 19 के उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 6 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे। (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है। (3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

19. प्राधिकारी ने निरीक्षण के लिए विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितवद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
20. प्राधिकारी मानते हैं कि ऐसी सूचना को प्रकट करना किसी पक्षकार के लिए जरूरी नहीं है जिसकी गोपनीयता कानून के तहत संरक्षित हो। हितवद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितवद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का

पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितवद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

21. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि जांच की शुरुआत और जांच की अवधि के बीच 7 माह का अंतराल है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि 6 माह से अधिक का अंतराल है तो जांच की शुरुआत निर्धारित करने के लिए कोई प्रतिबंध अथवा नियम नहीं है। केवल आवेदन पत्र दायर करने के संबंध में समय-सीमाएं थीं और उनका अनुपालन किया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि वर्तमान जांच एक सीवीडी जांच है, अतः कोरिया सरकार को परामर्श का अवसर प्रदान किया गया था। कोरिया सरकार को 09.10.2019 और फिर 15.10.2019 को परामर्श के लिए निमंत्रण भेजा गया था, तथापि कोरिया सरकार ने दोनों निमंत्रणों का उत्तर नहीं दिया, अतः प्राधिकारी द्वारा मानी गई जांच की अवधि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि उपयुक्त है।
22. जहां तक विशेष देशों से उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी एवं प्रतिकारी शुल्क, दोनों लगाए जाने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि धारा 9ख(क) में यह प्रावधान है कि किसी भी वस्तु को पाटन अथवा क्षति निर्यात सब्सिडीकरण की समान स्थिति के लिए प्रतिपूर्ति करने हेतु प्रतिकारी शुल्क और पाटनरोधी शुल्क, दोनों के अध्यधीन नहीं रखा जाएगा। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद पर पाटन एवं प्रतिकारी शुल्क, दोनों लगाने के लिए भारतीय कानूनों अथवा डब्ल्यूटीए करारों के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल प्रतिबंध यह है कि किसी भी वस्तु को पाटन और निर्यात सब्सिडीकरण की समान स्थिति के लिए प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिकारी शुल्क और पाटनरोधी शुल्क, दोनों के अध्यधीन नहीं रखा जाएगा।
23. निर्यातक द्वारा प्राप्त निर्यात सब्सिडियों से निर्यातक निर्यात कीमत कम करने में सक्षम होता है। इस प्रकार, निर्यात सब्सिडियां सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच अंतर बढ़ाती हैं और इसके परिणामस्वरूप अधिक पाटन मार्जिन होता है। पाटनरोधी शुल्क, जो पाटन मार्जिन की पूर्ण मात्रा तक लगाया जा सकता है, निर्यात सब्सिडियों से हुए निर्यात कीमत में ह्रास का उपचार करती हैं। ऐसी स्थिति में, प्रतिकारी शुल्क लगाकर निर्यात सब्सिडियों से हुए इस ह्रास का उपचार करने की और कोई आवश्यकता नहीं है।
24. स्टाइरिन बूटाडीन रबर पर पाटन मार्जिन की पूर्ण मात्रा तक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और इसीलिए निर्यात सब्सिडीकरण पर प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने प्रत्येक सब्सिडी कार्यक्रम की प्रकृति का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी ने निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक सब्सिडी मात्रा में सब्सिडियों को अलग-अलग किया है अर्थात् निर्यात सब्सिडी और सब्सिडी, जो निर्यात निष्पादन अर्थात् घरेलू सब्सिडियों पर आकस्मिक नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुल प्रतिकारी शुल्क निर्धारित करते समय वर्तमान मामले में कोई दोहरा उपाय नहीं है, प्राधिकारी को उन प्रतिकारी सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन नहीं जोड़ना चाहिए जो निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक हैं। तथापि, वर्तमान जांच में कोई प्रतिकार योग्य निर्यात सब्सिडियां नहीं हैं। प्राधिकारी ने तदनुसार प्रतिकारी शुल्क निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए घरेलू सब्सिडियों हेतु सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है।
25. इसके अतिरिक्त, पाटन एवं प्रतिकारी शुल्क नियम दोनों में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करेंगे जो यदि लगाई जाती है और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि पाटनरोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क की कुल मात्रा क्षति मार्जिन से अधिक न हो।
26. अतः प्राधिकारी ने यह सुनिश्चित किया है कि पूर्व पाटनरोधी जांचों में निर्धारित पाटनरोधी शुल्क और इस सब्सिडी/सीवीडी जांच में निर्धारित प्रतिकारी मार्जिन पूर्व पाटनरोधी जांचों तथा वर्तमान सब्सिडीरोधी जांचों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन से अधिक न हो।
27. जहां तक पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क, दोनों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि धारा 9ख(क) में यह प्रावधान है कि किसी भी वस्तु को पाटन अथवा क्षति निर्यात सब्सिडीकरण की समान स्थिति के लिए प्रतिपूर्ति करने हेतु प्रतिकारी शुल्क और पाटनरोधी शुल्क, दोनों के अध्यधीन नहीं रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, चूंकि पाटन एवं प्रतिकारी शुल्क नियम दोनों में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करेंगे जो यदि लगाई जाती है और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है और यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की मात्रा पाटन मार्जिन की सीमा तक है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) की मात्रा का मूल्यांकन करते समय पूर्व जांच और वर्तमान जांच में निर्धारित क्षति मार्जिन पर भी विचार किया है।

28. जहां तक 2001 से लागू शुल्कों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि दिनांक 24 अगस्त, 1999 की अधिसूचना संख्या 107/99-सीमा शुल्क द्वारा जापान, ताइवान, टर्की, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टाइरिन बुटाडीन रबर के आयातों पर लगाए गए शुल्क। 1500 और 1700 सीरीज के एसबीआर के आयातों पर शुल्क 03 जुलाई, 2001 की डीजीटीआर अधिसूचना तथा 31 मई, 2002 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 56/2002 द्वारा की गई मध्यावधि समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणाम से समाप्त किए गए थे। अतः, उसके बाद और 2017 में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से पूर्व संबद्ध सामानों के आयातों पर कोई शुल्क नहीं था।

सब्सिडी का मूल्यांकन – सिद्धांत एवं मानदंड (उत्पादकों और निर्यातकों को अगोपनीय प्रति)

च. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

29. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में जांच की शुरुआत से पूर्व वर्तमान जांच शुरू करने के लिए संबद्ध देश में प्रतिकार योग्य सब्सिडियों की मौजूदगी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिया गया है। कोरिया गणराज्य सरकार (जीओके) को परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था, परंतु उन्होंने प्राधिकारी द्वारा भेजे गए निमंत्रण का उत्तर न देना चुना। संबद्ध देश तथा कोरिया सरकार में संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी गई थी कि वे प्रश्नावली का उत्तर दायर करें और उन सब्सिडियों, यदि कोई हों, की मौजूदगी तथा मात्रा का उपयुक्त निर्धारण करने के लिए तथाकथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में सत्यापनीय साक्ष्य प्रदान करने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया था।
30. कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स कं. लि. (जिसे यहां आगे "केकेपीसी" अथवा "कुम्हो" कहा गया है) कोरिया गणराज्य के वाणिज्यिक कानूनों के तहत स्थापित एक लिमिटेड देयता कंपनी है। केकेपीसी कंपनी अपने प्रमुख व्यापार के रूप में सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रेसिन्स, विशेषता वाले रसायनों, इलैक्ट्रॉनिक रसायनों, ऊर्जा, भवन निर्माण सामग्री और उन्नत सामग्री के उत्पादन एवं विक्री में लगा हुआ है। कुम्हो कोरिया गणराज्य से संबद्ध सामानों का उत्पादक और निर्यातक है। कुम्हो द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान कुम्हो द्वारा भारतीय ग्राहकों को और साथ ही पोसोको के माध्यम से भी भारत को सीधे ही निर्यात किए जाते हैं। केकेपीसी ने जांच की अवधि में भारत को विचाराधीन उत्पाद के 29622 मी. टन का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया है और उनके द्वारा प्राप्त लाभों के संबंध में सूचना प्रदान की है।
31. प्राधिकारी ने डेस्क अध्ययन के आधार पर संभावित सीमा तक कुम्हो और पोस्को द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया है और उन कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किया गया था अथवा लगाया गया था। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि सब्सिडी कार्यक्रमों से ऋणों, अनुदानों और परित्यक्त राजस्व जो अन्यथा देय था, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान हुआ। परिणामस्वरूप, कुम्हो और पोस्को को इन अनुदानों के प्राप्तकर्ता के रूप में लाभ प्रदान किया गया था। सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी थे क्योंकि वे कुम्हो और पोस्को, कोरिया गणराज्य सहित कुछ उद्यमों के लिए सीमित थे।
32. यह नोट किया जाता है कि एलजी केम. लिमिटेड (जिसे यहां आगे एलजी भी कहा गया है) ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। मैसर्स एलजी केम. लिमिटेड संबद्ध सामानों का उत्पादक/निर्यातक है जिसने जांच की अवधि के दौरान सीधे ही भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि एलजी के निम्नलिखित संबद्ध पक्षकारों ने भी अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:
- एलजी कारपोरेशन
 - पंटोस लॉजिस्टिक्स कंपनी लिमिटेड
 - एसएंडआई कारपोरेशन
 - सीटेक कं. लि.
 - सर्व वन कं. लि.
33. कोरिया सरकार से भी प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हो गए हैं।

आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों का सामान्य अवलोकन

च.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

34. सब्सिडी के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. कार्यक्रम 1 के तहत, जो कंपनी कारपोरेट पुनर्गठन की प्रक्रिया में है, वह मूल तथा ब्याज के लिए ऋणदाता के दायित्व के निर्वाह अथवा ऋणों के पुनर्भुगतान, कटौती के विस्तार अथवा निवेश में ऋणों के परिवर्तन के लिए पात्र हैं।

- ख. कार्यक्रम 2 के तहत, निर्यातक को उस आयातित उत्पादन पर दिए गए शुल्क पर शुल्क वापसी की अनुमति दी जाती है जिसकी खपत निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में की जाती है।
- ग. कार्यक्रम 3 के तहत, कोरिया सरकार कोरिया गणराज्य में उत्पादकों तथा निर्यातकों को अनुदानों के रूप में विभिन्न सब्सिडियां देती है।
- घ. कार्यक्रम 4 के तहत, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगे किसी उद्यम को कर लाभ तथा ऋण प्रदान किए जाते हैं।
- ङ. कार्यक्रम 5 के तहत, कोई पात्र कंपनी कर कटौतियों तथा अनुदानों के रूप में लाभ प्राप्त करती है।
- च. कार्यक्रम 6 के तहत, उद्यम ऋण की कम दर पर ऋण तथा निर्यात वित्तपोषण, गारंटी और बिल छूट जैसे विभिन्न अन्य निर्यात लाभों के लिए पात्र हैं।
- छ. ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं जो यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश में निर्यातकों ने अनुदानों, ऋणों, कर प्रोत्साहनों, इक्विटी अंतर्निवेश, रियायती दरों पर निर्यात ऋण, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तु एवं सेवाएं, जो प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान करते हैं, के रूप में सब्सिडियां प्राप्त की हैं और ये लाभ सामान्यतः कोरिया में सभी कंपनियों को प्रदान नहीं किए जाते हैं।
- ज. ये कार्यक्रम एएससीएम और नियमावली के अनुसार कार्रवाई योग्य सब्सिडियां हैं।
- झ. कुम्हो पॉलीकेम, कुम्हो मित्सुई केमिकल्स, कुम्हो ट्रेडिंग, कुम्हो टीएंडएल और कोरिया एनर्जी पावर प्लांट कुम्हो इंटरनेशनल से संबद्ध हैं और इस प्रकार कुम्हो से संबद्ध हैं, परंतु उन्होंने उत्तर दायर नहीं किए हैं।
- ञ. किसी कंपनी विशेष ने सेवाएं अथवा इनपुट अथवा निधियां नहीं दी हैं, एक वास्तविक मामला है तथा इसकी जांच तभी की जा सकती है जब प्रत्येक संबद्ध कंपनी के संबंध में पूर्ण सूचना निर्यातक द्वारा दी जाए।
- ट. एलजी की सभी अनुबंधित कंपनियों ने उनकी वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किए गए अनुसार उत्तर दायर नहीं किया है।
- ठ. दायर उत्तर में कोई सूचना नहीं दी गई है जो यह सिद्ध करे कि संबद्ध कंपनी में सामानों का उत्पादक शुल्क वापसी के लिए कैसे पात्र है, जबकि उसने खुद उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।
- ड. यह तथ्य कि 13 बैंकों, व्यवस्था में कुम्हो को जिन्होंने ऋण दिए, में से 3 बैंक केडीबी, केईवीआईके और आईवीके सरकारी बैंक हैं जो यह दर्शाता है कि यह योजना उन कंपनियों द्वारा प्रचालित की जाती है जो सार्वजनिक निकाय हैं।
- ढ. एलजी ने अपूर्ण उत्तर दायर किया है और इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी है कि उसने कारपोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) लाभ प्राप्त किया है या नहीं, जैसा कि आरोप लगाया गया है। सीडीआर योजना किसी उत्पाद विशेष को प्रदान नहीं की जाती, अतः एलजी द्वारा दायर उत्तर को इस आधार पर रद्द किए जाने की आवश्यकता है कि उन्होंने केवल यह उल्लेख किया है कि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान अथवा औसत उपयोगी जीवनकाल (एयूएल) के लिए संबद्ध सामानों हेतु सीडीआर प्राप्त नहीं किया है।
- ण. चूंकि सरकार और निर्यातक, दोनों जिन्होंने उत्तर दायर किए हैं, ने यह सिद्ध करने के लिए अपेक्षित सूचना नहीं दी है कि इनपुट पर प्रदत्त शुल्क की वापसी के लिए एएससीएम के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया है, यह दावा कि वापसी प्रणाली इनपुट पर प्रदत्त सीमा शुल्क की ही छूट की अनुमति देता है, रद्द किए जाने की आवश्यकता है।
- त. सरकार द्वारा कंपनी को दिए जाने वाले किसी भी अनुदान का कंपनी द्वारा उत्पादित सभी उत्पादों पर प्रभाव है, अतः उत्तरदाता निर्यातक के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह सिद्ध करें कि प्राप्त विभिन्न अनुदानों के लाभ सभी विचाराधीन उत्पाद पर संबद्ध नहीं हैं।
- थ. कुम्हो की एक अनुबंधित कंपनी कोरिया एनर्जी पावर प्लांट ने कार्यक्रम 4 के तहत लाभ प्राप्त किए ही हैं, परंतु प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।
- द. एलजी और कुम्हो, दोनों ने कार्यक्रम 5 के तहत लाभ प्राप्त करने की बात स्वीकार की है।
- ध. कोरिया सरकार ने औद्योगिक परिसर में रियल एस्टेट के लिए स्थानीय कर में कटौती के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।
- न. कुम्हो ने सशर्त ऋण प्राप्त किया है और किसी भी उत्पाद/प्रचालन के लिए उनके द्वारा प्राप्त ऋण पर वर्तमान प्रयोजनों के लिए भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

- प. कुम्हो और कोरिया सरकार अपने उत्तरों में आरएसएलटीए के तहत विभिन्न स्थानीय कर कटौतियों को सूचित करने में विफल रहे हैं जिससे उनका उत्तर रद्द किए जाने योग्य है।
- फ. एलजी और कुम्हो, दोनों पोहांग योंगिल और ग्वांगगांग पत्तनों के माध्यम से किए गए निर्यातों पर स्थानीय सरकार द्वारा दिए गए लाभों को सूचित करने में विफल रहे हैं।
- व. कोरिया सरकार अनुरोध में श्रम लागत सहायतों के संबंध में सब्सिडियां सूचित करने में विफल रही है जिससे प्रतिकार योग्य सब्सिडी बनती है। इसके अतिरिक्त, कुम्हो और एलजी ने अपने उत्तर में इस योजना को सूचित नहीं किया है जिससे वह रद्द करने योग्य है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

35. सब्सिडी के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- (i) विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और निर्यात में शामिल न होने वाली संबद्ध कंपनियों द्वारा प्राप्त लाभ और उत्तरदाताओं को कच्ची सामग्री की आपूर्ति न करना असंगत है तथा इसलिए उनके लिए उत्तर दायर करना अपेक्षित नहीं है।
- (ii) एयूएल कोरिया सरकार और उत्तरदाताओं द्वारा दायर उत्तर पर आधारित होना चाहिए न कि 18 वर्षों के घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार।
- (iii) सीवीडी शुल्क की निर्यातों पर सिफारिश नहीं की जा सकती क्योंकि कम निर्यात कीमत का उपचार पाटनरोधी शुल्क लगाकर कर दिया गया है। निर्यात सब्सिडियों के कारण होने वाली कोरियाई उत्पादकों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच कीमत संबंधी किसी अंतर का प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क के माध्यम से पहले ही समाधान कर दिया गया है। कार्यक्रम 2 और कार्यक्रम 6 के कारण होने वाले शुल्कों की सिफारिश से दोहरा उपचार होगा।
- (iv) एससीएम करार के अनुसार, ऐसे करें का प्रेषण, जो उनसे अधिक की राशि में नहीं हैं, जो प्रोद्भूत है, सब्सिडी नहीं मानी जाएगी। सीमा शुल्क की वापसी अधिनियम के अनुसार यदि सामानों के निर्यात के लिए प्रयोग किया गया है तो सीमा शुल्क अधिकारी निर्यात के लिए कच्ची सामग्री, जो ऐसे सामानों के लिए प्रयुक्त की गई है, पर सीमा शुल्क आदि की वापसी करेगा।
- (v) यदि शुल्क वापसी का आरोप आयात प्रभारों से अधिक होने के रूप में लगाया जाता है तो प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे सीवीडी के अनुबंध-II के भाग 2(II) के पैरा 1 पर विचार करें।
- (vi) शुल्क वापसी योजना में प्रेषण दो पद्धतियों से होता है - सरलीकृत निर्धारित राशि की वापसी पद्धति तथा व्यक्तिगत पद्धति। उत्तरदाता सरलीकृत निर्धारित राशि पद्धति के तहत प्रेषण प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि यह केवल लघु से मध्यम आकार के उद्यम के लिए ही उपलब्ध है जिनकी शुल्क वापसी राशि 600 मिलियन केआरडब्ल्यू से कम है। तथापि, उत्तरदाता व्यक्तिगत पद्धति के तहत पात्र है जो कोरिया से कोटेड फ्री शीट पेपर में यूएसडीओसी द्वारा निर्धारित है। शुल्क वापसी की व्यक्तिगत पद्धति प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्रदान नहीं करती।
- (vii) "कंपनी क्रेडिट रॉल्यूटरी एग्रीमेंट" सीवीए की शर्तों के अनुसार की गई पुनर्गठन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा वित्तीय अंशदान नहीं होता।
- (viii) घरेलू उद्योग ने इस विवादित कार्यक्रम/योजना की विशेष रूप से पहचान नहीं की है जो विचाराधीन उत्पाद पर प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्रदान कर रही है और न ही विवादित कार्यक्रम/योजना का साक्ष्य दिया है जो विचाराधीन उत्पाद के लिए लाभ प्रदान कर रही है, परंतु केवल किसी सकारात्मक साक्ष्य के बिना अवधारणा बनाई है। इसके अतिरिक्त, याचिका में सब्सिडी मार्जिन की मात्रा नहीं दी गई है।
- (ix) कारपोरेट पुनर्गठन संवर्धन:

क. कारपोरेट पुनर्गठन संवर्धन के लिए वर्तमान कानून प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्रदान नहीं करता।

- ख. केईएक्सआईएम, केडीबी, कोओएफसी जैसी वित्तीय संस्थाएं सार्वजनिक निकाय नहीं हैं – यूएस-कार्बन स्टील (इंडिया) में अपीलिय निकाय का संदर्भ दिया गया है।
- ग. लगाए गए आरोपों के विपरीत सीपीआरए कंपनियों को किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं करता।
- घ. सीपीआरए के लिए अनुच्छेद 2.1(ख) की अपेक्षा निर्धारित की गई है और इस प्रकार सब्सिडी के लिए नहीं बनती।

(x) शुल्क वापसी:

- क. एएससीएम केवल लगाई गई/प्रोद्भूत राशि के अतिरिक्त आयात प्रभारों की वापसी प्रतिबंधित करता है।
- ख. कोरिया का डीडीवी कानून अधिक मात्रा में शुल्क छूट की स्थिति में अतिरिक्त छूट का संग्रहण अधिदेशित करता है और इसमें इस संबंध में प्रक्रिया का भी प्रावधान है। चूंकि यह योजना एएससीएम के तहत वैधता की अपेक्षाओं को पूरा करती है, अतः उसे प्रतिकारित नहीं किया जा सकता।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई रिपोर्ट (शुल्क वापसी प्रणाली में सुधार के लिए अध्ययन) में कुम्हो और एलजी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त वापसी के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।
- घ. कोरिया गणराज्य से कोटेड फ्री शीट पेपर का निर्णय जापान अन्य उत्पाद के लिए है और इसीलिए कोरिया गणराज्य की शुल्क वापसी योजना के साक्ष्य के रूप में उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

(xi) नवीकरणीय ऊर्जा गठन नीति:

- क. चूंकि कर कटौती निधियों का सीधा अंतरण नहीं है, अतः इस तरीके से सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता।
- ख. संबंधित कानून (आरएसटीए 2018 की धारा 25(1)(2) और आरएसटीए की धारा 25-2) उद्यम अथवा क्षेत्र विशिष्ट नहीं हैं, क्योंकि इसमें बहुविध क्षेत्रों में भारी संख्या में उद्यमों के रूप में एसएमई तथा एमएसई शामिल हैं।
- ग. आरएसटीए का अनुच्छेद 10-2 - इस कार्यक्रम के तहत कर कटौतियां उन सभी कंपनियों के लिए लागू हैं जिन्होंने अलग खाते में आरएंडडी परिसंपत्तियां रखी हैं और वर्तमान कार्यक्रम विचाराधीन उत्पाद पर प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए नहीं समझा जा सकता।
- घ. आरएसटीए का अनुच्छेद 11 - इस कार्यक्रम के तहत कर कटौतियां उन सभी कंपनियों के लिए लागू हैं जिन्होंने अवसंरचना के विस्तार में निवेश किया है और वर्तमान कार्यक्रम विचाराधीन उत्पाद पर प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए नहीं समझा जा सकता।
- ङ. आरएसटीए का अनुच्छेद 12 - इस कार्यक्रम के तहत कर कटौतियां उन सभी एसएमई और व्यक्तियों के लिए लागू हैं जिन्होंने पेटेंट अधिकार और जानकारी अंतरित की है। अतः वर्तमान कार्यक्रम विचाराधीन उत्पाद पर प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए नहीं समझा जा सकता।
- च. आरएसटीए का अनुच्छेद 12-2 - इस कार्यक्रम के तहत कर कटौतियां विशेष अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में सभी कंपनियों कंपनियों के लिए लागू हैं।
- छ. आरएसटीए का अनुच्छेद 18 - इस कार्यक्रम के तहत कर कटौतियां कोरिया गणराज्य में कार्यरत विदेशी राष्ट्रिकों के लिए लागू हैं और विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध नहीं हैं।
- ज. आरएसटीए का अनुच्छेद 26 - इस कार्यक्रम के तहत कर कटौतियां सभी एसएमई, "पारगमन कंपनियों" और उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाली किसी भी अन्य कंपनी के लिए लागू हैं। वर्तमान कार्यक्रम विचाराधीन उत्पाद पर प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए नहीं समझा जा सकता।
- झ. एलजी केम. की वार्षिक रिपोर्ट में सूचित संबद्ध कंपनियों के साथ लेन-देन के संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि मैसर्स एलजी केम. लिमिटेड ने अपने सेवा प्रदाताओं अर्थात् मैसर्स एलजी कॉर्पोरेशन (संबंधित निवेश

कंपनी), मैसर्स पंटोस लॉजिस्टिक्स कंपनी लिमिटेड (लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी), मैसर्स एस एंड एएमपी आई कॉर्पोरेशन (प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी), मैसर्स सेवॉन कंपनी लिमिटेड (प्रोक्योर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी) और कोरिया गणराज्य से मैसर्स सीटेक कंपनी लिमिटेड (यूटिलिटी सप्लायर कंपनी) से सेवाएं प्राप्त की हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

च.3 परिकलन पद्धति

36. सब्सिडी एवं प्रतिकार योग्य उपाय करार (जिन्हें आगे "एससीएम" कहा गया है) के अनुच्छेद 14 में एससीएम के अनुच्छेद 1 के पैरा 1 के अनुसरण में प्राप्तकर्ता को प्रदत्त लाभ के परिकलन के लिए दिशा-निर्देशों तथा सिद्धांत का प्रावधान है और उसमें यह भी प्रावधान है कि प्राप्तकर्ता को लाभ का परिकलन करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई भी पद्धति पारदर्शी और पर्याप्त रूप से स्पष्ट की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्राप्तकर्ता को लाभ का परिकलन करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई भी पद्धति उनके राष्ट्रीय कानून अथवा संबंधित सदस्य के कार्यान्वयन विनियमों में दी जाएगी और प्रत्येक प्रकरण विशेष में उसका अनुप्रयोग पारदर्शी तथा पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार, नियमावली में सब्सिडीकरण की मात्रा के निर्धारण के लिए सिद्धांत निर्धारित हैं। इस जांच में निर्धारण इन दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

याचिका में आरोपित सब्सिडी कार्यक्रम

याचिका में निम्नलिखित छः सब्सिडी कार्यक्रम विशेष रूप से आरोपित किए गए हैं और जांच की शुरुआत की सूचना में उल्लिखित हैं:

कार्यक्रम संख्या 1 : कारपोरेट पुनर्गठन/ऋण पुनर्गठन

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

37. याचिकाकर्ताओं ने कारपोरेट पुनर्गठन/ऋण पुनर्गठन के तहत इस सब्सिडी कार्यक्रम का आरोप लगाया है। कारपोरेट पुनर्गठन संवर्धन अधिनियम (सीआरपीए), 2014 के अनुच्छेद 4 और 2016 के अनुच्छेद 2(6) के अनुसार "उद्यम शब्द की परिभाषा" में उद्यम का अभिप्राय उससे है जिसने ऋणदाता वित्तीय संस्था ऋण प्राप्त किया हो और ऋण की कुल राशि 50 बिलियन डॉन (जिसे इसके बाद इस उप पैरा में "संदर्भ राशि" कहा गया है) से अधिक पहुँच जाए। ऐसे मामलों में, यदि दिवालियापन का संकेत देने वाले किसी उद्यम ने दावों के पुनर्समायोजन, ऋण के पुनर्भुगतान आदि के माध्यम से संदर्भ राशि से कम ऋण की कुल राशि कम की है, तो वह उद्यम भी माना गया उद्यम होगा। सीपीआरए 2016 के अनुच्छेद 2(7) के तहत "दिवालियापन के संकेत वाला उद्यम" शब्द का अभिप्राय ऐसे उद्यम से है जिसके बारे में प्रमुख ऋणदाता बैंक साधारण उधार के अलावा बाहर से अतिरिक्त नकद अंतर्वाह के बिना वित्तीय ऋणदाता से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान (जिसे यहां आगे "दिवालियापन के संकेत के रूप में उल्लिखित किया गया है") जैसे व्यापार की सामान्य अवधि में अपने दायित्वों का निष्पादन करने में कठिनाईयों वाले ऋण जोखिम मूल्यांकन के आधार पर पता लगाता है। इस योजना के अनुसार 4 प्रकार के ऋण पुनर्गठन हैं—

क. ऋणदाता – कंपनी स्वैच्छिक करार

ख. बर्कआउट (ऋणदाता के नेतृत्व में पुनर्गठन)

ग. न्यायालय द्वारा दिवालिया संबंधी कार्रवाईयां

घ. कारपोरेट पुनरुज्जीवन संबंधी विशेष अधिनियम

कंपनियां वित्तीय जोखिम और गंभीरता के किस्म जिस श्रेणी में वह हैं, के अनुसार पात्र हैं।

38. कारपोरेट पुनर्गठन दिवालियापन के संकेत दर्शाने वाले उद्यम के लिए कारपोरेट पुनर्गठन संवर्धन अधिनियम (सीआरपीए) के अनुसार किया जाता है। कोरिया सरकार द्वारा नियंत्रित बैंकों अर्थात् कोरिया डेवलपमेंट बैंक, कोरिया फाइनेंशियल कारपोरेशन (कोओएफसी), केईएक्सआईएम, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया (आईबीके) ने कारपोरेट पुनर्गठन में ऋणदाता के रूप में भाग लिया। कुम्हो एक ऋण पुनर्गठन अर्थात् ऋणदाता – कंपनी स्वैच्छिक करार 2010-2012 (सीवीए) के तहत तीन वर्षों की अवधि के लिए इस कार्यक्रम के तहत लाभ के लिए पात्र थी। एलजी ग्रुप भी इस कार्यक्रम के तहत लाभ के लिए पात्र है।

39. ऋण के बाद में भुगतान, 2010 से 2015 तक स्थिर व्याज दर, परिवर्तनीय बांडों की खरीद आदि के रूप में कारपोरेट पुनर्गठन कार्यक्रम के तहत उद्यम को अनावर्ती लाभ प्रदान किया गया था।

कोरिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

40. कुम्हो और एलजी केम. सहित जांचाधीन कंपनियों ने सीआरपीए के तहत अभ्यास संबंधी कार्यवाहियां नहीं कीं। इसके बजाए, कुम्हो ने उनके ऋणदाताओं के द्वारा और उनके बीच किए गए निजी करार के अनुसरण में अभ्यास कार्रवाईयां कीं। अभ्यास कार्रवाई का आशय कंपनी को स्थिर करके अधिक से अधिक ऋण वसूली के लिए ऋणदाताओं को अनुमति देना है। यह कंपनी द्वारा और उसके ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से किया जाता है। ऋणदाताओं द्वारा की गई अभ्यास कार्रवाईयां किसी सरकारी एजेंसी अथवा प्राधिकारी द्वारा शासित नहीं की जाती हैं। ऋणदाता उन ऋणदाता बैंकों की एक समिति बनाएंगे जो पुनर्गठन की कार्रवाईयां संचालित करेगी। अभ्यास कार्रवाईयां के अनुसरण में, पुनर्गठन कार्रवाईयां किसी सरकारी एजेंसी अथवा प्राधिकारी द्वारा संचालित नहीं की जाती हैं। ये कार्रवाईयां कंपनी के ऋणदाताओं द्वारा की जाती हैं।
41. सीवीए, सीआरपीए अथवा कोरिया में किसी अन्य कानून द्वारा शासित नहीं होता है, अतः पुनर्गठन प्रक्रिया में सरकार का कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना नहीं होता। ऋणदाताओं द्वारा सहायता प्रदान करने का निर्णय एक वाणिज्यिक निर्णय था और ऋणदाताओं के अपने हित में हित को सुरक्षित करने की कार्रवाई थी। इस पूरी पुनर्गठन प्रक्रिया में कोरिया सरकार द्वारा कोई निर्णय अथवा उसकी कोई भूमिका नहीं थी।
42. मैसर्स कुम्हो ने अपने उत्तर में कोरिया सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह शामिल न होना दर्शाने के लिए प्रश्नावली के उत्तर में सीवीए और सीआरपीए के तहत पुनर्गठन कार्यक्रम के बीच सभी अंतर स्पष्ट रूप से दिए हैं। निर्यातक ने यह भी स्पष्ट किया कि दिवालियापन हल कर दिया गया है और वित्तीय ऋणदाताओं की सातवीं काउंसिल में सीवीए को 28.12.2012 को अर्थात् जांच की अवधि से पूर्व रद्द कर दिया गया था। इसके रद्द होने पर, ऋणदाता बैंकों ने 2015 के अंत तक तीन वर्षों की अवधि में ऋण के पुनर्भुगतान का वितरण करने की अनुमति दी। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कोई प्राप्ति अथवा वित्तीय अंशदान का प्रोद्भवन नहीं है। सीवीए के तहत पुनर्गठन प्रक्रिया ऋणदाता के संकल्प द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित की जाती है जिसमें सभी ऋणदाताओं के शामिल होने और 100 प्रतिशत सहमति की अपेक्षा होती है। अतः किसी लागू कानून अथवा विनियम के तहत सरकार से कोई लाभ प्राप्त करने की कोई प्रश्न नहीं है।
43. यह अनुरोध किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत एलजी केम. ने किसी प्रकार का कोई कारपोरेट पुनर्गठन/ऋण पुनर्गठन नहीं किया। स्थापना से ही एलजी केम. बिना किसी संकट के अपना व्यापार चला रहा है। एलजी केम. अपनी वित्तीय स्थिरता में उत्कृष्ट है और कुछ बकाया कारपोरेट बांडों को छोड़कर कोई विद्यमान बैंक ऋण नहीं है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई कारपोरेट पुनर्गठन नहीं था जिसे कंपनी के लिए समग्र रूप से किया गया हो और इसे एलजी केम. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से सत्यापित किया जा सकता है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कारपोरेट पुनर्गठन के संबंध में किसी तथ्य का उल्लेख नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम कारपोरेट पुनर्गठन संवर्धन अधिनियम, 2007 के अनुच्छेद 6 और कारपोरेट पुनर्गठन संवर्धन अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 2(8) के तहत शासित था।
45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की जांच विगत में अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा पूर्व में की गई है जो इसकी मौजूदगी सिद्ध करता है। उदाहरण के लिए, इस कार्यक्रम की प्रतिकारयोग्यता यूएस – कुछ संक्षारणरोधी स्टील उत्पाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों द्वारा की गई है।
46. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और वह वित्तीय अंशदान प्राप्त करने वाले को एतद्वारा लाभ प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह उस उद्यम तक सीमित है जो कारपोरेट एवं ऋण पुनर्गठन करता है।

कुम्हो:

47. कुम्हो के प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना यह दर्शाती है कि कुम्हो ने इस कार्यक्रम के तहत कारपोरेट पुनर्गठन किया है।
48. इस कार्यक्रम के तहत, पुनर्गठन दिवालियापन का संकेत दर्शाने वाले उद्यम के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, संकल्पों पर वित्तीय ऋणदाता परिषद और पुनर्गठन प्रक्रिया कर रहे उद्यम द्वारा सहमति दी जाती है। इस कार्यक्रम के तहत

- पुनर्गठन प्रक्रिया ऋणदाता कंपनी स्वैच्छिक करार के माध्यम से थी और सीआरपीए द्वारा शासित नहीं थी। वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा पारित संकल्पों में विभिन्न प्रकार के उपायों का प्रावधान था, यथा (i) बकाया ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त अवधि, (ii) यूएसएएनसीई एल/सी की सीमा में वृद्धि, (iii) नए ऋण देना और (iv) परिवर्तनीय बांड की खरीद।
49. पुनर्गठन प्रक्रिया में लगे ऋणदाता बैंकों में तीन सरकारी स्वामित्व वाले बैंक अर्थात् कोरिया डेवलेपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया और इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया शामिल हैं।
50. एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया अधिनियम के अनुच्छेद 1 में यह प्रावधान है कि बैंक का प्रयोजन निर्यात और आयात, विदेश में निवेश और विदेशी संसाधनों के उपयोग या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के निगमीकरण के माध्यम से जैसे विदेशी आर्थिक सहयोग के लिए अपेक्षित वित्त प्रदान कर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास का संवर्धन करना है। अधिनियम के अनुच्छेद 18 में यह प्रावधान है कि बैंक (i) निर्यात के संवर्धन, (ii) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण आयात, (iii) लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा निर्यात एवं आयात, (iv) विदेशी निवेश का संवर्धन, (v) सरकार द्वारा आवश्यक माने गए दायित्व, (vi) विशिष्ट क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए ऋण देंगे। इस अधिनियम में इन कार्यों को करते समय कार्यनीति एवं वित्त मंत्रालय का अनुमोदन भी अपेक्षित है। प्रचालन योजना, बैंक की व्यापार नियम पुस्तक भी कार्यनीति एवं वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जानी होती है। अधिनियम के अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान है कि कार्यनीति एवं वित्त मंत्रालय बैंक के प्रचालन का पर्यवेक्षण करेगा।
51. कोरिया डेवलेपमेंट बैंक अधिनियम के अनुच्छेद 1 में यह प्रावधान है कि बैंक का प्रयोजन ऐसे कोरिया डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना कर वित्तीय उद्योग एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उत्तम विकास में योगदान करना है जो उद्योगों के विकास और पोषण, अवसंरचना के विस्तार, क्षेत्रीय विकास, वित्तीय बाजार के स्थिरीकरण, संधारणीय वृद्धि की सुविधा देने के लिए आवश्यक निधियां दें और उनका प्रबंधन करे। अधिनियम के अनुच्छेद 18 में यह प्रावधान है कि केडीबी उद्योगों, अवसंरचना, ऊर्जा, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा किसी अन्य क्षेत्र, जिसे सरकार आवश्यक साझे के विकास के लिए निधियां प्रदान करेगा। अधिनियम के अनुच्छेद 22 में यह प्रावधान है कि वित्तीय सेवाएं आयोग व्यापार योजना के लिए अनुमोदन प्रदान करता है जहां लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र के लिए निधियों के प्रावधान को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्तीय सेवाएं आयोग बैंक के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा। वित्तीय सेवाएं आयोग कोरिया सरकार की एक एजेंसी है जिसमें वित्तीय नीति तथा विनियामक पर्यवेक्षण पर सांविधिक प्राधिकार निहित है।
52. इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया अधिनियम के अनुच्छेद 1 में भी लघु एवं मध्यम उद्यम स्वामियों का आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए उनके स्वतंत्र आर्थिक क्रियाकलापों के संवर्धन का प्रावधान है जो लघु एवं मध्यम उद्यम स्वामित्वों के लिए एक दक्ष ऋण प्रणाली की स्थापना में योगदान करता है। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया भी अधिनियम के अनुच्छेद 46 के अनुसार वित्तीय सेवाएं आयोग के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। अधिनियम के अनुच्छेद 33 में यह प्रावधान है कि वह एसएमई को ऋण प्रदान करेगा और सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करेगा।
53. प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि सरकारी स्वामित्व वाले बैंक सरकारी निकाय हैं क्योंकि उन पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकारी कार्यों को करने के लिए सरकारी प्राधिकार में निहित होते हैं। (i) बकाया ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अनुग्रह अवधि, (ii) यूएसएएनसीई एल/सी की सीमा में वृद्धि, (iii) नया ऋण देने और (iv) इन सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा परिवर्तनीय बांड की खरीद संबंधी उपाय सरकारी बैंकों के कार्य हैं।
54. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी बैंक सामान्य सीवीए के तहत कार्य कर रहे हैं और (i) बकाया ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अनुग्रह अवधि प्रदान करने, (ii) यूएसएएनसीई एल/सी की सीमा में वृद्धि, (iii) नया ऋण देने और (iv) परिवर्तनीय बांड की खरीद के संदर्भ में निजी स्वामित्व वाले बैंकों के कार्य सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के कार्यों से भिन्न नहीं हैं। ऋणों, यूएसएएनसीई तथा परिवर्तनीय बांडों की खरीद का विश्लेषण यह दर्शाता है कि सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों और सरकारी स्वामित्व में न होने वाले अन्य ऋणदाता बैंकों द्वारा अपनाई गई परिपाटी के बीच कोई अनिवार्य अंतर नहीं है। इस बात का समर्थन करने के लिए कोई सूचना अथवा साक्ष्य नहीं है कि ऋणों, यूएसएएनसीई की सीमा में वृद्धि और सरकारी स्वामित्व में न होने वाले ऋणदाता बैंकों द्वारा परिवर्तनीय बांडों की खरीद के संबंध में निर्णय बाजार सिद्धांतों के आधार पर थे। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि पुनर्गठन प्रक्रिया में शामिल सभी निजी स्वामित्व वाले बैंकों को (i) बकाया ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अनुग्रह अवधि, (ii) यूएसएएनसीई एल/सी की सीमा में वृद्धि, (iii) नए ऋण देने और परिवर्तनीय बांडों की खरीद के संबंध में उपाय अपनाने का कार्य सौंपा गया था अथवा निर्देश दिया गया था।

55. कुम्हो के लिए सीवीए के तहत पुनर्गठन 2010-2012 के बीच अर्थात् 10 वर्ष की एयूएल अवधि के अंतर्गत हुआ। सीवीए के तहत अधिकतर ऋणों का पुनर्भुगतान किया गया था और 2015 तक समाप्त कर दिए गए थे तथा सीवीए के अनुग्रह पर कुछ ऋण बढ़ाए गए थे और 2017 तक उनका पुनर्भुगतान कर दिया गया था।
56. नए तक बढ़ाए गए ऋणों और सीवीए के तहत यूएसएनसीई ऋण सुविधा के माध्यम से ऋणों के मामले में लाभ की राशि इन बैंकों द्वारा लगाए गए व्याज और तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर लगाई गई व्याज दर के बीच का अंतर परिकलित करके निर्धारित की जाती है। इस प्रयोजन के लिए उस समय समतुल्य ऋण दर से कंपनियों के कारपोरेट बांड पर लगाई गई निर्धारित व्याज दर मानी जाती है। सीवीए के तहत इन सभी ऋणों पर प्रदत्त व्याज की राशि और निर्धारित व्याज दर के अनुसार देय कुल व्याज राशि के बीच का अंतर एकबारगी अनावर्ती लाभ के रूप में माना गया था। जांच की अवधि के दौरान प्रोद्भूत लाभ के रूप में माना गया था। जांच की अवधि के लिए प्रोद्भूत लाभ निर्धारित करने के लिए लाभ की राशि एयूएल अवधि में आबंटित की गई थी।
57. परिवर्तनीय बांड के मामले में, कुम्हो के परिवर्तनीय बांड बैंकों द्वारा सीवीए पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत खरीदे गए थे। बैंकों को देय व्याज निर्धारित व्याज दर के अनुसार था। परिवर्तनीय बांड शेयरों में परिवर्तन किए गए थे और 2015 में अर्थात् जांच की अवधि से पूर्व बाजार कीमत पर बेचे गए थे।
58. परिवर्तनीय बांड के मामले में लाभ निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने कारपोरेट बांडों की बिक्री के समय कुम्हो की ऋण दर पर विचार किया। प्राधिकारी ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि बैंकों द्वारा कुम्हो के बांड की खरीद कारपोरेट पुनर्गठन प्रक्रिया का भाग थी। इसके अतिरिक्त, ऋणों और यूएसएनसीई ऋण सुविधा के असमान, बैंकों द्वारा कुम्हो के परिवर्तनीय बांडों की खरीद को बैंकों के सामान्य वाणिज्यिक कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता।
59. परिवर्तनीय बांडों का शेयर में परिवर्तन और बाद में पुनर्गठन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद बैंकों द्वारा शेयरों की पुनः बिक्री भी कुम्हो द्वारा प्राप्त लाभ की राशि निर्धारित करने के लिए संगत नहीं है। प्राधिकारी निर्धारित हैं कि कुम्हो के ये परिवर्तनीय बांड अन्य निजी बैंकों/कंपनियों द्वारा बाजार सिद्धांतों के आधार पर और पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान उनके सामान्य वाणिज्यिक प्रचालनों के भाग के रूप में नहीं खरीदे गए होते इस प्रकार, बैंकों द्वारा परिवर्तनीय बांड की खरीद के मामले में कुल लाभ इन परिवर्तनीय बांडों की खरीद के लिए बैंकों द्वारा कुम्हो को दी गई कीमत के बराबर है। यह कुल लाभ राशि जांच की अवधि के लिए हुए लाभ के निर्धारण के लिए एयूएल अवधि में आबंटित की गई थी।
60. कुम्हो द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में नए ऋणों, बढ़ाए गए ऋणों, यूएसएनसीई के माध्यम से ऋणों की राशि और इस कार्यक्रम के तहत परिवर्तनीय बांड जारी किए जाने के संबंध में सूचना दी गई है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
61. प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि पुनर्गठन प्रक्रिया में बैंकों द्वारा ऋणों का प्रावधान, यूएसएनसीई की सीमा में वृद्धि निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान बनता है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी विशिष्ट भी है क्योंकि यह पुनर्गठन प्रक्रिया करने वाले उद्यम तक ही सीमित है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

एलजी केम. लिमिटेड

62. तथापि, एलजी केम. ने इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने भी यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि इस कार्यक्रम के तहत एलजी केम. लि. द्वारा लाभ प्राप्त किया गया था जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को ई-एसबीआर का निर्यात किया।
63. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 2 - शुल्क वापसी कार्यक्रम संख्या 2 : शुल्क वापसी – निर्यातों के लिए कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क की वापसी/गैर-वास्तविक रूप से शामिल की गई मदों पर शुल्क वापसी तथा अतिरिक्त हानि दर

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

64. निर्यातक कंपनियां आयातित कच्ची सामग्री पर दिए गए सीमा शुल्क की उस समय वापसी प्राप्त करते हैं जब निर्यात आयात घोषणा के दो वर्षों के भीतर किया जाए। यह कार्यक्रम सीमा शुल्कों की वापसी से संबंधित विशेष मामलों पर अधिनियम के

अनुसार शासित होता है। शुल्क वापसी (i) सरलीकृत निर्धारित राशि की वापसी की पद्धति के अनुसार अथवा (ii) व्यक्तिगत वापसी पद्धति के अनुसार दी जाती है। इस कार्यक्रम के तहत शुल्क वापसी की राशि उस सीमा तक विद्यमान होती है जो आयातित उन इनपुट पर आयात प्रभागों की राशि से अधिक होती है, जिनकी खपत अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देने के बाद निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में की गई हो।

कोरिया सरकार/अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

65. शुल्क वापसी कार्यक्रम निर्यातित सामानों के उत्पादन में खपत में लाए जाने वाले इनपुट पर वास्तविक रूप से लगाए गए शुल्कों से अधिक सीमा शुल्कों की वापसी अथवा प्रेषण की अनुमति नहीं देता। शासी अधिनियम में सीमा शुल्क की वापसी राशि निर्धारित करने के लिए दो पद्धतियों का प्रावधान है: (i) व्यक्तिगत वापसी पद्धति और (ii) सरलीकृत निर्धारित राशि की वापसी की पद्धति। शुल्क वापसी कार्यक्रम की व्यक्तिगत वापसी पद्धति ही एक ऐसी पद्धति है जो जांचाधीन कंपनियों पर लागू है। इस विवादित योजना के तहत कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाता है क्योंकि वापसी की राशि का परिकलन निर्यातित उत्पाद में कच्ची सामग्री के वास्तविक प्रयोग के अनुसार किया जाता है। "अतिरिक्त" वापसी के अभाव में निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त आयातित सामग्री पर प्रोद्भूत कर की वापसी पर सीमा प्रशुल्क अधिनियम और एससीएम करार के अनुसार "सब्सिडी" के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।
66. कोरिया गणराज्य से संबद्ध सामानों के आयातों पर पहले ही पाटनरोधी शुल्क है। शुल्क वापसी कार्यक्रम निर्यात आकस्मिक है और इससे निर्यात सब्सिडीकरण होता है। जीएटीटी के अनुच्छेद VI(5) और सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ख(1)(क) में यह प्रावधान है कि कोई उत्पाद पाटन अथवा निर्यात सब्सिडीकरण की समान स्थिति के लिए प्रतिपूर्ति करने हेतु पाटनरोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क, दोनों के अध्यधीन नहीं होगा।
67. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में खपत में लाए गए आयातित उत्पादों, यथा - "नैर-वास्तविक रूप से शामिल की गई मर्दे और प्राप्त अतिरिक्त हानि दर" पर लगाए गए शुल्कों से अधिक सीमा शुल्क की कोई वापसी नहीं थी।

प्राधिकारी द्वारा जांच

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क की वापसी से संबंधित विशेष मामलों संबंधी अधिनियम – अधिनियम के अनुच्छेद 12 10817, 14 जुलाई 2011 (आधारभूत कच्ची सामग्री आदि पर कर भुगतान का प्रमाण-पत्र) और सीमा शुल्क की वापसी से संबंधित विशेष मामलों पर प्रेसिडेंसियल डिक्री के अनुच्छेद 9 <दिनांक 15 दिसंबर, 2015 के अधिनियम संख्या 13559 द्वारा संशोधित> के तहत शासित था।
69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तथाकथित सब्सिडी कार्यक्रम में निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर दिए गए आयात शुल्क की वापसी का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के तहत शुल्क वापसी की दो पद्धतियां हैं - (i) व्यक्तिगत वापसी पद्धति और (ii) सरलीकृत निर्धारित राशि की वापसी की पद्धति। प्रतिभागी उत्पादक/ निर्यातक सरलीकृत निर्धारित राशि की वापसी की पद्धति के लिए पात्र नहीं है और इसीलिए व्यक्तिगत वापसी पद्धति के अनुसार शुल्क वापसी प्राप्त की है।
70. व्यक्तिगत वापसी पद्धति के तहत निर्यात के लिए कच्ची सामग्री पर लगाए गए सीमा शुल्क की वापसी से संबंधित विशेष मामले अधिनियम ("अधिनियम") में यह प्रावधान है कि आयातित कच्ची सामग्री का प्रयोग निर्यातित उत्पाद में किया ही जाना चाहिए (अनुच्छेद 3)। आयातित कच्ची सामग्री का प्रयोग करने वाले उत्पाद का निर्यात दो वर्ष की अवधि के भीतर होना चाहिए (अनुच्छेद 9)। उत्पादक/निर्यातक के लिए यह अपेक्षित है कि वे निर्यात के लिए घोषणा दायर करने की तारीख से दो वर्ष के भीतर वापसी के लिए आवेदन करें।
71. प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया है कि अधिनियम में यह अपेक्षा है कि "आयातित कच्ची सामग्री को संगत निर्यात सामानों के साथ रासायनिक रूप से अथवा भौतिक रूप से संयुक्त होना चाहिए।" उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रयोग रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है और कच्ची सामग्री से मिलान खाने वाली तालिका भी यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत की है कि शुल्क वापसी लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों को अपनी कच्ची सामग्री संबद्ध करनी है और "प्रयोग रिपोर्ट" का प्रयोग करते हुए निर्यात करना है।
72. प्रतिभागी/सहयोगी दोनों उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन यह दर्शाता है कि आयात शुल्क का कोई अतिरिक्त प्रेषण नहीं है और शुल्क वापसी की राशि निर्यातित सामानों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर दिए गए शुल्क की राशि से अधिक नहीं होगी।

73. प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क के प्रेषण के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए और इसीलिए इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

कार्यक्रम संख्या 3 : एसबीआर उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सरकारी अनुदान अथवा विनिर्माताओं की तदर्थ सब्सिडियां

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

74. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत एसबीआर उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट अथवा विनिर्माताओं की तदर्थ सब्सिडियों के अनुसार विभिन्न सरकारी अनुदान हैं। कुछ परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान तथा अन्य कर छूटें अथवा कटौतियां प्रदान कर उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सामान्य कार्यगत नीतियां हैं। कोरिया सरकार द्वारा अपने उद्यमों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। अनुदान परिसंपत्तियों अथवा आय से संबंधित हो सकते हैं जो एलजी कंपनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सब्सिडीयुक्त कीमत पर प्रदान किए जाते हैं। याचिकाकर्ता समझते हैं कि कुम्हो पैट्रोकेमिकल कं. लि. और एलजी ग्रुप उपर्युक्त लाभ के लिए पात्र हैं।

कोरिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

75. याचिकाकर्ता इस कार्यक्रम के संबंध में कोई सार्थक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं और इसलिए संगत कार्यक्रम की पहचान करना संभव नहीं है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी नवाचार संवर्धन अधिनियम के अनुच्छेद 11 के तहत निर्धारित अनुदान कार्यक्रमों को छोड़कर कोई अनुदान कार्यक्रम नहीं है।
76. इस कार्यक्रम के तहत एलजी केम. ने जांच की अवधि के दौरान अनुसंधान एवं विकास संबंधी सरकारी अनुदानों की छोटी सी राशि प्राप्त की। तथापि, प्राप्त अनुदान न तो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से संबंधित हैं और न ही बिक्री से संबंधित। इसके अतिरिक्त, एलजी केम. के समेकित नकद प्रवाह विवरण में सूचित अन्य अनुदान उसकी नानजिंग, चीन में स्थित सहायक कंपनी (एलजी केम. नानजिंग, एलजी सीएनजे) से संबंधित है। यह अनुरोध किया गया है कि अनुदान चीनी सरकार से प्राप्त किया जाता है न कि कोरिया सरकार से और सहायक कंपनी किसी भी रूप में अथवा तरीके से विचाराधीन उत्पाद की बिक्री तथा उत्पादन में शामिल नहीं है। अतः इस कार्यक्रम के तहत विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन/बिक्री के संबंध में उत्तरदाता द्वारा कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सरकार से सहायता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं औद्योगिक प्रौद्योगिकी नवाचार संवर्धन अधिनियम के अनुच्छेद 11 में निर्धारित हैं। इस अधिनियम के आधार पर सरकार योजना बनाती है और उद्योगों को निर्धारित करती है तथा अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों को वार्षिक रूप से सहायता देती है और सार्वजनिक घोषणा जारी करती है।
78. कोई भी कंपनी अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती है और एक बार जब कंपनी की आरएंडडी परियोजना सरकारी समीक्षा तथा अनुमोदन के तहत चयनित हो जाती है तो वह सरकार के साथ सहमत परियोजना योजना के आधार पर आरएंडडी परियोजना चलाई जाएगी।
79. अनुमोदित आरएंडडी परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। कंपनियां और सरकार उस आरएंडडी परियोजना के लिए बैंक खाते का प्रबंधन करती हैं जो उस परियोजना के लिए निर्धारित है। व्यापार योजना परियोजना के लिए सरकार और कारपोरेट के अंशदान की राशि निर्धारित करती है। कंपनियां और सरकार निर्धारित राशि को बैंक खाते में अंतरित करती हैं। जब कंपनी आरएंडडी अवधि के दौरान आरएंडडी परियोजनाओं के लिए खर्च की कुछ राशि खर्च करती है तो सरकारी अनुदान कंपनी के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है।
80. इस कार्यक्रम में निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे इस वित्तीय अंशदान के प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह चुनिंदा उद्यमों और क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध है।

81. कुम्हो द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है। प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि कुम्हो पर इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
82. तथापि, एलजी केम. लिमिटेड ने इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने भी यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि एलजी केम. लिमिटेड द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया गया था। जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को ई-एसवीआर का निर्यात किया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि एलजी केम. पर इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 4 : नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना गठन नीति

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

83. याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना गठन नीति के तहत निधि के रूप में कोरिया सरकार अपने कोरिया ऊर्जा एजेंसी के नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र के माध्यम से संस्थापन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के उत्पादन के लिए निधियों के रूप में प्रोत्साहन देती है। प्रचालन निधि मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा सुविधा का व्यापार प्रचालन संवर्धित करने के लिए छोटे आकार की कंपनियों को दी जाती है। विशेष कराधान के प्रतिबंध अधिनियम के अनुच्छेद 25-2 और अनुच्छेद 118 के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के लिए कर कटौती का प्रावधान है।
84. याचिकाकर्ता समझते हैं कि जो उद्यम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगे हुए हैं, यथा – पवन विद्युत उत्पादन सुविधा, सौर ताप ऊर्जा, जियोथर्मल सुविधा, बायो सुविधा, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल उत्पादन लाइन, पवन विद्युत टरबाइन उत्पादन लाइन में लगे हैं, वे उपर्युक्त लाभ के लिए पात्र हैं।

कोरिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

85. कोरिया सरकार ऊर्जा प्रयोग को युक्तिसंगत बनाने के लिए और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए ऊर्जा बचत सुविधाओं में निवेश के लिए दीर्घावधि ऋण प्रदान करती है। यह कार्यक्रम 1997 में स्थापित किया गया था और कोरिया ऊर्जा एजेंसी ऊर्जा प्रयोग युक्तिसंगतीकरण परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम का संचालन करती है।
86. इस कार्यक्रम के तहत, एलजी केम. ने जांच की अवधि (एयूएल अवधि सहित) के दौरान कोरिया सरकार से या कोरिया एनर्जी एजेंसी के नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र के माध्यम से निधि के रूप में कोई सब्सिडी (अथवा अनुदान) प्राप्त नहीं किया और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना गठन नीति के संबंध में जांच की अवधि के दौरान विशेष कराधान के प्रतिबंध अधिनियम के अनुच्छेद 25-2 और अनुच्छेद 118 के तहत कोई कर कटौती प्राप्त नहीं की गई थी। कर कटौती की केवल एक छोटी सी राशि (6.5 मिलियन केआरडब्ल्यू/कुल कंपनी राजस्व का 0.000028 प्रतिशत) अनुच्छेद 25-2 के तहत किया गया था, परंतु कर कटौती ऊर्जा प्रयोग युक्तिसंगतीकरण से संबंधित है न कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना गठन नीति से संबंधित।
87. कोरिया सरकार ने पुष्टि की कि एलजी केम. ने अनुच्छेद 25-2 के तहत कर कटौती की केवल एक छोटी सी राशि प्राप्त की, परंतु ऊर्जा प्रयोग युक्तिसंगतीकरण कार्यक्रम के तहत कर कटौती नहीं। इस कार्यक्रम के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना गठन नीति निम्नलिखित चार प्रकार की सहायता में थी:
 - i. ऊर्जा बचत सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता
 - ii. स्मार्ट ग्रिडों के प्रयोग के सृजन तथा सुविधा के संबंध में निवेश किए गए खर्चों के लिए सब्सिडीकरण आदि।
 - iii. ऊर्जा बचत सुविधाओं में निवेश के लिए कर ऋण।
 - iv. विशेष कराधान प्रतिबंध अधिनियम अनुच्छेद 118 – सीमा शुल्कों की कटौती।
88. कोरिया सरकार ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा प्रयोग युक्तिसंगतीकरण परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिशा-निर्देश कुछ क्षेत्रों, उद्यमों, उद्योगों अथवा उद्यम समूहों अथवा उद्योगों के लिए इस कार्यक्रम की पात्रता को सीमित नहीं करते। ऊर्जा बचत सुविधाओं में निवेश करने वाले किसी भी उद्यम को इस कार्यक्रम के तहत दीर्घावधि ऋणों के लिए आवेदन करने की अनुमति है। अतः इस कार्यक्रम में उस विशेषता का अभाव है जो किसी सब्सिडी कार्यक्रम पर विचार किए जाने के लिए अपेक्षित है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

89. इस कार्यक्रम में उन उद्यमों को दीर्घावधि ऋण तथा अनुदानों का प्रावधान है जो ऊर्जा प्रयोग को युक्तिसंगत बनाने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के प्रयास संवर्धित करने के लिए ऊर्जा बचत सुविधाएं संस्थापित करते हैं। यह कार्यक्रम केवल उन उद्यमों को दिया जाता है जो ऊर्जा प्रयोग युक्तिसंगतीकरण अधिनियम के अनुच्छेद 14 और ऊर्जा प्रयोग युक्तिसंगतीकरण के प्रवर्तन डिक्री अधिनियम के अनुच्छेद 27 में परिभाषित किए गए अनुसार ऊर्जा बचत सुविधाएं संस्थापित करते हैं।
90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में अधिमानीय ऋण एवं अनुदान (निधियों का सीधे अंतरण) के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। ऋण के मामले में लाभ की राशि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अनुसरण में दिए गए ऋणों पर किए जाने वाले व्याज भुगतान की राशि और किसी अन्य तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर किए जाने वाले व्याज भुगतान की राशि के बीच के अंतर के बराबर है। अनुदान के मामले में लाभ की राशि जांच की अवधि में होने वाले अनुदान की राशि के बराबर है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह ऊर्जा बचत सुविधाओं में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए सीमित है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
91. कुम्हो द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा लाभ प्राप्त किया गया है। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
92. एलजी केम. लिमिटेड द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि उसने इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है, परंतु ऊर्जा प्रयोग युक्तिसंगतीकरण कार्यक्रम के तहत शामिल है। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 5 : अनुसंधान एवं विकास परियोजना सहायता नीति/विशेष अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों के अंतर्गत कंपनियों के लिए कारपोरेट कर छूट/कटौती

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

93. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजना सहायता नीति/विशेष अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों के अंतर्गत कंपनियों के लिए कारपोरेट कर छूट/कटौती है। उपर्युक्त कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र व्यय के लिए देय करों की कटौती के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों में कोरियाई कारपोरेट निवेश को सुकर बनाना है। (अनुच्छेद 10 से 12, 1ख) के अनुसार, विशेष स्थानीय कराधान प्रतिबंध अधिनियम (अनुच्छेद 26) और आय कर की प्रवर्तन डिक्री अधिनियम (अनुच्छेद 12) में अनुसंधान एवं विकास निवेश के लिए विभिन्न कर ऋणों का प्रावधान है, यथा:
- (1) कारपोरेट अनुसंधान केंद्रों के लिए प्रयुक्त रियल एस्टेट हेतु स्थानीय कर में कटौती।
 - (2) प्रौद्योगिकी के अंतरण, अधिग्रहण और लाइसेंसिंग के लिए कर ऋण।
 - (3) विदेशी इंजीनियरों के लिए आय कर कटौती।
 - (4) अनुसंधान एवं विकास से संबंधित योगदानों पर विशेष कराधान।
 - (5) विशेष अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों के अंतर्गत कंपनियों के लिए कारपोरेट कर छूट/कटौती।
 - (6) प्रशुल्क कटौती।
94. जो कोरियाई कंपनी अपनी अनुसंधान एवं विकास परियोजना निष्पादित करती है, वे उपर्युक्त लाभों के लिए पात्र है। यह अनुरोध किया गया है कि जो उद्यम स्वायत्त वाहनों, इलैक्ट्रिक वाहनों, कृत्रिम आसूचना, इंटरनेट, क्लाउड, बड़े आंकड़ों, पहनने योग्य स्मार्ट यंत्रों, आईटी कंवेजर्स, उन्नत सॉफ्टवेयर, सुरक्षा, अनुभवी वस्तुओं, उन्नत सेमीकंडक्टरों/सेंसरों, ओएलईडी, 3डी प्रिंटिंग, 5जी संचार, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन (यूएचडी), बायो/स्वास्थ्य में लगे हुए हैं, वे उपर्युक्त लाभ के लिए पात्र हैं।

कोरिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

95. कोरियाई कराधान प्रणाली व्यापक रूप से दो प्रकार के करों में वर्गीकृत है, (i) राष्ट्रीय और (ii) स्थानीय कर। राष्ट्रीय कर में (i) उद्यम के लिए कारपोरेट कर, (ii) व्यक्तियों के लिए आय कर और (iii) मूल्यवर्धित कर हैं। स्थानीय कर में स्थानीय सरकार द्वारा लगाए गए कर शामिल हैं।

विशेष कराधान प्रतिबंध अधिनियम के तहत छः प्रकार के कर ऋण हैं:

1. अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास उद्यमों के लिए कर ऋण (अनुच्छेद 10)।
 2. अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास उद्यमों के लिए सुविधाओं में निवेश हेतु कर ऋण (अनुच्छेद 11)।
 3. ऊर्जा बचत सुविधाओं में निवेश के लिए कर ऋण (अनुच्छेद 25-2)।
 4. पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सुविधाओं में निवेश आदि के लिए कर ऋण (अनुच्छेद 25-3)।
 5. सुरक्षा सुविधाओं में निवेश आदि के लिए कर ऋण (अनुच्छेद 25)।
 6. उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सुविधाओं में निवेश आदि हेतु कर ऋण (अनुच्छेद 24)।
96. इस कार्यक्रम के तहत, एलजी केम. ने जांच की अवधि के दौरान विशेष कराधान प्रतिबंध अधिनियम (जिसे आगे यहां आरएसटीएम कहा गया है) के तहत अनुसंधान एवं विकास संबंधी कारपोरेट कर छूट/कटौती (जिसे यहां आगे कारपोरेट कर ऋण कहा गया है) का छोटा सा भाग प्राप्त किया। एलजी केम. ने अपनी कर विवरणी में कर ऋण राशि के व्यौरे के साथ जांच की अवधि के दौरान प्राप्त कारपोरेट कर ऋण की कुल राशि भी सूचित की। तथापि, कारपोरेट कर ऋण की कुल राशि (आरएंडडी संबंधी कारपोरेट कर ऋण सहित) कुल कंपनी राजस्व में तुलनात्मक रूप से कम है। इसके अतिरिक्त, अधिकतर कर छूट/कटौती न तो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से संबंधित है और न ही बिक्री से संबंधित है।
97. एलजी केम. ने अनावर्ती कार्यक्रम के संबंध में जांच की अवधि और एयूएल के दौरान विशेष स्थानीय कराधान प्रतिबंध अधिनियम (जिसे यहां आगे आरएसएलटीए कहा गया है) के अनुच्छेद 46 के तहत आरएंडडी संबंधी स्थानीय कर कटौती भी प्राप्त की। तथापि, आरएसटीए के तहत कारपोरेट कर ऋण की तरह स्थानीय कर कटौती की कुल राशि कुल कंपनी राजस्व में तुलनात्मक रूप से कम है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय कर कटौती का केवल एक छोटा सा भाग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित है।
98. कोरिया सरकार ने आरएसटीए के तहत कारपोरेट कर कटौती और आरएसएलटीए के तहत स्थानीय कर कटौती सहित आरएंडडी सहायता नीति कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न सूचनाएं दी हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत जब कोई उद्यम विशेष कराधान प्रतिबंध अधिनियम में परिभाषित किए गए अनुसार अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, ऊर्जा बचत, सुरक्षा और उत्पादकता व्यय करता है तो वह उद्यम निर्धारित दर पर कर ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। उद्यम उस कर योग्य वर्ष के लिए कारपोरेट कर से कर ऋण राशि की कटौती करने का पात्र होता है जिसमें वह खर्चा किया गया है।
100. इस कार्यक्रम में उस परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। लाभ प्रदत्त कारपोरेट कर और इन कर ऋणों के अभाव में देय कारपोरेट कर के बीच का अंतर है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि इसमें निर्धारित प्रयोजनों के लिए खर्च करने वाले विशेष उद्यमों को लाभ प्रदान किया जाता है।
101. कुम्हो और एलजी द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि इस सन्निधि कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है। प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि इस सन्निधि कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 6 : इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया द्वारा अधिमार्ग उधार देना

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

102. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के तहत, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया द्वारा अधिमार्ग उधार दिया जाता है। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया ने कम ब्याज दर पर ऋण दिए हैं जो सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति को ध्यान में न रखते हुए वाणिज्यिक बैंकों से थोड़ा सा कम हैं। प्रोत्साहन के लिए एसएमई (लघु एवं मध्यम उद्यम) उपर्युक्त लाभ के लिए पात्र हैं। ब्याज दर सीधी पद्धतियों के तहत 1.75 प्रतिशत से 3.7 प्रतिशत की रेंज पर है। कोरिया एक्जिम बैंक ने निर्यातों के लिए वित्तीय गारंटी सहायता प्रदान की है। कंपनी की चूक पर ईईएक्सआईएम मूलधन तथा ब्याज के साथ पूरी ऋण राशि का पुनर्भुगतान करता है। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया अथवा कोरिया एक्जिम बैंक ने ब्याज की कम दर से निर्यात एवं

आयात कारक, विदेशी निवेश ऋण कार्यक्रम और व्यापार बिल रियायत प्रदान की है। याचिकाकर्ता समझते हैं कि कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड और एलजी ग्रुप उपर्युक्त लाभ के लिए पात्र हैं।

कोरिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

103. ऋण और ऋण गारंटियां वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं। बैंक स्वतंत्र कंपनियों के रूप में प्रचालन कर रहे हैं। इन बैंकों को कोई सरकारी निर्देश नहीं हैं अथवा सरकार की उनमें संलिप्तता नहीं है। प्रतिभागी निर्यातकों के अनुरोध में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों से प्राप्त सभी ऋणों के पूर्ण व्यौरे प्रदान किए गए हैं। प्रतिभागी निर्यातकों ने सरकार से कम व्याज दर पर कोई ऋण प्राप्त नहीं किए हैं और इन ऋणों से उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है।
104. एलजी केम. ने अपनी याचिका में उल्लिखित बैंक, यथा - कोरिया डेवलेपमेंट बैंक (केडीबी), इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया (आईबीके) और द एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया (केईएक्सआईएम) से न तो ऋण लिया और न ही किन्हीं वित्तीय सेवाओं का उपयोग किया। कोरिया सरकार ने पुष्टि की कि एलजी केम. ने याचिका में उल्लिखित बैंक, यथा - कोरिया डेवलेपमेंट बैंक (केडीबी), इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया (आईबीके) और द एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया (केईएक्सआईएम) से न तो ऋण लिया और न ही किन्हीं वित्तीय सेवाओं का उपयोग किया।
105. कोरिया सरकार ने अनुरोध किया कि एलजी केम. ने याचिका में उल्लिखित बैंक, यथा - कोरिया डेवलेपमेंट बैंक (केडीबी), इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया (आईबीके) और द एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया (केईएक्सआईएम) से न तो ऋण लिया और न ही किन्हीं वित्तीय सेवाओं का उपयोग किया।

प्राधिकारी द्वारा जांच

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सरकारी स्वामित्व वाले बैंक इस कार्यक्रम के तहत उद्यमों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं, यथा - (i) प्रचालन ऋण, (ii) ऊर्जा प्रयोग युक्तिसंगतीकरण के लिए दीर्घावधि ऋण, (iii) अल्पावधि सीमा ऋण आदि।
107. कोरिया डेवलेपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया सरकारी स्वामित्व वाले बैंक हैं और उन्होंने कोरिया गणराज्य से प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों को ऋण प्रदान किए हैं।
108. प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि ये सरकारी स्वामित्व वाले बैंक सरकारी निकाय हैं। तदनुसार, सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा दिए गए ऋण सरकारी निकाय द्वारा निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान हैं। प्राप्तकर्ता को प्रदत्त ये लाभ इन बैंकों द्वारा लगाई गई व्याज की राशि और तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर लगाई गई व्याज की राशि के व्याज के अंतर के बीच के रूप में है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह या तो निर्यात पर आकस्मिक है अथवा उस उद्यम के लिए सीमित है जो ऋण के लिए अन्य निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है।

कुम्हो

109. कुम्हो द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है। प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि कुम्हो पर इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

एलजी केम.

110. एलजी केम. ने याचिका में उल्लिखित बैंक, यथा - कोरिया डेवलेपमेंट बैंक (केडीबी), इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया (आईबीके) और द एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया (केईएक्सआईएम) से न तो ऋण लिया और न ही किन्हीं वित्तीय सेवाओं का उपयोग किया। अतः जांच की अवधि के दौरान एलजी केम. को न तो कोई वित्तीय अंशदान और न ही कोई लाभ प्रदान किया गया था। प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि एलजी केम. पर इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 7 : अन्य सब्सिडी

सहयोगी उत्पादकों तथा निर्यातकों द्वारा प्राप्त अन्य कार्यक्रम

111. निम्नलिखित सब्सिडियों की पहचान "अन्य सब्सिडी कार्यक्रम" के रूप में की गई है क्योंकि इन सब्सिडियों का घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में विशेष रूप से दावा नहीं किया गया है और जांच की शुरुआत की सूचना में इनका उल्लेख नहीं किया

गया है, परंतु इन सब्सिडियों के संबंध में सूचना प्रतिभागी कंपनियों द्वारा अपने प्रश्नावली के उत्तर में दी गई है और साथ ही प्राधिकारी द्वारा की गई पूछताछ पर सहयोगी/प्रतिभागी उत्पादकों और निर्यातकों को दी गई है।

अन्य सब्सिडी: कुम्हो

112. याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त कार्यक्रम संख्या 1 ~ 6 को छोड़कर कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया है।

कार्यक्रम 7.1.1 – औद्योगिक परिसरों में रियल एस्टेट के लिए स्थानीय कर में कटौती

कोरिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

113. प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों ने औद्योगिक परिसरों में स्थित कारखानों के लिए अनुच्छेद 78(4) (औद्योगिक परिसरों के लिए कटौती आदि) के तहत औद्योगिक भवन के निर्माण अथवा विस्तार द्वारा अधिग्रहीत रियल एस्टेट पर अधिग्रहण कर के लिए कर कटौती प्राप्त की है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

114. जब कोई उद्यम रियल एस्टेट अधिग्रहीत करता है तो उसे अधिग्रहण कर देना होता है। अधिग्रहण कर उस कारपोरेट पर लगाया जाता है जिसने विशेष स्थानीय कर अधिनियम के अनुच्छेद 7 में परिभाषित रियल एस्टेट अधिग्रहीत की है। इस कार्यक्रम के तहत कोई उद्यम उस समय अधिग्रहण कर के लिए कर कटौती की कुछ राशि प्राप्त करना का पात्र होता है जब वह औद्योगिक परिसरों में स्थित रियल एस्टेट अधिग्रहीत करता है। जब कोई उद्यम उन औद्योगिक परिसरों में स्थित रियल एस्टेट अधिग्रहीत करता है जो विशेष स्थानीय कराधान अधिनियम के अनुच्छेद 78(4) के तहत परिभाषित हैं, तो वह कर कटौती प्राप्त कर सकता है।
115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में उस परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और जिससे लाभ प्रदान किया जाता है। लाभ की राशि अधिनियम के तहत देय कर और कटौती के बाद प्रदत्त कर के बराबर है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन उद्यमों तक सीमित है जो निर्धारित रियल एस्टेट अधिग्रहीत करते हैं।
116. कुम्हो द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि उनके द्वारा इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया गया है। प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम 7.1.2 – कोरिया एनर्जी एजेंसी द्वारा सशर्त ऋण/ऋण

कोरिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

117. विदेश में खोज व्यापार परियोजना के लिए कोरिया एनर्जी एजेंसी द्वारा सशर्त ऋण प्रदान किए जाते हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

118. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोरिया एनर्जी एजेंसी (के ई ए) एक सरकारी एजेंसी है जो ऊर्जा क्षमता के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा नीतियां बनाती हैं।
119. कार्यक्रमों को संचालित करने वाले संगत कानून ओवरसीज रिसोर्सेज डेवलपमेंट बिजनेस एक्ट और एनर्जी एंड रिसोर्सेज स्पेशल अकाउंट एक्ट हैं। ओवरसीज रिसोर्सेज डेवलपमेंट बिजनेस एक्ट के अनुच्छेद 10 में यह प्रावधान है कि विदेशी संसाधनों के विकास के संवर्धन के लिए, सरकार विनिर्दिष्ट व्ययों में मदद कर सकती है। ओवरसीज रिसोर्सेज डेवलपमेंट बिजनेस एक्ट के अनुच्छेद 11 के तहत यह प्रावधान है कि सरकार एक ओवरसीज रिसोर्सेज डेवलपमेंट को ओवरसीज संसाधन विकास में सहायता प्रदान करती है। एनर्जी एंड रिसोर्सेज स्पेशल अकाउंट एक्ट में ओवरसीज संसाधनों सहित ऊर्जा और संसाधनों के संबंध में परियोजनाओं के लिए स्थापित धनराशि के लिए विशेष लेखों का प्रावधान है।
120. इस कार्यक्रम के तहत, ओवरसीज एक्सप्लोरेशन बिजनेस परियोजना के लिए कोरिया एनर्जी एजेंसी द्वारा उद्यमों को ऋण प्रदान किए जाते हैं। उद्यमों को व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय से ओवरसीज फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट बिजनेस फंड के अनुरूप होना चाहिए। ऋणों का अनुमोदन, जारी करना और अदायगी व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई इस घोषणा द्वारा संचालित होती है। इस कार्यक्रम के तहत, यदि ओवरसीज एक्सप्लोरेशन बिजनेस परियोजना वाणिज्यिक रूप से काम शुरू कर देती है ऋणों की अदायगी की बाध्यता होती है, ।

121. तदनुसार, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि कोरिया एनर्जी एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए ऋण एक सार्वजनिक निकाय द्वारा धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में एक वित्तीय योगदान है।
122. प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए लाभ माफ किए गए ऋण की राशि के रूप में है और यदि ऋण की अदायगी की जानी है तो इन बैंकों द्वारा प्रभारित व्यय की राशि और तुलनात्मक वाणिज्यिक ऋण पर प्रभारित व्याज की राशि के बीच का अंतर है। यह कार्यक्रम भी विशेष रूप से बनाया गया है, क्योंकि यह या तो निर्यात प्रासंगिक है या ऐसे उद्यमों तक सीमित है जो ऋण के लिए अन्य विशिष्ट मानदंड की पूर्ति करते हैं। कुम्हो द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर में यह दर्शाया गया है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के खिलाफ प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम 7.1.3 – एक वर्कप्लेस इंफेंट केयर सेंटर स्थापित करना और विस्तारित करना

कोरिया सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

123. एक वर्कप्लेस इंफेंट केयर सेंटर के लिए वर्ष 2015 में अनुदान प्राप्त किया गया था और कोरिया वर्क्स कंपेंसेशन एंड वेलफेयर सर्विसेज द्वारा पोस्को इंटरनेशनल को भुगतान किया गया था। मूल अनुदान की राशि की चार (4) वर्षों में मूल्य कम हो रहा है।
124. एल जी केम द्वारा यह दावा किया गया है कि उसने एक वर्कप्लेस, इंफेंट केयर सेंटर संचालित करने के लिए जांच की अवधि के दौरान श्रम लागत सहायता की *** के आर डब्ल्यू राशि प्राप्त की है। तथापि, प्राप्त की गई समस्त राशि इंफेंट केयर सेंटर को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित की गई है, जिसके लिए प्रतिवादी का यह मानना है कि एक वर्कप्लेस इंफेंट केयर सेंटर के संचालन के लिए श्रम लागत सहायता कार्यक्रम से कोई भी लाभ नहीं मिला है। यह दावा किया गया है कि वर्कप्लेस और नर्सरी के निर्माण के लिए कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं है। वर्कप्लेस चाइल्ड केयर सेंटरों के निर्माण/ स्थापना कारोबार के स्वामी का शुल्क पर नियंत्रण होता है, जो प्रेसीडेंसियल डिग्री द्वारा विनिर्दिष्ट आकार से बड़े आकार में एक वर्कप्लेस संचालित करता है। वर्कप्लेस और नर्सरी के निर्माण से प्राप्त लाभ ही सम्पत्ति कर में कमी और "आरएसएलटीए – अनुच्छेद 19 (चाइल्ड केयर सेंटरों और किंडरगार्टनों के लिए कटौती या छूट)" के तहत चाइल्ड केयर सेंटर के लिए सम्पत्ति कर कटौती और अर्जित कर कटौती है। प्राप्त कर कटौती का व्यौरा "अन्य कार्यक्रम" के उत्तर के रूप में पहले ही प्रदान किया जा चुका है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

125. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत कोरिया वर्क्स कंपेंसेशन एंड वेलफेयर सर्विसेज द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसका हर चार वर्षों में मूल्य ह्रास हो जाता है।
126. प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनुदान, धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में एक वित्तीय योगदान है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया गया है। सब्सिडी कार्यक्रम भी यह कार्यक्रम भी विशेष रूप से बनाया गया है क्योंकि यह एक इंफेंट केयर सेंटर वाले कतिपय उद्यमों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है।
127. पोस्को द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर से यह दर्शाया गया है कि ए यू एल अवधि के दौरान इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत उन्हें लाभ मिला है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम 7.1.4 – आर एंड डी परिसम्पत्तियों के लिए अनुदान

कोरिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

128. विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्राप्त कतिपय एकमुश्त अनुदान कंपनियों के वित्तीय विवरणों में दर्ज किया गया था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

129. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत, आर एंड डी सम्पत्तियों जैसे टूल और माड्यूल के लिए अनुदान प्राप्त किया गया था और स्टील प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए सम्पत्ति, संयंत्र और मशीनरी के लिए आंशिक अनुदान प्राप्त हुआ था।
130. प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनुदान धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में एक वित्तीय योगदान है और उससे लाभ प्रदान किए हैं। यह सब्सिडी कार्यक्रम भी विशेष रूप से बनाया गया है, क्योंकि यह आर एंड डी क्रियाकलाप में लगे कतिपय उद्यमों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। पोस्को द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली

उत्तर यह दर्शाते हैं कि ए यू एल अवधि के दौरान इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत उन्हें लाभ मिले हैं। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह लाभ गैर विचाराधीन उत्पाद से जुड़ा है। इसलिए प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के खिलाफ कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाए।

कार्यक्रम 7.1.5 – कारपोरेट कर छूट

कोरिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

131. विभिन्न निवेश व्ययों और अन्य व्ययों के अनुसरण में कंपनियों द्वारा प्राप्त किया गया टैक्स क्रेडिट कंपनी द्वारा दायर की गई वार्षिक कर विवरणी से पहचाना जा सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

132. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत कंपनी वार्षिक कर विवरणी दाखिल करते समय उसके द्वारा किए गए ऐसे अन्य व्ययों और निवेश के लिए कर क्रेडिट का दावा कर सकती है।
133. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम के तहत राजस्व माफी के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय होता। इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त कर क्रेडिट के अभाव में लाभ, भुगतान किए गए कारपोरेट टैक्स और देय कारपोरेट टैक्स के बीच अंतर के समान है। पोस्को द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर यह दर्शाते हैं कि उन्होंने इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम 7.1.6 – एक वर्कप्लेस इंपैक्ट केयर सेंटर के प्रचालन के लिए श्रम लागत सहायता

कोरिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

134. सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक वर्कप्लेस इंपैक्ट केयर सेंटर के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करती है और किंडरगार्टन शिक्षकों की श्रम लागत की व्यवस्था करके उनकी सहायता करती है। ऐसी सहायता आवर्ती होती है, क्योंकि वर्कप्लेस इंपैक्ट केयर सेंटर द्वारा लिए गए किंडरगार्टन शिक्षकों की संख्या पर विचार करते हुए मासिक और नियमित आधार पर लाभ दिए जाने चाहिए। साथ ही, ऐसे लाभ वर्कप्लेस इंपैक्ट केयर सेंटर के बैंकिंग खाते को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किए जाते हैं और केवल श्रम लागत के लिए व्यय किए जाने तक सीमित है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा वर्कप्लेस पर इंपैक्ट केयर सेंटर के श्रम लागत व्ययों के लिए सरकार द्वारा एक उद्यम को अनुदान प्रदान किया जाता है।
136. प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनुदान धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में एक वित्तीय योगदान है और एतद्वारा लाभ प्रदान किए जाते हैं। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशेष रूप से बनाया गया है, क्योंकि यह एक इंपैक्ट केयर सेंटर वाले कतिपय उद्यमों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है।
137. पोस्को द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली उत्तर यह दर्शाते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम 7.1.7 – कोरिया अंतराष्ट्रीय बैंक ("आईबीके") के अलावा अन्य सरकारी निवेश वाले बैंकों से ऋण

कोरिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

138. सरकारी निवेश वाले बैंकों से ऋण लेने वाली कंपनियां जैसे कोरिया एनर्जी एजेंसी, कोरिया डेवलपमेंट बैंक, कोरिया, दि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया (केईएक्सआईएम), कोरिया रूरल कम्यूनिटी कारपोरेशन (केआरसी), जो न केवल विचाराधीन उत्पाद संबंधी कारोबार के लिए प्रयोग किए गए हैं बल्कि उनके सामान्य प्रचालन नकदी प्रवाह अथवा गैर

विचाराधीन उत्पाद के कारोबारों जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक खनन तथा खाद्य संसाधन विकास परियोजना के लिए भी प्रयुक्त किए गए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

139. इस कार्यक्रम के तहत, सामान्य प्रचालनों और ऐसे प्रचालनों, जो संबद्ध उत्पाद के उत्पादन से संबंधित नहीं हैं, के लिए कोरिया में सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा उद्यमों को ऋण प्रदान किए जाते हैं।
140. प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारित किया है कि ये सरकारी स्वामित्व वाले बैंक सार्वजनिक निकाय हैं। तदनुसार, सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण एक सार्वजनिक निकाय द्वारा धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान हैं। प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए लाभ इन बैंकों द्वारा प्रभारित व्याज की राशि और तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर प्रभारित व्याज की राशि के बीच के अंतर के रूप में हैं। यह कार्यक्रम भी विशेष रूप से बनाया गया है, क्योंकि यह ऐसे उद्यम के लिए सीमित है, जो ऋण के लिए विशिष्ट मानदंडों को पूरा करता है। पोस्को द्वारा दाखिल किया गया प्रश्नावली उत्तर यह दर्शाता है कि उनके द्वारा इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया गया है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के खिलाफ प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाया जाए।

कार्यक्रम 7.1.8 – बंदरगाह सुविधाएं इस्तेमाल करने के लिए प्राप्त उपयोग प्रोत्साहन

कोरिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

141. कंपनियां बंदरगाह के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पोहांग इओंगिल पोर्ट अथॉरिटी से बंदरगाह इस्तेमाल प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं। स्थानीय सरकार बंदरगाह पर शिपिंग कंटेनर कार्गो को हैंडल करने वाले कन्साइनर और फारवार्डर को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। यह प्रोत्साहन बंदरगाह का इस्तेमाल करने वाले कंटेनरों की कार्गो मात्रा के आधार पर प्रदान किया जाता है।
142. ऐसे प्रोत्साहन बार-बार प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर अर्ध वर्ष के बाद स्थानीय सरकार द्वारा नियमित रूप से मापा जाता है। प्रोत्साहन की राशि इतनी कम है कि इसका नगण्य लाभ होता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

143. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय सरकार द्वारा ऐसे कन्साइनरों, फारवार्डरों तथा अन्य को अनुदान प्रदान किया जाता है, जो बंदरगाह पर शिपिंग कार्गो को हैंडल करते हैं।
144. प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि कार्यक्रम के तहत स्थानीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में धनराशि का प्रत्यक्ष अंतरण प्रदान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय योगदान होता है और उससे लाभ प्रदान किए जाते हैं। सब्सिडी कार्यक्रम भी ऐसे उद्यमों के लिए प्रासंगिक जो बंदरगाह सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। पोस्को द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर से यह दर्शाया गया है कि उनके द्वारा इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किए जाते हैं। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम 7.1.9 – इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में आर एंड डी के लिए प्राप्त सहायता

कोरिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

145. कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों और माड्यूल वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी के लिए, जांच की अवधि से पूर्व लाभ प्राप्त किए गए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

146. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि (i) माड्यूल वाणिज्यिकरण प्रौद्योगिकी और (ii) छोटे एवं मध्यम वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए आई ओ टी प्रौद्योगिकी के आधार पर अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में धनराशि का प्रत्यक्ष अंतरण प्रदान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय योगदान होता है और उससे लाभ प्रदान किए जाते हैं। सब्सिडी कार्यक्रम भी कतिपय उद्यमों के लिए प्रासंगिक है। पोस्को द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर यह दर्शाते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा लाभ प्राप्त किए गए हैं। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लाभ गैर विचाराधीन उत्पाद से जुड़े हैं। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के खिलाफ कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम 7.1.10 – खाद्य एवं कृषि उद्योग में एक ओवरसीज अनुसंधान परियोजना के लिए सहायता**कोरिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

147. कंपनियां खाद्य और कृषि उद्योग में अपनी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह कार्यक्रम विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन अथवा निर्यात से संबंधित नहीं हैं और इस प्रकार, यह प्रतिसंतुलनकारी नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

148. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में ओवरसीज अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
149. प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में धनराशि का प्रत्यक्ष अंतरण प्रदान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय योगदान मिलता है और उससे लाभ प्रदान किए जाते हैं। सब्सिडी कार्यक्रम भी कतिपय उद्यमों तक प्रासंगिक हैं। पोस्को द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर यह दर्शाते हैं कि उनके द्वारा इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किए जाते हैं। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लाभ गैर विचाराधीन उत्पाद से जुड़े हैं। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के खिलाफ कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम 7.1.11 – आस्ट्रेलिया में कॉपर खान विकास में एक अनुसंधान परियोजना के लिए सहायता**कोरिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

150. आस्ट्रेलिया में एक कॉपर खान शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन के लिए अनुदान प्राप्त किए गए। यह कार्यक्रम विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन अथवा निर्यात के लिए संबंधित नहीं है और इस प्रकार यह प्रति संतुलनकारी नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

151. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत ओवरसीज खान परियोजना के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है।
152. प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए प्रावधान है जिसके फलस्वरूप वित्तीय योगदान होता है और उससे लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी कार्यक्रम कतिपय उद्यमों के लिए प्रासंगिक है। पोस्को द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर यह दर्शाते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा लाभ प्राप्त किए गए हैं। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लाभ गैर विचाराधीन उत्पाद से जुड़ा है। तथापि, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के खिलाफ कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कुम्हो और पोस्को (उत्पादक/ निर्यातक)

153. कुम्हो कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है। कुम्हो द्वारा उत्पादित की गई संबद्ध वस्तुएं भारतीय उपभोक्ताओं को कुम्हो द्वारा सीधे भारत को निर्यात की जाती हैं। इन दोनों कंपनियों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं और उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभ के संबंध में सूचना प्रदान की है।
154. प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के आधार पर कुम्हो और पोस्को के द्वारा प्रदान की गई सूचना की यथासंभव जांच की है और ऐसे कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है, जिसके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किया गया अथवा अर्जित किया गया। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि सब्सिडी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप ऋणों, अनुदानों और पूर्व निश्चित राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान किया गया, जो अन्यथा देय था। इसके परिणामस्वरूप कुम्हो और पोस्को को इन अनुदानों के प्राप्तकर्ता के रूप में लाभ प्रदान किया गया था। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशेष रूप से बनाया गया था क्योंकि यह कुम्हो और पोस्को सहित कतिपय उद्यमों तक सीमित था।
155. नीचे सारणी में सब्सिडी कार्यक्रमों के नाम और तदनुसंगी सब्सिडी मार्जिन उपलब्ध कराए गए हैं:-

सब्सिडी मार्जिन संक्षिप्त सारणी : कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं० लि और पोस्को

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	सीआईएफ के % के रूप में सब्सिडी मार्जिन	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन रेंज
याचिका के कथित कार्यक्रम				
कुम्हो				
(1)	निगमित पुर्नसंरचना (ऋण, ऋणों पर रियायती अवधि, यूएसएएनसीई)	***	ऋण/अनुदान	0-5%
1(2)	निगमित पुर्नसंरचना (परिवर्तनीय बांड)	***	ऋण/अनुदान	
3	अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए सरकारी अनुदान	***	ऋण/अनुदान	0-5%
4(1)	नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना ढांचा नीति (ऋण)	***	ऋण	0-5%
4(2)	नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना ढांचा नीति (अनुदान)	***	अनुदान	
5	विशेष कराधान अधिनियम के प्रतिबंध के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजना समर्थन नीति (कर क्रेडिट/पूर्व निर्धारित राजस्व)	***	कर क्रेडिट/पूर्व निर्धारित राजस्व	0-5%
6	इंडस्ट्रीयल बैंक ऑफ कोरिया द्वारा अधिमान्य ऋण	***	ऋण	0-5%
7.1.1	औद्योगिक परिसरों में स्थावर संपदा के लिए स्थानीय कर की कटौती	***	कर क्रेडिट/पूर्व निर्धारित राजस्व	0-5%
7.1.2	सशर्त ऋण	***	ऋण/अनुदान	0-5%
कुम्हो के लिए जोड़		***		0-5%
पोस्को				
7.1.3	कार्य स्थान पर एक शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना एवं प्रचालन हेतु अनुदान	***	अनुदान	0-5%
7.1.5	निवेश और अन्य व्ययों के लिए निगमित कर छूट, कर क्रेडिट	***	कर क्रेडिट/पूर्व निर्धारित राजस्व	0-5%
7.1.6	कार्य स्थान पर शिशु देखभाल केंद्र के प्रचालन के लिए श्रम लागत सहायता	***	अनुदान	0-5%
7.1.7	आईबीके के अतिरिक्त सरकार द्वारा निवेशित बैंकों से ऋण	***	ऋण	0-5%
7.1.8	पोहांग योंगिल एवं ग्वांगयांग पत्तन के लिए प्राप्त उपयोग प्रोत्साहन	***	अनुदान	0-5%

पोस्को के लिए जोड़	***		0-5%
कुम्हो और पोस्को के लिए भारांशित औसत	***		0-5%

156. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कुम्हो और पोस्को के लिए सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।

अन्य सब्सिडियां : एल जी केम लि०

157. याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्तानुसार उपरोक्त कार्यक्रम संख्या 1 से 6 के अलावा कोई अन्य सब्सिडी कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया था। तथापि, प्रतिवादी उत्पादक/ निर्यातक मै० एल जी केम, कोरिया गणराज्य ने जांच की अवधि के दौरान यह प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अन्य कार्यक्रमों के तहत निम्नलिखित लाभ/ सब्सिडी प्राप्त की है।

एल जी केम लि०

158. निम्नलिखित अन्य सब्सिडी हैं जो निर्माता / निर्यातक द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई हैं

एल जी केम लि०

कार्यक्रम 7.2.1 : अन्य सब्सिडी – औद्योगिक परिसरों आदि के लिए कटौती

क. कोरिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

159. औद्योगिक परिसरों में रीयल एस्टेट के लिए स्थानीय कर में कटौती के संबंध में, यह अनुरोध किया गया है कि प्रश्नावली उत्तर तैयार करते समय, एल जी केम ने यह पाया कि विभिन्न स्थानीय कर कटौतियां जांच की अवधि के दौरान आरएसएलटीए के तहत प्राप्त की गई थी। यह भी अनुरोध किया गया है कि एल जी केम को जांच की अवधि के दौरान ए यू एल के दौरान गैर-आवर्ती कार्यक्रम के संबंध में विशेष स्थानीय कराधान का प्रतिषेध अधिनियम (इसके बाद आरएसएलटीए) के अनुच्छेद 19, 47(2) और 78 के तहत अन्य विभिन्न स्थानीय कर कटौती प्राप्त की।
160. आरएसएलटीए के अनुच्छेद 78 – औद्योगिक परिसरों के लिए कटौती, इत्यादि के तहत एल जी केम को कुछ मात्रा में स्थानीय कर कटौतियां प्राप्त हुई हैं। एक आवर्ती कार्यक्रम के रूप में, एल जी केम को जांच की अवधि के दौरान संपत्ति कर कटौती के रूप में 68.8 मिलियन के आर डब्ल्यू प्राप्त हुए और एक गैर-आवर्ती कार्यक्रम के रूप में एल जी केम को ए यू एल के दौरान अर्जित कर कटौती के रूप में 15,668 मिलियन के आर डब्ल्यू प्राप्त हुए हैं।
161. तथापि, आरएसएलटीए के तहत कारपोरेट कर क्रेडिट की तरह से स्थानीय कर कटौती की कुल राशि कुल कंपनी राजस्व में अपेक्षाकृत कम है। इसके साथ ही, केवल स्थानीय कर कटौती का केवल कुछ ही हिस्सा उत्पादन के संबंध में और विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियों के संबंध में है।
162. कोरिया की सरकार ने आनलाइन सत्यापन के दौरान आरएसएलटीए के तहत कई स्थानीय कर कटौतियों सहित औद्योगिक परिसरों इत्यादि के लिए अन्य सब्सिडी – संपत्ति कर कटौती के संबंध में सूचना प्रदान की है।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

163. कार्यक्रम के तहत राजस्व माफी के रूप में और प्रत्यक्ष धन अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया जाता है और एतद्वारा ऐसे वित्तीय अंशदान प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किए गए हैं। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बनाया गया है क्योंकि यह कतिपय उद्यम तक सीमित है। एल जी केम लि० को इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुए हैं। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के तहत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(i) कार्यक्रम 7.2.2 : अन्य सब्सिडी – सियोसन सिटी से औद्योगिक परिसरों इत्यादि के लिए अधिग्रहण कर कटौती

क. कोरिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

164. आरएसएलटीए के अनुच्छेद 78 – औद्योगिक परिसरों के लिए कटौती आदि के तहत एल जी केम को कुछ मात्रा में अधिग्रहण कर कटौतियां प्राप्त हुई हैं। एक गैर-आवर्ती कार्यक्रम के रूप में, एल जी केम को ए यू एल के दौरान 3045 मिलियन के आर डब्ल्यू की अधिग्रहण कर कटौती प्राप्त हुई।

165. तथापि, आरएसटीए के तहत कारपोरेट कर क्रेडिट की तरह स्थानीय कर कटौती की कुल राशि कुल कंपनी राजस्व में अपेक्षाकृत छोटी है। इसके साथ ही, केवल स्थानीय कर कटौती का कुछ ही हिस्सा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और विक्रियों से संबद्ध है।
166. कोरिया की सरकार ने आनलाइन सत्यापन के दौरान सियोसन सिटी से औद्योगिक परिसरों इत्यादि के लिए अन्य सब्सिडी अधिग्रहण कर कटौती से संबंधित सूचना प्रदान की है।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

167. कार्यक्रम के तहत राजस्व माफी के रूप में और धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया जाता है और एतद्वारा ऐसे वित्तीय योगदान प्राप्तकर्ता को एतद्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बनाया गया, क्योंकि यह कतिपय उद्यम तक सीमित है।
168. एल जी केम लि० को इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ मिला है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(i) कार्यक्रम संख्या 7-3 : अन्य सब्सिडी – ग्रीन आर्किटेक्चर के रूप में प्रमाणित भवनों के लिए संपत्ति कर कटौती

क. कोरिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

169. आरएसएलटीएस के अनुच्छेद 47(2) – ग्रीन आर्किटेक्चर के रूप में प्रमाणित भवनों के लिए कटौती के तहत एल जी केम को जांच की अवधि के दौरान 4.5 मिलियन के आर डब्ल्यू की संपत्ति कर कटौती प्राप्त हुई है।
170. तथापि, आरएसटीए के तहत कारपोरेट कर क्रेडिट की तरह स्थानीय कर कटौती की कुल राशि कुल कंपनी राजस्व में अपेक्षाकृत छोटी है। इसके साथ ही, स्थानीय कर कटौती का एक छोटा हिस्सा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और विक्रियों के संबंध में है।
171. कोरिया सरकार ने आनलाइन सत्यापन के दौरान ग्रीन आर्किटेक्चर के रूप में प्रमाणित भवनों के लिए अन्य सब्सिडी – संपत्ति कर कटौती के संबंध में सूचना प्रदान की।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

172. कार्यक्रम के तहत राजस्व माफी और धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है और ऐसे वित्तीय योगदान के प्राप्तकर्ता को एतद्वारा लाभ प्रदान किया है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बनाया गया क्योंकि यह कतिपय उद्यम तक सीमित है।
173. एल जी केम लि० को इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(ii) कार्यक्रम संख्या 7-4 : अन्य सब्सिडी – सियोल सिटी से ग्रीन आर्किटेक्चर के रूप में प्रमाणित भवनों के लिए अधिग्रहण कर कटौती

क. कोरिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

174. आरएसएलटीएस का अनुच्छेद 47 (2) – ग्रीन आर्किटेक्चर के रूप में प्रमाणित भवनों के लिए कटौती के तहत एल जी केम को छोटी मात्रा में अधिग्रहण कर कटौती प्राप्त हुई है। एक गैर-आवर्ती कार्यक्रम के रूप में, एल जी केम को ए यू एल के दौरान 240.0 मिलियन के आर डब्ल्यू की अधिग्रहण कर कटौती प्राप्त हुई।
175. तथापि, आरएसटीए के तहत कारपोरेट कर क्रेडिट की ही तरह से, स्थानीय कर कटौती की कुल राशि कुल कंपनी राजस्व में अपेक्षाकृत छोटी है। इसके साथ ही, स्थानीय कर कटौती का केवल कुछ ही हिस्सा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और विक्रियों से संबंधित है।

176. कोरिया गणराज्य की सरकार ने आनलाइन सत्यापन के दौरान सियोल सिटी से अन्य सब्सिडी – ग्रीन आर्किटेक्चर के रूप में प्रमाणित भवनों के लिए अधिग्रहण कर कटौती से संबंधित सूचना प्रदान की है।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

177. कार्यक्रम के तहत राजस्व माफी और धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है और एतद्वारा ऐसे वित्तीय योगदान के प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया गया है। कार्यक्रम विशेष रूप से बनाया गया है, क्योंकि यह कतिपय उद्यम तक सीमित है।
178. एल जी केम लि० को इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ मिला है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(iii) कार्यक्रम संख्या 7-5-1 : अन्य सब्सिडी – डेजियोन सिटी से चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए संपत्ति कर कटौती

क. कोरिया गणराज्य की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

179. आरएसएलटीए के अनुच्छेद 19 – चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए कटौती अथवा छूट के तहत एल जी केम को कुछ ही मात्रा में संपत्ति कर कटौतियां प्राप्त हुई हैं। एक आवर्ती कार्यक्रम के रूप में, एल जी केम को जांच की अवधि के दौरान 1.0 मिलियन के आर डब्ल्यू संपत्ति कर कटौती प्राप्त हुई है।
180. तथापि, आरएसटीए के तहत कारपोरेट कर क्रेडिट की तरह ही स्थानीय कर कटौती की कुल राशि कुल कंपनी राजस्व में अपेक्षाकृत छोटी है। इसके साथ ही, स्थानीय कर कटौती का केवल कुछ ही हिस्सा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और विक्रियों के संबंध में है।
181. कोरिया गणराज्य की सरकार ने आनलाइन सत्यापन के दौरान दाओजियोन सिटी से चाइल्ड केयर सेंटर और किंडरगार्टन के लिए अन्य सब्सिडी – संपत्ति कर कटौती के संबंध में सूचना प्रदान की है।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

182. कार्यक्रम के तहत राजस्व माफी के रूप में और धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है और एतद्वारा ऐसी वित्तीय योगदान के प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किए गए हैं। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बनाया गया है, क्योंकि यह कतिपय उद्यम तक सीमित है।
183. एल जी केम लि० इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्रदान किया गया है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(iv) कार्यक्रम संख्या 7-5-2 : अन्य सब्सिडी – सियोल सिटी से चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए संपत्ति कर कटौती

क. कोरिया गणराज्य की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

184. आरएसएलटीए के अनुच्छेद 19 – चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए कटौती अथवा छूट के तहत एल जी केम को संपत्ति कर कटौती की कुछ राशि प्राप्त हुई। आवर्ती कार्यक्रम के रूप में एल जी केम को जांच की अवधि के दौरान 2.0 मिलियन के आर डब्ल्यू संपत्ति कर कटौती प्राप्त हुई।
185. तथापि, आरएसटीए के तहत कारपोरेट कर क्रेडिट के समान ही स्थानीय कर कटौती की कुल राशि कुल कंपनी राजस्व में अपेक्षाकृत छोटी है। इसके साथ ही, केवल कुछ ही स्थानीय कर कटौती का हिस्सा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और विक्रियों से संबंधित है।
186. कोरिया गणराज्य की सरकार ने आनलाइन सत्यापन के दौरान सियोल सिटी से चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए अन्य सब्सिडी – संपत्ति कर कटौती के संबंध में सूचना प्रदान की है।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

187. कार्यक्रम के तहत राजस्व माफी और धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है और एतद्वारा ऐसे वित्तीय योगदान के प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया गया है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बनाया गया है, क्योंकि यह कतिपय उद्यम तक सीमित है।
188. एल जी केम लि० को इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(v) कार्यक्रम संख्या 7-6-1 : अन्य सब्सिडी – सियोल सिटी से चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए अधिग्रहण कर कटौती**क. कोरिया गणराज्य की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

189. आरएसएलटीए के अनुच्छेद 19 – चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए कटौती अथवा छूट के तहत एल जी केम को छोटी मात्रा में अधिग्रहण कर कटौतियां प्राप्त हुई हैं। एक गैर-आवर्ती कार्यक्रम के रूप में, एल जी केम को ए यू एल के दौरान अधिग्रहण कर कटौती के 89.5 मिलियन के आर डब्ल्यू प्राप्त हुए।
190. तथापि, आरएसटीए के तहत कारपोरेट कर क्रेडिट की ही तरह, स्थानीय कर कटौती की कुल राशि कुल कंपनी राजस्व में अपेक्षाकृत कम है। इसके अलावा, केवल स्थानीय कर कटौती का कुछ ही हिस्सा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और विक्रियों के संबंध में है।
191. कोरिया गणराज्य की सरकार ने आनलाइन सत्यापन के दौरान सियोल सिटी से चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए अन्य सब्सिडी – अधिग्रहण कर कटौती के संबंध में सूचना प्रदान की है।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

192. कार्यक्रम के तहत राजस्व माफी और धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया जाता है और एतद्वारा ऐसे वित्तीय योगदान के प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया गया है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बनाया गया है, क्योंकि यह कतिपय उद्यम तक सीमित है।
193. एल जी केम लि० को इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(vi) कार्यक्रम संख्या 7-6-2 : अन्य सब्सिडी – देवजियोन सिटी के लिए चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए अधिग्रहण कर कटौती**क. कोरिया गणराज्य की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

194. आरएसएलटीए के अनुच्छेद 19 – चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए कटौती अथवा छूट के तहत एल जी केम को छोटी मात्रा में अधिग्रहण कर कटौतियां प्राप्त हुई हैं। एल जी केम को ए यू एल के दौरान अधिग्रहण कर कटौती के लिए 36.5 मिलियन के आर डब्ल्यू प्राप्त हुए।
195. तथापि, आरएसटीए के तहत कारपोरेट कर क्रेडिट की ही तरह, स्थानीय कर कटौती की कुल राशि कुल कंपनी राजस्व में अपेक्षाकृत कम है। इसके अलावा, केवल स्थानीय कर कटौती का कुछ ही हिस्सा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और विक्रियों के संबंध में है।
196. कोरिया गणराज्य की सरकार ने आनलाइन सत्यापन के दौरान देजियोन सिटी से चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए अन्य सब्सिडी – अधिग्रहण कर कटौती के संबंध में सूचना प्रदान की है।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

197. कार्यक्रम के तहत राजस्व माफी और धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया जाता है और एतद्वारा ऐसे वित्तीय योगदान के प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया गया है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बनाया गया है, क्योंकि यह कतिपय उद्यम तक सीमित है।
198. एल जी केम लि० को इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
199. एल जी केम लि० को इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(vii) कार्यक्रम संख्या 7-7 : अन्य सब्सिडी – एक वर्कप्लेस इंफेंट केयर सेंटर के प्रचालन के लिए श्रम लागत सहायता**क. कोरिया गणराज्य की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

200. एल जी केम को एक वर्कप्लेस इंफेंट केयर सेंटर चलाने के लिए श्रम लागत सहायता भी प्राप्त हुई है। तथापि, प्राप्त हुए समस्त राशि प्रत्यक्ष रूप से इंफेंट केयर सेंटर को अंतरित की गई। यह अनुरोध किया गया था। प्रतिवादी यह विश्वास करते हैं कि एक वर्कप्लेस इंफेंट केयर सेंटर चलाने के लिए श्रम लागत सहायता कार्यक्रम से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
201. कोरिया गणराज्य की सरकार ने आनलाइन सत्यापन के दौरान संगत विनियमों सहित एक वर्कप्लेस इंफेंट केयर सेंटर चलाने के लिए अन्य सब्सिडी श्रम लागत सहायता के लिए संबद्ध सूचना प्रदान की है।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

202. कार्यक्रम के तहत धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया जाता है। तथापि, यह किसी वित्तीय योगदान के प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान नहीं करता।
203. एल जी केम लि० को इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। एल जी केम लि० को इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(viii) कार्यक्रम संख्या 7-8 : अन्य सब्सिडी – के-शोर एक्सपोर्ट संबंधी क्रेडिट गारंटी**क. कोरिया गणराज्य की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

204. यह कहा गया था कि एल जी केम ने अपने निर्यात विक्रयों के लिए के-शोर क्रेडिट गारंटी का इस्तेमाल किया है। एल जी केम इसके लिए अतिरिक्त व्यय वहन करता है। के-शोर क्रेडिट गारंटी के इस्तेमाल के लिए हुआ व्यय पूरी कंपनी के लिए है और भारत के बाजार में विचाराधीन उत्पाद की निर्यात विक्री में, सत्यापन पैकेज के रूप में प्रदान किया जाता है। यह भी कहा गया था कि भारत के बाजार में विचाराधीन उत्पाद की निर्यात विक्रयों के बारे में व्यापार प्राप्त राशि की कोई चूक नहीं है। अतः के-शोर की निर्यात संबंधी क्रेडिट गारंटी के तहत कोई वित्तीय योगदान प्राप्त नहीं हुआ।
205. कोरिया गणराज्य की सरकार ने आनलाइन सत्यापन के दौरान संगत विनियमों सहित अन्य सब्सिडी – के-शोर निर्यात संबंधी क्रेडिट गारंटी के संबंध में सूचना प्रदान की है।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

206. एल जी केम लि० को इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। एल जी केम लि० को इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
207. नीचे दी गई तालिका में एल जी केम लि०, कोरिया गणराज्य के संबंध में सब्सिडी कार्यक्रमों और उनके अनुरूप सब्सिडी मार्जिन के संबंध में ब्यौरे दिए गए हैं :-

कार्यक्रम सं.	अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सीआईएफ के % के रूप में सब्सिडी मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
			%	
कार्यक्रम सं. 4	अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं – स्थापना नीति	ऋण/ अनुदान	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 5	अनुसंधान और विकास परियोजना सहायता नीति/ विशेष आर एंड डी जोन के भीतर कंपनियों के लिए कारपोरेट कर छूट / कटौती	टैक्स क्रेडिट / राजस्व माफी	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 7-1	औद्योगिक परिसरों आदि के लिए संपत्ति कर कटौती	टैक्स क्रेडिट / राजस्व माफी	***	0-5%
कार्यक्रम सं.	सियोसन सिटी से औद्योगिक परिसरों आदि के	टैक्स क्रेडिट / राजस्व	***	0-5%

7-2-1	लिए अधिग्रहण कर कटौती	माफी		
कार्यक्रम सं. 7-2-2	सियोल सिटी से औद्योगिक परिसरों आदि के लिए अधिग्रहण कर कटौती	टैक्स क्रेडिट / राजस्व माफी	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 7-3	ग्रीन आर्किटेक्चर के रूप में प्रमाणित भवनों के लिए सम्पत्ति कर कटौती	टैक्स क्रेडिट / राजस्व माफी	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 7-4	सियोल सिटी से ग्रीन आर्किटेक्चर के रूप में प्रमाणित भवनों के लिए अधिग्रहण कर कटौती	टैक्स क्रेडिट / राजस्व माफी	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 7-5-1	दियोजियन सिटी से चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए संपत्ति कर कटौती	टैक्स क्रेडिट / राजस्व माफी	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 7-5-2	सियोल सिटी से चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए संपत्ति कर कटौती	टैक्स क्रेडिट / राजस्व माफी	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 7-6-1	सियोल सिटी से चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए संपत्ति कर कटौती	टैक्स क्रेडिट / राजस्व माफी	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 7-6-2	दियोजन सिटी के लिए चाइल्ड केयर सेंटर्स और किंडरगार्टन के लिए अधिग्रहण कर कटौती	टैक्स क्रेडिट / राजस्व माफी	***	0-5%
	कुल		***	0-5%

208. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एल जी केम लि० के लिए सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।

कोरिया गणराज्य से अन्य उत्पादक और निर्यातक

209. कोरिया गणराज्य से सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क सहयोगी पक्षकारों के लिए सब्सिडी मार्जिन के अधिकतम के आधार पर निर्धारित किया गया है।

विवरण	सीआईएफ का सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज
कार्यक्रम सं. 1-6 , जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा ओराप लगाया गया है	***	0-5%
सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्राप्त की गई अन्य सब्सिडी	***	0-5%
कुल सब्सिडी	***	0-5 %

प्राधिकारी नोट करता है कि कोरिया गणराज्य से अन्य उत्पादक और निर्यातक के लिए सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

210. क्षति तथा कारणात्मक संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- आईएसआरपीएल ने नवंबर, 2013 में अपने परीक्षण उत्पादन की शुरुआत की थी तथा फरवरी, 2014 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की।

- ii. आरआईएल ने अक्टूबर, 2014 में परीक्षण उत्पादन की शुरुआत की तथा अक्टूबर, 2016 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की।
- iii. चूंकि उद्योग ने हाल ही में विनिर्माण की स्थापना की है, इसका उत्पादन तथा बिक्री क्षति की अवधि में एक प्राकृतिक सुधार दर्शाती है।
- iv. सरकार द्वारा पूर्व में लगाई गई पाटन सेवाओं के कारण घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में आंशिक सुधार अतिरिक्त रूप में है।
- v. भारतीय तथा विदेशी उत्पादकों के लिए डिलीवरी समय में अंतर है जो मूल्य तुलनीयता को प्रभावित करता है।
- vi. नए प्लांट संचालनों के कारण उत्पादन क्षमताओं को कम करने के लिए समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग के लाभ की गणना की जा सकती है।
- vii. देश में नई क्षमताओं के साथ व्यावसायीकरण तथा अनुकूलन कर रहे आयात, भारत में उत्पादन तथा खपत के संबंध में एक प्राकृतिक गिरावट दर्शाते हैं, हालांकि कोरियाई आयात, बाजार में कीमतों को आगे बढ़ा रहे हैं।
- viii. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को उचितकीमत लगाने से रोका है।
- ix. आयातों की माल उतराई की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।
- x. कई तथ्यों के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है – (क) विगत वर्षों में घरेलू उद्योग अपरिपक्व चरण में था, (ख) उत्पादन प्रक्रिया इस प्रकार थी जैसे उद्योग उत्पादन का अनुकूलन करता है।
- xi. घरेलू उद्योग सहित क्षमता, आयातित उत्पाद से प्रतिस्पर्धा में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद की बिक्री करने हेतु दबाव बनाने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है।
- xii. घरेलू बिक्री का विस्तार सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इस उद्योग ने आयातों से प्रतिस्पर्धा में उत्पाद की बिक्री की है।
- xiii. घरेलू उद्योग को उत्पादन की लागत से काफी कम कीमत पर बिक्री के लिए मजबूर किया गया है, जिससे इसके परिचालन की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता पर बहुत प्रभाव पड़ा है।
- xiv. घरेलू उद्योग को 2016-17 में लाभ हो रहा था किंतु 2017-18 में घरेलू उद्योग ने वित्तीय हानियों से गुजरना शुरू कर दिया जो आगे जाकर जांच की अवधि में और भी खराब हो गया।
- xv. घरेलू उद्योग द्वारा कमाया गया रोकड़ लाभ तथा ब्याज से पहले लाभ 2016-17 तथा 2017-18 में सकारात्मक थे लेकिन जांच की अवधि में नकारात्मक हो गए।
- xvi. घरेलू उद्योग को बिक्री में हानियों के बावजूद, घरेलू उद्योग के साथ आविष्कारों के स्तर महत्वपूर्ण हैं।
- xvii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग तथा बाजार हिस्सेदारी के संबंध में एक सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि मूल्य मापदंडों के संबंध में नकारात्मक वृद्धि हुई है।
- xviii. आयातों ने पूंजी बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग की योग्यता पर प्रभाव डाला है क्योंकि घरेलू उद्योग हानियों में परिचालन कर रहा है।
- xix. आवेदकों ने देश में क्षमताएं स्थापित करने के लिए 3000 करोड़ रूपए से अधिक निवेश किया है।
- xx. पाटनरोधी सेवाओं को कम मूल्य वाले आयातों के हानिकारक प्रभाव को संबोधित करने के योग्य नहीं बनाया गया है।
- xxi. पहले आयात आवश्यक थे, लेकिन चूंकि घरेलू उद्योग ने स्वयं को स्थापित कर लिया है, अब आयात आवश्यक नहीं हैं।

- xxii. सीवीडी नियमों में दिए गए क्षति मापदंडों की सूची पूर्ण नहीं है जिसे मैनुअल में भी स्वीकृत किया गया है। यदि घरेलू उद्योग, घरेलू उद्योग में क्षति को दर्शाने वाले किन्हीं अन्य मापदंडों को मान्यता देता है तो प्राधिकारी को घरेलू उद्योग में क्षति का आकलन करते समय इस पर विचार करना चाहिए।
- xxiii. घरेलू उद्योग को प्रतिकूल कीमतों पर निर्यात के लिए मजबूर किया गया जो यह दर्शाता है कि यह घरेलू बाजार में पीड़ित है। प्राधिकारी को क्षति दर्शाने वाले मापदंड के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा कम लाभकारी निर्यात पर विचार करना चाहिए।
- xxiv. निर्यात बाजार में पूर्व जांच में प्राधिकारी द्वारा क्षति के संकेत के रूप में अलाभकारी कीमतें नोट की गई हैं।
- xxv. प्राधिकारी अन्य सभी वास्तविक अथवा कुशल आर्थिक मापदंडों पर विचार करने के लिए अपेक्षित है जो घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर प्रभाव डालते हैं।
- xxvi. घरेलू उद्योग पाटन के पूर्व खराब प्रभावों से बहाली की प्रक्रिया में है। मौजूदा मामले में न्यायोचित क्षति मापदंड के रूप में इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए।
- xxvii. यहां तक कि यूरोपीय संघ कानून को विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कोई उद्योग पाटन अथवा सब्सिडी के पूर्व प्रभावों से बहाल होने की प्रक्रिया में है। विभिन्न क्षति मापदंडों की गैर-संपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी को ऐसे सभी अन्य क्षति मापदंडों पर विचार करना चाहिए जो प्राधिकारी के सामने लाए गए थे।
- xxviii. कीमत कटौती, एक ही समय में आयात कीमत तथा घरेलू कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। चूंकि जांच अवधि के दौरान कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर है, एक औसत आधार तुलना अत्यंत त्रुटिपूर्ण है। प्राधिकारी को मासिक तुलना पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक विशेष माह में आयात कीमत तथा बिक्री कीमत पर विचार करते हुए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आयात उन बिक्रियों का नेतृत्व करता है जो उस माह में किए गए हैं। यह तुलना अत्यंत भ्रामक हो जाएगी यदि एक विशेष माह में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना आयात कीमत से की जाए जो उस माह के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त, बिक्री के माह पर उस तिथि के माह वार विश्लेषण के आधार पर विचार किया जाना अपेक्षित है, जब सामग्री बेकार हो गई थी। मात्र बीजक के माह का विचार-विमर्श अनुचित है। इसके अलावा, मासिक विश्लेषण तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि घरेलू बिक्री और निर्यात कीमत दोनों एक ही माह में की गई बिक्री से संबंधित न हों।
- xxix. सभी स्रोतों से आयातों में गिरावट हुई है। संबद्ध देश से आयात अभी भी मात्रा में महत्वपूर्ण हैं।
- xxx. 2016-17 से आरंभ किए जाने हेतु कीमत ह्रास विश्लेषण अपेक्षित है क्योंकि विगत वर्षों में उत्पादन काफी कम था जिसके कारण लागतें अधिक थीं।
- xxxi. घरेलू उद्योग को बाजार में स्वयं को स्थापित करने के लिए आयात मूल्य के मिलान हेतु मजबूर किया गया था। कीमत ह्रास के कारण नकारात्मक कीमत कटौती हुई है जिसे विभिन्न जांच में प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है।
- xxxii. घरेलू उद्योग अभी भी निष्क्रिय क्षमताओं के साथ काम कर रहा है तथा इसे अलाभकारी निर्यात करने के लिए मजबूर किया जाता है और इसे बढ़ते हुए सामान का सामना करना पड़ता है।
- xxxiii. लक्षित उत्पादन तथा बिक्रियों और वास्तविक उत्पादन तथा बिक्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।
- xxxiv. घरेलू उद्योग ब्याज से पहले हानि झेल रहा है। इसलिए घरेलू उद्योग की उच्च ब्याज लागत के लिए क्षति को जिम्मेदार ठहराने का कोई कारण नहीं है।
- xxxv. रोकड़ लाभ यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि विचार-विमर्श के अंतर्गत उत्पाद से संबंधित व्यवसाय सहजता से कार्य कर सकते हैं।
- xxxvi. कीमत न्यूनीकरणमें बढ़ोतरी इस कारण से है कि आरआईएल ने 30 सितंबर, 2016 को अपनी योजना से पूंजी कमाई तथा आरआईएल के मामले में सितंबर, 2016 तक कोई न्यूनीकरण नहीं था।

- xxxvii. घरेलू उद्योग न तो उत्पाद स्तर पर अनुसंधान तथा विकास में अपने द्वारा किए गए व्यय का रिकॉर्ड रखता है और न ही घरेलू उद्योग ने इस विषय में क्षति पर कोई दावा किया है, न ही यह कोई निर्धारित मापदंड है।
- xxxviii. वार्षिक रिपोर्टों में संदर्भित मंदीमात्रा के संबंध में है न कि कीमत के तथा इसका अर्थ है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विस्तार नहीं हुआ, जैसा कि सोचा गया था।
- xxxix. जबकि घरेलू उद्योग में क्षति को मंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ता लाभों का आनंद ले रहे हैं।
- xl. आवेदक पर्याप्त सबूत पेश कर चुके हैं क्योंकि डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों के अनुसार बिक्री की तारीख पर मौजूदा जांच में विश्वास नहीं किया जा सकता। हालांकि, मात्र अनुमान के अलावा हितबद्ध पक्षकारों ने कोई दावा नहीं किया है।
- xli. यहां तक कि मैनुअल के अनुसार, अपवाद के तौर पर रिलाइंस को द्वितीयक स्रोत में रखा जा सकता है।
- xlvi. आवेदकों के कच्चे माल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के समान हैं तथा इसलिए कोई कारण नहीं है कि क्यों स्थानांतरित कीमतों के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है।
- xlvi. अन्य हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा क्षति होने के किसी भी अन्य कारण के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। इसलिए, किसी भी जिम्मेदार विश्लेषण का संचालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xliv. जन हित के तर्क-वितर्क की प्रतिक्रिया में, घरेलू उद्योग ने उसे प्रस्तुत किया है, जबकि घरेलू उद्योग वित्तीय हानियां झेल रहा है, संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है। मौजूदा मामले में कोई प्रतिकूल जन हित शामिल नहीं है। जबकि जन हित के संदर्भ में बल्कि उपभोक्ता, उपभोक्ता हित की बात कर रहे हैं। घरेलू उद्योग की क्षति की लागत पर उपभोक्ता हित को नहीं बचाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, इसके फलस्वरूप कर्तव्यों का प्रभाव अत्यधिक महत्वहीन होगा।
- xliv. पाटनरोधी अथवा सब्सिडी-रोधी कर्तव्य संरक्षणवादी मानदंड नहीं है किंतु इन्हें अनुचित व्यापार व्यवहार की जांच के लिए लगाया जाता है।
- xlvi. संपूर्ण रूप से घरेलू उद्योग के लिए क्षति की जांच का संचालन अपेक्षित है, न कि एक उत्पादक के लिए चयनित रूप से।
- xlvi. आईएसआरपीएल द्वारा कमाए गए लाभ इसके द्वारा किए गए पूंजी निवेश के विचार से महत्वहीन हैं।
- xlvi. अन्य हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के किसी भी अन्य कारण के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं।
- xlvi. घरेलू उत्पादकों की बिक्री कीमतों के संबंध में अनुरोधों का उत्तर देते हुए, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कीमत, लागत प्रारूपों में इसके द्वारा प्रदान की गई है। उत्तरदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के कुछ स्रोतों के बजाए उसी का सत्यापन किया जा सकता है तथा उस पर विश्वास किया जा सकता है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

211. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:-

- कटौती के उद्देश्य हेतु आयात में समय अंतराल के लिए अपेक्षित कोई विशेष तर्क नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी आयात लेन-देन, एलसी की शुरूआत, बीओएल के निर्गमन इत्यादि के लिए अपेक्षित है। प्राधिकारी ने भी पीवीआर तथा एसबीआर की पिछली एडीडी जांच में कोई विचार नहीं किया है।
- घरेलू उद्योग ने सामग्री रूकावट का कोई दावा नहीं किया है क्योंकि यह पहले से ही स्थापित है। प्राधिकारी द्वारा मात्र भौतिक क्षति का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

- iii. अनुबंध-1 के पैरा (2) के अनुसार, सविस्ती के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं, प्राधिकारी इस पर विचार करने के लिए अपेक्षित है। हालांकि, उत्पादन तथा खपत के संबंध में तथा आयात में निरपेक्ष रूप से गिरावट आई है।
- iv. न्यू न्यूमैटिक टायर्स एंड कॉस्टिंग्स की सीवीडी जांच में, जब एडी ड्यूटी लगाई थी, आयात में बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू उद्योग यह दावा नहीं कर सकता कि आयात में वृद्धि की आवश्यकताओं की अवहेलना होनी चाहिए क्योंकि एडीडी लागू किया गया था।
- v. घरेलू उद्योग पर आयातों के कारण कोई कीमत प्रभाव नहीं है। संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों से अधिक है। आयात की कीमतों की तुलना एडीडी को जोड़ने के बाद की जानी चाहिए। रूझानों की तुलना के आधार पर कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं है। आयात की कीमत में घरेलू उद्योग की विक्रियों की लागत में बढ़ोतरी के समान वृद्धि हुई है।
- vi. घरेलू विक्रियों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि में क्षति की अवधि में महत्वपूर्ण गिरावट हुई।
- vii. क्षमता में वृद्धि न होने पर भी, घरेलू उद्योग की व्याज तथा न्यूनीकरण लागत में बढ़ोतरी हुई।
- viii. याचिकाकर्ता आर एंड डी लागतों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने में असफल हो गए। हालांकि, 2018-19 की आरआईएल की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि संबद्ध वस्तुओं से संबंधित महत्वपूर्ण नवपरिवर्तन किए गए हैं।
- ix. याचिकाकर्ता ऑटोमोटिव उद्योग में हुई मंदी के कारण होने वाली क्षति का कारण बताने में असफल हो गए हैं जबकि आर आई एल की वार्षिक रिपोर्ट में इसे दर्ज किया गया है।
- x. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि कोरिया से उत्पाद के आयातों में घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण गिरावट हो रही है इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन की विक्री करने योग्य है। कोरिया से आयात में निरपेक्ष रूप से तथा उत्पादन के संबंध में गिरावट हुई है।
- xi. जांच की अवधि में आयात की कीमत में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है।
- xii. पीयूसी की विक्री की घरेलू लागत में आधार वर्ष (2015-16) की तुलना में पी ओ आई में मात्र 21 सूची बिन्दुओं से बढ़ोतरी हुई है जबकि उसी अवधि के दौरान पी यू सी की घरेलू विक्री कीमत में 41 सूची बिन्दुओं से बढ़ोतरी हुई है। इसमें कोई कीमत ह्रास नहीं है।
- xiii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद को अलग-अलग ग्रेड में करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चयनित मैनुअल दृष्टिकोण मिथ्याकरण के लिए उत्तरदायी है तथा प्राधिकारी द्वारा इसका पुनः निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।
- xiv. जांच की अवधि में कोई कीमत कटौती नहीं हुई है।
- xv. उत्पाद की वास्तविक घरेलू कीमतें, कीमत कटौती के विश्लेषण हेतु विचाराधीन कीमतों की अपेक्षा कम होंगी।
- xvi. प्राधिकारी निष्कर्ष देते हैं कि पूर्व पाटन-रोधी जांच में निर्यातों में पिछड़ने का कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं है।
- xvii. उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा घरेलू विक्री में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी हुई है।
- xviii. घरेलू उद्योग भी 0.15 मिलियन टन प्रति उत्पाद प्रति वर्ष के संबंध में अपनी स्थापित क्षमता का विस्तार करने की योजना बना रहा है। यदि किसी उत्पादक को हानि हो रही है, तो वह विस्तार के लिए नहीं जाता है।
- xix. क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान कुल विक्री मूल्य में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है, जिससे स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की कीमतें बढ़ गई हैं।
- xx. आर आई एल का प्रयोग सामान्य व्यवहार, बाजार में प्रवेश करने, प्रभुत्व हासिल करने तथा उसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा समाप्त करने हेतु अपहरक कीमत निर्धारण का उपयोग करने के लिए है।
- xxi. जब पीयूसी के डीआई के उत्पादन स्तर के संबंध में तुलना की गई, पी ओ आई के दौरान 2015-16 में मालसूची स्तर वास्तव में 12 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हो गया है।

- xxii. आधार वर्ष (2015-16) में मालसूची कारोबार अनुपात 19 गुना से बढ़कर पी ओ आई में 32 गुना हो गया।
- xxiii. संयंत्र की शुरूआत की तारीख से, घरेलू उद्योग मांग का महत्वपूर्ण हिस्सा रखने के योग्य हो गया है।
- xxiv. घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही हानियां, कच्चे माल की लागत, न्यूनीकरण तथा वित्त लागत भुगतान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।
- xxv. कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी भी, घरेलू उद्योग द्वारा स्थानांतरण के कीमत निर्धारण के लिए जिम्मेदार है।
- xxvi. घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि पेट्रोरासायनिक क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
- xxvii. घरेलू उद्योग साझा किया गया आर्थिक डाटा इसके द्वारा विनिर्मित पेट्रोरासायनिक उत्पादों से संबंधित है न कि अकेले एस बी आर से।
- xxviii. घरेलू उद्योग आंतरिक मामलों को झेल रहा है जैसे कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानियां, पूंजी निवेशों के न्यूनीकरण में बढ़ोतरी, उच्च ऋण शेष तथा पेट्रोरासायनिक क्षेत्र में घरेलू उद्योग द्वारा अधिक पूंजी निवेश के कारण बैलेंस शीट को कम करना, छिट-पुट घटनाएं जैसे गुजरात के बड़ोदरा में घरेलू उद्योग उत्पादन सुविधा में आग लगने जैसी घटनाओं से घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है।
- xxix. निर्यात बाजार में निरंतर हो रहे नुकसान ने इस बात के और प्रमाण दिए कि कोरिया आर पी से होने वाले आयातों के घरेलू परिचालन में घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान पर कोई प्रभाव नहीं है।
- xxx. एस बी आर की कीमतें ऑटो क्षेत्र उद्योग में हो रही मंदी से भी प्रभावित हैं।
- xxxi. कर्तव्यों का आरोपण लोक हित के विपरीत होगा।
- xxxii. घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई में स्वीकार किया है कि मात्रा तथा कीमत रूझानों में इसका प्रदर्शन वांछनीय है।
- xxxiii. आयात की कीमत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है जिससे स्पष्ट है कि कोई कीमत प्रभाव नहीं है। कोई कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं है।
- xxxiv. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कीमतें मार्च, 15 के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। सूचीकरण के साथ उन पर विचार करने से पता चलता है कि कोई कीमत कटौती नहीं है।
- xxxv. घरेलू उद्योग ने आंकड़ों का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया है। मैनुअल के अनुसार द्वितीयक स्रोत पर रिलायंस को नहीं रखा जा सकता है।
- xxxvi. प्राधिकारी द्वारा अन्य तथ्यों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा होने वाली क्षति के लिए गैर-जिम्मेदाराना विश्लेषण करना अपेक्षित है।
- xxxvii. याचिका में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का आईएसआरपीएल की वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए वित्तीय वक्तव्यों के साथ कोई संबंध नहीं है।
- xxxviii. घरेलू उद्योग 2016-17 के आंकड़ों पर जांच की अवधि में क्षति होने का दावा करने तथा यह तर्क देने के लिए कि पहले आरोपित किए गए पाटनरोधी कर्तव्य हानिकारक प्रभाव को संबोधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, भरोसा नहीं किया जा सकता।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 212. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विभिन्न निवेदनों पर विचार किया है और रिकार्ड तथा उपलब्ध तथ्यों पर लागू कानूनों पर विचार करते हुए इसका विश्लेषण किया है। यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों का उल्लेख करता है।
- 213. अनुबंध – II के साथ पठित सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 13 में व्यवस्था की गई है कि किसी क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति निर्दिष्ट कर सकते हैं, "..... दोनों की उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी (क) सब्सिडी प्राप्त आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर सब्सिडी प्राप्त आयातों का

प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। सस्मिडी प्राप्त आयातों की मात्रा के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ इस पर विचार करेंगे कि क्या सस्मिडी प्राप्त आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या तो कुल रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष रूप में। कीमतों पर सस्मिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी विचार करेंगे कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में सस्मिडी प्राप्त आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास करता है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हुआ होता। भारत में घरेलू उद्योग पर सस्मिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, माल सूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, सस्मिडी की मात्रा और मार्जिन आदि पर सस्मिडी रोधी नियमावली के अनुबंध – I के अनुसरण में विचार किया गया है।

214. जहां तक इस निवेदन का प्रश्न है कि घरेलू उद्योग कच्ची सामग्री के उच्च अंतरण मूल्य निर्धारण के कारण हानि उठा रहा है, यह स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की जांच की है। यह देखा गया है कि वर्तमान प्रयोजन के लिए विचार की गई खपत कीमत दो याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा अनुरक्षित वित्तीय रिकार्डों के अनुसार है।
215. जहां तक घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों के दावे का संबंध है कि घरेलू उद्योग निर्यात बिक्रियों में भी क्षति का सामना कर रहा है, यह नोट किया गया है कि यह घरेलू बाजार में बिक्रय करने की अक्षमता के कारण अलाभकारी कीमतों पर निर्यात कर रहा है जो आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही क्षति को प्रतिबिंबित करता है।
216. जहां तक इस निवेदन का संबंध है कि घरेलू उद्योग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी से प्रभावित है, यह नोट किया गया है कि पूरी क्षति अविधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ी है।
217. जहां तक इस दावे का संबंध है कि बाजार में प्रवेश करने, प्रभुत्व प्राप्त करने और परिणामस्वरूप प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए बेहद सस्ता कीमत निर्धारण वसूल करने की रिलायंस इंडस्ट्री की पुरानी प्रथा है, प्राधिकारी का विचार है कि शुल्कों को लागू करने से बाजार में प्रतियोगिता समाप्त नहीं होगी। इसके बजाय, यह बाजार में निष्पक्ष प्रतियोगिता को सुनिश्चित करेगा।
218. जहां तक इस दावे का संबंध है कि आई एस आर पी एल लाभ में है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के रूप में स्थापित दोनों आवेदकों के लिए क्षति विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।
219. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध पर घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों को ध्यान में रखा है तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा प्रयोज्य कानूनों पर विचार करते हुए विश्लेषण स्वतः ही घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का उल्लेख करता है।

छ.3.1 घरेलू उद्योग पर सस्मिडी प्राप्त आयातों का मात्रा प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

220. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में भारत में वर्तमान जांच उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को ध्यान में रखा है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	102,155	134,936	173,699	191,325
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	170	187
3	अन्य भारतीय उत्पादक	मी. टन	-	-	-	-
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-
5	संबद्ध आयात	मी. टन	83,358	61,549	50,843	45,914
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	61	55

7	कोरिया के अतिरिक्त ए डी डी आकर्षित करने वाले देशों से आयात	मी. टन	38,471	37,468	27,016	23,963
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	70	62
9	अन्य देशों से आयात	मी. टन	5,986	4,248	6,314	4,566
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	105	76
11	मांग / खपत	मी. टन	229,970	238,202	257,872	265,768
12	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	112	116

221. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान उत्पाद के लिए मांग लगातार बढ़ी है।

ख. कुल और सापेक्ष अवधि में आयात

222. सस्मिडी प्राप्त आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की आवश्यकता है कि क्या या तो कुल रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष सस्मिडी प्राप्त आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों का आश्रय लिया है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
1	कोरिया से आयात	मी. टन	83,358	61,549	50,843	45,914
2	अन्य आयात	मी. टन	44,457	41,716	33,330	28,529
3	कुल आयात	मी. टन	1,27,816	1,03,265	84,173	74,443
4	के संबंध में संबद्ध आयात					
क	कुल आयात	%	65	60	60	62
ख	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	93	95
ग	भारतीय उत्पादन	%	74	38	27	21
घ	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	52	37	28
ड	भारतीय मांग	%	36	26	20	17
च	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	54	48

223. यह देखा गया है कि:-

क. कोरिया से आयातों में क्षति अवधि में कुल रूप में गिरावट आई है।

ख. संबद्ध आयातों में भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष गिरावट आई है।

224. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों में गिरावट इस तथ्य के कारण है कि घरेलू उद्योग ने हाल ही में (आधार वर्ष उत्पादन का दूसरा साल था) उत्पादन आरंभ किया था और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश की थी जिसे 30 अगस्त, 2017 को लागू किया गया था। घरेलू उद्योग ने आगे स्पष्टीकरण दिया था कि उत्पादन प्रक्रिया ऐसी है कि उत्पादन को इष्टतम करने के लिए प्रयास किए जाने पड़ते हैं। चूंकि, घरेलू उद्योग अपने उत्पादन को लगातार बढ़ा रहा है, कोरिया और अन्य देशों से आयात लगातार गिर रहे हैं।

छ.3.2. घरेलू उद्योग पर सब्सिडी प्राप्त आयातों का कीमत प्रभाव:-

225. घरेलू उद्योग की कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं के प्रभाव के संबंध में, यह जांच किए जाने की जरूरत है कि क्या सब्सिडी प्राप्त आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा कीमतों में ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक बढ़ गई होती।

क. कीमत कटौती

226. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की विक्री कीमत की संबद्ध देश की संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। 1500 श्रृंखला और 1700 श्रृंखला के लिए अलग – अलग तुलना की गई है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
क			एस बी आर – कुल			
1	पहुंच मूल्य	रु./मी. टन	88,032	1,04,786	1,15,631	1,17,548
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	131	134
3	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***
5	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
6	कीमत कटौती	रेंज	(0-10)%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%
ख			एस बी आर - 1500			
1	विक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	133	141
3	पहुंच कीमत	रु./मी. टन	86,591	1,05,358	1,17,651	1,20,095
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	136	139
5	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***
7	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
8	कीमत कटौती	रेंज	(0-10)%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%
ग			एस बी आर - 1700			
1	विक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	137	144
3	पहुंच कीमत	रु./मी. टन	88,195	1,00,329	1,09,914	1,14,030
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	125	129
5	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***
7	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
8	कीमत कटौती	रेंज	(10-20)%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%

227. यह देखा गया है कि पी ओ आई और क्षति अवधि में कीमत कटौती नकारात्मक है।

ख. कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास

228. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने कीमतों में महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित हुई होती, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की निम्नानुसार तुलना की गई थी। यह देखा गया है कि वर्तमान प्रयोजनों के लिए विचारित विक्रियों की लागत वित्तीय रिकार्डों और चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसार की गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पी ओ आई
1	एस बी आर 1500					
क	विक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
ख	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	115	120
ग	विक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
घ	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	133	141
ङ	पहुंच कीमत	रु./मी. टन	86,591	105,358	117,651	120,095
च	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	136	139
2	एस बी आर 1700					
क	विक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
ख	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	113	127
ग	विक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
घ	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	137	144
ङ	पहुंच कीमत	रु./मी. टन	88,195	100,329	109,914	114,030
च	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	125	129
3	एस बी आर - कुल					
क	विक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
ख	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	114	121
ग	विक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
घ	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	134	141
ङ	पहुंच कीमत	रु./मी. टन	88,032	104,786	115,631	117,548
च	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	131	134

229. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि में विक्री कीमत में गिरावट नहीं आई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग ने कीमत ह्रास का सामना नहीं किया है।

230. तथापि, यह नोट किया गया है कि सब्सिडी प्राप्त आयात संपूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की विक्रियों की लागत की तुलना में निम्न बने रहे। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग लाभकारी कीमतें प्राप्त करने में अक्षम है और दोनों ग्रेडों में हानि का सामना कर रहा है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों ने कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है जो अन्यथा उत्पादन में वृद्धि के कारण घटित हुई होती।

कम कीमत पर बिक्री

231. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही कम कीमत पर बिक्री, यदि कोई हो, की भी जांच की है। यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से महत्वपूर्ण रूप से कम है जिसके परिणामस्वरूप कम कीमत पर बिक्री हुई –

विवरण	इकाई	
आयात मात्रा	मी. टन	45,914
क्षति - रहित कीमत (एन आई पी)	रु./मी. टन	***
पहुंच मूल्य	रु./मी. टन	117548
कम कीमत पर बिक्री / क्षति मार्जिन	रु./मी. टन	***
कम कीमत पर बिक्री / क्षति मार्जिन	%	***
कम कीमत पर बिक्री / क्षति मार्जिन	रेंज	0-10%

झ.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

232. पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध – I में यह आवश्यकता है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्य परक जांच शामिल हो। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में आगे यह व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले आंकड़ों, जिनमें विक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेशों पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकद प्रभाव पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल है, की उद्देश्य परक और निष्पक्ष जांच शामिल होगी। प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उनके निवेदनों में किए गए तर्कों के ध्यान में रखा है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

233. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, घरेलू विक्रियों और निर्यात के संबंध में क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	क्षमता	मी. टन	2,61,000	2,61,000	2,61,000	2,61,000
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
3	उत्पादन	मी. टन	1,13,317	1,61,581	1,88,344	2,23,343
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	166	197
5	क्षमता उपयोग	%	43%	62%	72%	86%
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	166	197

7	घरेलू विक्रियां	मी. टन	1,02,155	1,34,936	1,73,699	1,91,325
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	170	187

234. यह देखा गया है कि:-

- क. घरेलू उद्योग के संघटकों में से एक ने क्षति अवधि के आरंभ में अपनी उत्पादन क्षमता घोषित की है।
- ख. घरेलू उद्योग के पास भारत में संबद्ध वस्तु की मांग के महत्वपूर्ण भाग को पूरा करने की क्षमता है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि यदि झूठी फ्री आयातों के जरिए पूरी की जा रही मांग को हटा दिया जाता है तो यह देश में उत्पाद की पूरी मांग को पूरा कर सकता है।
- ग. घरेलू उद्योग के उत्पादन, विक्रियों और क्षमता उपयोग ने अवधि में सुधार दर्शाया है। यह इस तथ्य के कारण है कि याचिकाकर्ता आरंभिक वर्षों में उभरती हुई स्थिति में थे। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा सृजित क्षमताओं और उत्पादन संबंधी दवावों के कारण, घरेलू उद्योग के पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं था कि वे अपनी कीमतों को आयातों के साथ बेंचमार्क करे और बाजार में उत्पादन की बिक्री करे।

ख. बाजार हिस्सा

235. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पी ओ आई
1	संबद्ध देश	%	36%	26%	20%	17%
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	54	48
3	कोरिया के अतिरिक्त ए डी डी आकर्षित करने वाले देशों से आयात	%	17%	16%	10%	9%
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	63	54
5	अन्य देश	%	3%	2%	2%	2%
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	94	66
7	घरेलू उद्योग	%	44%	57%	67%	72%
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	152	162
9	कुल योग	%	100%	100%	100%	100%

236. यह देखा गया है कि उत्पादन, विक्रियों और ए डी डी के अधिरोपण में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। मांग में संबद्ध आयातों का हिस्सा घटा है। तथापि, विभिन्न देशों के हिस्सों पर विचार करते हुए, कोरिया का हिस्सा महत्वपूर्ण है।

ग. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

237. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पी ओ आई
1	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	134	141

3	विक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	114	121
5	लाभ/(हानि)	रु./मी. टन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(21)	(27)	(31)
7	लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(28)	(46)	(59)
9	नकद लाभ	रु./मी. टन	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	16	13	(1)
11	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	21	23	(2)
13	पी वी आई टी	रु./मी. टन	***	***	***	***
14	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	2	(13)	(7)
15	पी वी आई टी	लाख रु.	***	***	***	***
16	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	3	(22)	(14)
17	आर ओ सी ई	%	***	***	***	***
18	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	3	(23)	(14)

238. यह देखा गया है कि -

- क. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग वित्तीय हानियों का सामना कर रहा है।
- ख. वर्ष 2016-17 में घरेलू उद्योग की प्रति इकाई हानि में कमी आई किंतु अगले वर्ष और पी ओ आई में इसमें वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग की हानियों में पिछले वर्ष की हानियों की तुलना में जांच की अवधि में 26% की वृद्धि हुई।
- घ. घरेलू उद्योग ने आरंभ में नकद हानियों का सामना किया। इसने 2016-17 से नकद लाभ अर्जित करना आरंभ किया। पी ओ आई में घरेलू उद्योग ने एक बार फिर नकद हानियों का सामना किया।
- ङ. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना किया। उसके पश्चात आर ओ आई में इसमें सुधार हुआ और घरेलू उद्योग ने 2016-17 में सकारात्मक आर ओ आई अर्जित किया। हालांकि, 2017-18 और पी ओ आई में नकारात्मक आर ओ आई का सामना भी किया।
- च. इस तर्क के बारे में कि, घरेलू उद्योग को क्षति उच्च व्याज और मूल्य ह्रास लागत के कारण है, यह देखा गया है और नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने नकद हानि और साथ ही व्याज पूर्व हानि दर्ज की है। इसलिए, पी ओ आई में लाभों में गिरावट व्याज में वृद्धि और मूल्य ह्रास लागत के कारण नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि आवेदकों में से एक ने क्षति अवधि के आरंभ में व्यावसायिक उत्पादन आरंभ किया था जिस कारण मूल्य ह्रास लागतों में वृद्धि हुई।

घ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

239. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी नीचे दी गई सारणी के अनुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पी ओ आई
1	कर्मचारियों की संख्या	सं.	320	329	339	338
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	106	106
3	दैनिक उत्पादकता	मी. टन/दिन	324	462	538	638
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	166	197
5	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/संख्या	354	491	556	661
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	157	187
7	वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	112	124
9	वेतन और मजदूरी	रु./मी. टन	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	67	63

240. यह देखा गया है कि:

- क. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है।
- ख. क्षति अवधि में प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- ग. क्षति अवधि में वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि हुई है किंतु क्योंकि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है, इस कारण प्रति यूनिट लागत में गिरावट आई है। अतः, मजदूरी घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं कर सकती।

ड. माल सूची

241. घरेलू उद्योग के पास क्षति अवधि में माल सूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पी ओ आई
1	आरंभिक स्टॉक	मी. टन	18,869	7,632	16,587	9,808
2	अंतिम स्टॉक	मी. टन	7,632	16,587	9,808	16,871
3	औसत माल सूची	मी. टन	13,251	12,110	13,198	13,340
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	100	101

242. यह देखा गया है कि 2016-17 में घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूचियों में गिरावट आई है किंतु जांच अवधि के अंत के प्रति इसमें वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने माल सूचियों के एकत्र होने से रोकने के लिए घाटे में महत्वपूर्ण निर्यात किया है। इस के बावजूद, पी ओ आई में अंतिम मालसूचियों में एक बार फिर वृद्धि हुई है। इसके अलावा, यदि घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त निर्यातों को अपनाया नहीं होता तो घरेलू उद्योग की मालसूचियां उच्च हुई होती।

च. वृद्धि

243. मात्रा और लाभ मापदंडों की प्रवृत्ति नीचे दी गई सारणी के अनुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19
1	उत्पादन	वाई/वाई	43%	17%	19%
2	घरेलू बिक्रियां	वाई/वाई	32%	29%	10%
3	बाजार हिस्सा	वाई/वाई	28%	19%	7%
4	लाभ/हानि	वाई/वाई	72%	-68%	-26%
5	नकद लाभ	वाई/वाई	121%	8%	-110%
6	पी बी आई टी	वाई/वाई	103%	-831%	39%
7	आर ओ सी ई	वाई/वाई	103%	-848%	41%

244. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में उत्पादन, बिक्रियों और बाजार हिस्से की शर्तों में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक थी। हालांकि, लाभों, नकद लाभों और आर ओ आई में वृद्धि 2016-17 में मुख्य रूप से सकारात्मक थी, किंतु पी ओ आई में यह नकारात्मक हो गई। उत्पाद और मात्रा के संबंध में बाजार में स्वयं को पूरी तरह से स्थापित करने के पश्चात भी घरेलू उद्योग द्वारा वित्तीय हानियों और नकारात्मक आर ओ आई का सामना करना पड़ा।

ख. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

245. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने वित्तीय हानियों का सामना किया है। सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रतिस्पर्धा के साथ, उत्पाद के प्रचालनों ने पूंजी निवेश जुटाने की उत्पाद की क्षमता को संघटित रूप से प्रभावित किया है।

ज. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन

246. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन को निम्नानुसार मूल्यांकित किया गया है:-

उत्पादक/निर्यातक	एन आई पी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	अमरीकी डॉलर/मी. टन	अमरीकी डॉलर/मी. टन	अमरीकी डॉलर/मी. टन	%	रेंज
एल जी केमी. लि.	***	***	***	***	0-10
कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लि.	***	***	***	***	0-10
अन्य	***	***	***	***	30-40

झ. क्षति पर निष्कर्ष

247. रिकॉर्ड के बारे में जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की चोट के आधार पर निष्कर्ष निकालता है -

- क. कुल रूप में और भारत में उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में, इस अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में गिरावट आई है।
- ख. उद्योग ने हाल ही में व्यावसायिक उत्पादन आरंभ किया था (फरवरी, 2014 में आई एस आर पी एल और अक्टूबर, 2016 में आर आई एल)। चूंकि, घरेलू उद्योग ने उत्पादन (और परिणामस्वरूप घरेलू बिक्रियों) बढ़ाया था, संबद्ध आयातों में गिरावट आई थी। तथापि, आयातों की मात्रा बाजार में उत्पाद में उत्पाद की कीमतों और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है।

- ग. कोरियाई आयात भारत में आयातों के सबसे बड़े हिस्से पर आधिपत्य रखते हैं।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा अनुसरण की जा रही पद्धति के आधार पर कीमत कटौती नकारात्मक है।
- ङ. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से कम है।
- च. संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास किया है। घरेलू उद्योग लागतों में वृद्धि के समानुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है।
- छ. घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि में वित्तीय हानियों का सामना किया है। घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही वित्तीय हानियों में 2016-17 में गिरावट आई और उसके बाद पी ओ आई तक इसमें उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई।
- ज. 2016-17 में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ और उसके पश्चात नकद लाभ और आर ओ आई के संबंध में पी ओ आई तक इसमें ह्रास हुआ।
- झ. जहां याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग मात्रा संबंधी मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम है, कीमत मापदंडों के संबंध में यह वृद्धि नकारात्मक थी।
- ञ. घरेलू उद्योग के पास मालसूची क्षति अवधि में अस्थिर बनी रही और पी ओ आई के अंत में इसमें एक बार फिर वृद्धि हुई।

छ. कारणात्मक संबंध

248. प्राधिकारी ने निम्नानुसार जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारक भी घरेलू उद्योग को क्षति का कारण बन सकते हैं:-

क. तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

- ख. अन्य प्रमुख देशों से आयात पहले ही पाटन रोधी शुल्कों के अध्यधीन हैं। मौजूदा सीमा शुल्क और पाटन रोधी शुल्क को जोड़े जाने के पश्चात भी कोरिया की पहुंच कीमत बाकी विश्व के आयातों की तुलना में सबसे कम है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

249. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए है। अतः, खपत के पैटर्न ने घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां

250. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती है।

ङ. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

251. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, इसलिए, क्षति का एक संभव कारक नहीं है।

च. निर्यात निष्पादन

252. प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में कोई संभव ह्रास घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

253. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण नहीं है।

ज. कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

254. कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:-

- क. संबद्ध देशों से सब्सिडी प्राप्त आयात उल्लेखनीय मात्रा में भारत में प्रवेश कर रहे हैं।

- ख. सापेक्ष और कुल शर्तों, दोनों रूपों में, आयातों में कमी हुई है। तथापि, प्रतिकूल आयातों ने बाजार में महत्वपूर्ण हिस्से पर आधिपत्य किया है जिस कारण प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ता है।
- ग. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य न केवल एन आई पी से निम्न है बल्कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विक्रियों की लागत से भी कम है।
- घ. विभिन्न देशों से आयातों की पहुंच कीमत दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की विक्री कीमत कोरियाई आयातों की पहुंच कीमत से प्रभावित है।
- ङ. घरेलू उद्योग के निष्पादन में एक बार फिर लाभों, नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय में ह्रास हुआ।

प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियां

घरेलू उद्योग द्वारा टिप्पणियां

255. प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रकटीकरण विवरण पर घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं :-

- क. निम्नलिखित सूचना के प्रकटीकरण के लिए अनुरोध करते हुए, घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण पर टिप्पणियां दायर नहीं की हैं :-
- फार्मेंट वी, फार्मेंट डी नियामक
 - नियोजित पूंजी की संगणना
 - स्वीकृत और अस्वीकृत व्ययों का विवरण
 - लिंक की गई फाइलें नहीं दी गई हैं और दिया गया एन आई पी किया गया पेस्ट विशेष है। ऐसी सूचना और प्रकटीकरण के साथ, घरेलू उद्योग द्वारा यह समझना संभव नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं में से प्राधिकारी द्वारा क्या स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया है।
- ख. एन आई पी के प्रकटीकरण के लिए घरेलू उद्योग की प्रकटीकरण संबंधी पूर्ण फाइलों की जरूरत है।
- ग. पी वी आर के आयातों और एस वी आर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच और सभी पी टी ए मामलों में प्राधिकारी द्वारा आर आई एल की बुटाडीन खपत कीमत को स्वीकार किया गया था।
- घ. एक मामले में खपत कीमत को अनुमति देना और अन्य मामले में अस्वीकृत कर देना एक परस्पर विरोधी और भेदभाव पूर्ण विचारधारा है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टिप्पणियां

256. प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटीकरण विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:-

विचाराधीन उत्पाद

257. सोल्यूशन एस वी आर वर्तमान जांच के क्षेत्र से परे है।

विविध

258. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जांच शुरूआत की तारीख को जांच की अवधि 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।

सब्सिडी कार्यक्रम

सामान्य

259. संगत न्यायशास्त्र के साथ संबंधित प्रतिकारी शुल्क ('सी वी डी') जांचों के संबंध में वर्तमान कानून और विनियम में उपयुक्त रूप से यह व्यवस्था की गई है कि एक डी एस में उन अनिवार्य तथ्यों पर डीजीटीआर के निष्कर्ष शामिल होने चाहिए जो इस निर्णय के आधार का निर्माण करेंगे कि निश्चयात्मक उपायों को लागू किया जाना है अथवा नहीं (देखें भारतीय सी वी डी नियमावली का निमय 18)। तथापि, प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन निर्धारण में अपना निर्णय दिया है।

कार्यक्रम 1

260. सिर्फ इसलिए कि निगमित पुर्नसंरचना में शामिल बैंक सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त है, ये बैंक 'सार्वजनिक निकाय' नहीं हो सकते। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि बैंक कोरिया सरकार के प्रभावी नियंत्रण, नियमन और पर्यवेक्षण के अधीन है।
261. सरकार के स्वामित्व वाले बैंक भी उसी तरीके से काम करते हैं जैसे निजी वाणिज्यिक बैंक सहभागिता की शर्तें व्यापारिक आधार पर बाजार दबावों द्वारा निर्धारित की जाती हैं और इन्हें 100 प्रतिशत क्रेडिटर्स की सहमति की जरूरत है। इसलिए, निर्णय विशुद्ध रूप से व्यावसायिक था।
262. प्राधिकारी ने यह दर्शाने के लिए जांच का समर्थन नहीं किया है कि इन बैंकों ने सरकारी निर्देशों के आधार पर निगमित पुर्नसंरचना प्रक्रिया में सहभागिता की है। के डी वी ने केवल एक सामान्य क्रेडिटर के रूप में भाग लिया है।
263. प्रत्येक क्रेडिटर बैंक के लिए कुम्हो के वर्तमान बांड अनुपात के समानुपात में यू एस ए एनसीई ऋण/क्रेडिट सीमा में वृद्धि हुई थी। के डी वी की यू एस ए एनसीई की वास्तविक व्यावसायिक व्याज दर अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक थी। इसमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ है।
264. अल्पावधि ऋणों को अतिरिक्त रूप से जारी करना सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुसरित एक सामान्य अभ्यास है और न कि एक सार्वजनिक निकाय द्वारा लिया गया खास उपाय नहीं है। इसके अलावा, प्रयुक्त व्याज दर, जिस पर दूसरे क्रेडिटर का करार निष्पादन किया गया था, सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए है।
265. कन्वर्टीबल बांड (परिवर्तनीय) का क्रय अनिवार्य नहीं था बल्कि क्रेडिटर्स के लिए वैकल्पिक था तथा आई वी के तथा के ई एक्स आई एम ने किसी परिवर्तनीय बांड का क्रय नहीं किया। परिवर्तनीय बांडों को क्रय करने की पात्रता या तो अन्य लेनदारों अथवा पूर्व निर्धारित के पक्ष में त्याग दी गई।
266. परिवर्तनीय बांडों की खरीद पुर्नसंरचना प्रक्रिया के भाग के रूप में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किया गया आमतौर पर समर्थित व्यावसायिक निर्णय है।
267. वित्तीय समर्थन केवल दिवालियापन से उबरने के लिए अनिवार्यता के रूप में उपलब्ध कराया गया। बैंक का निर्णय स्वतंत्र परामर्शी मै० प्राइसवाटर हाउस कूपर द्वारा जारी उचित अध्यवसायी रिपोर्ट द्वारा समर्थित विशुद्ध रूप से एक व्यावसायिक निर्णय था।
268. कुम्हो में जांच अवधि से बहुत पहले ही पुर्नसंरचना की गई थी और पुर्नसंरचना प्रक्रिया से उत्पन्न सभी वापसी अदायगी बाध्यताओं का भी जांच की अवधि से पहले ही निराकरण कर दिया गया था। इसलिए, प्रतिवादी को प्राप्त किसी लाभ का वर्तमान जांच में विरोध नहीं किया जा सकता।
269. सी आर पी ए, 2016 को अधिनियमित भी नहीं किया गया था जब कुम्हो ने निगमित पुर्नसंरचना आरंभ और पूरी की थी। इसलिए, प्राधिकारी का मत कि कार्यक्रम को निगमित प्रोन्नति अधिनियम, 2016 के द्वारा अभिशसित किया गया था, गलत विवरण है।
270. प्राधिकारी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि पेश की गई वित्तपोषण की शर्तें गैर- व्यावसायिक आधार पर आधारित थीं। इसके लेनदारों द्वारा कुम्हो को उपलब्ध कराई गई वित्तपोषण की शर्तें इंगित करती हैं कि निगमित पुर्नसंरचना व्यापारिक रूप से उचित आधार पर की गई थी।
271. कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फैले हुए उद्यम शामिल हैं और यह किसी विशेष उद्यम या क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं।

कार्यक्रम 3

272. औद्योगिक प्रौद्योगिकी नवीनकरण प्रोन्नति अधिनियम ('आईटीआईपीए') के अंतर्गत वित्तपोषण कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, संस्थान, संगठन, उद्यम आदि शामिल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इस प्रकार, एक विशेष उपक्रम या क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

कार्यक्रम 4

273. कार्यक्रम 4 के अंतर्गत, कर लाभ और दीर्घावधिक ऋण कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं और उन सभी कंपनियों और वैयक्तिकों को उपलब्ध हैं जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। इसमें कोई विशिष्टता नहीं है।

कार्यक्रम 5

274. कार्यक्रम 5 में बड़ी संख्या में वे उद्यम शामिल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इस प्रकार यह किसी विशिष्ट उद्यम या क्षेत्रों तक सीमित नहीं है।

कार्यक्रम 6

275. कार्यक्रम 6 स्वरूप में निर्यात सब्सिडी है और प्राधिकारी ने इसका प्रतिकार किया है। यह उनके मत के बिल्कुल विपरीत है कि पाटन या निर्यात सब्सिडीकरण की समान स्थिति की प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रतिकारी शुल्क और पाटनरोधी शुल्क दोनों के अधीन कोई अनुच्छेद नहीं होगा।

कार्यक्रम 7

276. कार्यक्रम 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.8 और 7.3 सभी उद्यमों के लिए क्षेत्र, सेक्टर अथवा उद्योग के बावजूद उपलब्ध है और इस प्रकार प्रतिकार योग्य नहीं है।
277. कार्यक्रम संख्या 7.1.2 संसाधन विकास क्षेत्र में सामान्य निवेश पद्धति के अनुरूप एक निवेश निर्णय है। यदि कारोबार सफल रहता है तो लाभ का एक भाग (ऋण पर आधारित) जी ओ के को वापस लौटाया जाना चाहिए।
278. भारत सरकार उन कार्यक्रमों को अनुरक्षित करती है जो 50 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्य स्थानों के लिए एक शिशु सदन (क्रेश) की स्थापना को अनिवार्य बनाते हैं और अंशदान उपलब्ध करती है। यदि प्राधिकारी कार्यक्रम संख्या 7.1.3 को प्रतिकार योग्य पाते हैं, तो विदेशों में अन्य व्यापार उपचार मंचों के समक्ष चलाई जा रही समान योजनाओं को भी इनके बराबर रखा जा सकता है।
279. एल जी केम० और कुम्हो के लिए कार्यक्रम सं. 7.1.4 के तहत दिए गए अनुदान को प्रतिकार योग्य नहीं पाया गया है क्योंकि यह शिशु देखभाल सदन के लिए अनुरक्षित खातों में सीधे ही हस्तांतरित किया गया था। कानून के तहत क्रियाविधि अनिवार्य है और उसके अंतर्गत सभी लाभ भोगियों पर लागू होता है। इसलिए, कार्यक्रम का पोस्को या जी ओ के से किसी अन्य निर्यातकों/उत्पादकों के विरुद्ध प्रतिकार नहीं किया जाना चाहिए।
280. कार्यक्रम सं. 7.1.5 के तहत कोई लाभ नहीं विद्यमान है, क्योंकि यह केवल विदेशी क्षेत्राधिकार में अर्जित आय पर अदा किए गए निगमित कर पर दोहरे कराधान की घटना से कोरियन निगमित करदाता को राहत प्रदान करता है।
281. प्राधिकारी ने केवल समग्र रूप से कार्यक्रम 7.1.5 में सब्सिडी मार्जिन की संगणना की है, तथापि सब्सिडी मार्जिन भारत को पोस्को द्वारा उत्पाद के निर्यातों के कारण है। पोस्को के लिए परिणामस्वरूप सब्सिडी मार्जिन नगण्य होना चाहिए।
282. कार्यक्रम सं. 7.1.7 के तहत ऋणों को सामान्य प्रचालनों को आयोजित करने के लिए उपलब्ध कराया गया है और ये संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित नहीं हैं।
283. प्राधिकारी ने पोस्को के लिए कार्यक्रम सं. 7.1.7 के अंतर्गत सब्सिडी मार्जिन की संगणना में त्रुटि की है।
284. कार्यक्रम सं. 7.5 सरकार द्वारा अपनाए गए समाज कल्याण उपाय है और इसकी कारोबार संबंधी गतिविधियों के संबंध में व्यापार, उद्योग या हस्ती को कोई लाभ प्रोद्भूत नहीं होता।
285. संपूर्ण निर्धारित सब्सिडी मार्जिन को जांच की अवधि के दौरान केकेपीसी द्वारा उत्पादित और भारत को निर्यातित संपूर्ण निर्यात मात्रा के कारण नहीं माना जा सकता। दोनों चैनलों के लिए सब्सिडी मार्जिन को पृथक-पृथक निर्धारित किए जाने और

प्रत्येक चैनल के जरिए निर्यात मात्राओं में आवंटित किए जाने की आवश्यकता है और भारांशित औसत सव्सिडी मार्जिन प्राधिकारी द्वारा केकेपीसी को प्रदान किया जाना चाहिए।

286. प्रकटीकरण विवरण इस पर मौन है कि कैसे घरेलू उद्योग ने भारतीय सी वी डी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) (ख) में प्रतिबिंबित ए एस सी एम के अनुच्छेद 11.2 के तहत न्यूनतम प्रमाणिक मानकों को पूरा किया है।
287. प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं में प्रासंगिकता और पर्याप्त साक्ष्य का अभाव है और इनका प्रतिवाद नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम प्रतिकार योग्य सव्सिडियों को स्थापित करने के लिए संगत कानूनों के अंतर्गत अनिवार्यताओं को पूरा करने में असफल है। कोई भी कार्यक्रम/योजनाएं विशिष्टता के उक्त मानकों को पूरा नहीं करता।
288. प्रकटीकरण विवरण का उत्तर देने वाले हितवद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर विचार करना एक बाध्यता है। वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने जरूरी अनिवार्यता को छोड़ दिया है और विचार किए गए तथ्यों पर उत्तर देने वालों को अवसर दिए बिना प्रतिधारणा पर ही निष्कर्ष निकाला है।
289. डीजीटीआर ने स्वीकार किया है कि पी यू सी उपचारों से वर्तमान ए डी डी निर्यात सव्सिडियों के कारण उत्पन्न निर्यात कीमत में विरूपण उत्पन्न हुआ है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

290. इस निष्कर्ष में कोई तथ्य नहीं है कि कोरिया गणराज्य से पी यू सी के आयात महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
291. पूर्ववर्ती वर्षों में प्रारंभिक स्तर पर होने के कारण आवेदक घरेलू उद्योग के प्रचालन संबंधी निष्पादनों की जांच के लिए अप्रासंगिक हैं।
292. प्रकटीकरण विवरण में लाभप्रदता के अतिरिक्त सभी क्षति संबंधी संकेतक स्वयं में स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। जैसाकि ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) बनाम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टेट द्वारा निर्णय दिया गया है सिर्फ लाभप्रदता पर हुआ बुरा प्रभाव महत्वपूर्ण क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त है।
293. बड़े हुए हस्तांतरण कीमत निर्धारण के अभाव को निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी द्वारा की गई जांच अपर्याप्त है। एन आई पी के परिकलन में प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई कच्ची सामग्रियों की कीमतों की तुलना बाजार में प्रचालित कच्ची सामग्रियों की कीमतों से करनी चाहिए।
294. निर्यात विक्रियों के कारण क्षति घरेलू उद्योग उपचार जांच में निर्धारण के अधीन नहीं है। व्यापार नियामक प्रभावों की जांच का क्षेत्र घरेलू उद्योग बाजार में सीमित है।
295. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, से स्टेट और ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में निर्णय दिया गया है कि सभी क्षेत्रों में 22 प्रतिशत के प्रतिफल को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता और यह परिवर्तन के अधीन है। सिंथेटिक रबड़ विनिर्माण उद्योग में 22 प्रतिशत की प्रतिफल साधारण है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

296. क्षतिरहित कीमत के परिकलन और उसके प्रकटीकरण पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन पर क्षतिरहित कीमत को नियमावली के अनुबंध-III के अनुसरण में और प्राधिकारी के निरंतर अभ्यास के अनुसार निर्धारित किया गया है।
297. यह दावा किया गया है कि निर्धारण में पर्याप्त साक्ष्य की कमी है। यह नोट किया गया है कि आवेदक ने जांच शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए सव्सिडी के पर्याप्त और यथेष्ट साक्ष्य उपलब्ध कराए थे। प्राधिकारी ने परामर्श के लिए कोरिया की सरकार को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए थे। किंतु, कोरिया की सरकार ने इसका उत्तर नहीं दिया। इसलिए प्रत्यर्थी के दावे अविवादित ही रह गए। प्राधिकारी ने न्यूनतम साक्ष्यात्मक मानकों के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात ही जांच की शुरुआत की थी। प्रतिभागी उत्पादकों और कोरिया सरकार द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तर भी सव्सिडी की विद्यमानता को दर्शाते हैं। प्रकटीकरण विवरण और वर्तमान जांच परिणामों में कार्यक्रम की विशिष्टता और प्रतिपूर्ति को पहले ही प्रकट किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि प्रकटीकरण विवरण को जारी किए जाने के पश्चात सव्सिडी मार्जिन सहित, प्रकटीकरण विवरण में प्रस्तावित सव्सिडी मार्जिन के निर्धारण की पद्धतियों की गोपनीय प्रति संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों, दोनों को प्रकट की गई और इस जांच परिणाम में उनसे प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है।

298. प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकारी द्वारा “निर्धारित” शब्द के प्रयोग से संबंधित तर्क के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पद “निर्धारण” के प्रयोग का अर्थ यह नहीं है कि यह अंतिम निर्धारण है। जब नियम 16 के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, तब प्राधिकारी केवल अनिवार्य तथ्यों को प्रकट करते हैं और निर्धारण का प्रस्ताव करते हैं और प्रकटीकरण टिप्पणियों के सभी पहलुओं पर सभी हितवद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं। इसलिए, “निर्धारण” अपने सही अर्थ में केवल तभी अंतिम होगा जब अंतिम जांच परिणाम जारी किए जाएंगे और न कि प्रकटीकरण विवरण के स्तर पर।
299. जहां तक इस निवेदन का संबंध है कि बैंक सार्वजनिक निकाय नहीं हैं, यह नोट किया गया है बैंक ऐसी एजेंसी के निर्देश अथवा अधीक्षण पर कार्य कर रहे हैं जो सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त अथवा नियंत्रित हैं। जहां तक निगमित पुनर्संरचना कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त न कर रहे केकेपीसी से संबंधित तर्क का संबंध है, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराग्राफों में विस्तार से केकेपीसी द्वारा प्राप्त किए गए लाभ की संगणना उपलब्ध कराई है।
300. जहां तक निगमित पुनर्संरचना की विशिष्टता का संबंध है, यह स्वीकार किया गया है कि कार्यक्रम का एकमात्र प्रयोजन दिवालियेपन से उचित रूप से सुधार करने के लिए वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराना है। लाभ प्रत्येक के लिए उपलब्ध नहीं था, किंतु केवल कुछ विशिष्ट हस्तियों तक सीमित था, इस प्रकार कार्यक्रम को स्वरूप में विशिष्ट बनाता है।
301. जहां तक निगमित पुनर्संरचना कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त न कर रहे केकेपीसी से संबंधित तर्क का संबंध है, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के प्रासंगिक पैराग्राफों में विस्तार से केकेपीसी द्वारा प्राप्त किए गए लाभ की संगणना उपलब्ध कराई है।
302. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि दोनों निर्यात चैनलों के लिए सब्सिडी मार्जिन को पृथक् रूप से निर्धारित और प्रत्येक चैनल के जरिए निर्यात मानकों में आवंटित किए जाने की जरूरत है और प्राधिकारी द्वारा केकेपीसी को भारांशित औसत सब्सिडी मार्जिन प्रदान की जानी चाहिए, यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने प्रत्येक चैनल के जरिए सब्सिडी मार्जिन को आवंटित करने के पश्चात भारांशित औसत सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया है।
303. जहां तक इस दावे का संबंध है कि प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखी गई सब्सिडियों में से कुछ निर्यात सब्सिडी हैं और इसलिए उनका विरोध नहीं किया जा सकता, यह नोट किया गया है कि सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखी गयी सारी सब्सिडियां केवल उत्पादन सब्सिडी हैं और प्राधिकारी द्वारा किन्हीं निर्यात सब्सिडियों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
304. यह नोट किया गया है कि कार्यक्रम सं. 7.1.5 निगमित कर छूट कार्यक्रम, के तहत कोई भी पात्र उद्यम इसके द्वारा उपगत विभिन्न निवेश व्ययों पर कर क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। इस कार्यक्रम से संबंधित यह सूचना कोरिया गणराज्य की सरकार और पोस्को द्वारा दायर उत्तर से ली गई है। पोस्को द्वारा दायर उत्तर दर्शाता है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा लाभ प्राप्त किया गया है।
305. वर्तमान जांच कोरियाई उत्पादकों द्वारा प्राप्त किसी निर्यात सब्सिडी को नहीं दर्शाती है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सी वी डी मार्जिन संभव निर्यात सब्सिडीज के कारण किसी प्रकार के मार्जिन को अंतर्निहित नहीं करती। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी को नोट किया है। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि विद्यमान पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन के स्तर पर है। पाटनरोधी जांच में निर्धारित क्षति मार्जिन निर्धारित पाटन मार्जिन और लागू पाटनरोधी शुल्क की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्च था। चूंकि, निर्धारित क्षति मार्जिन उच्च था, आयातों से घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही क्षति की सीमा तक घरेलू उद्योग का संरक्षण नहीं किया गया था क्योंकि कानून केवल पाटन की सीमा तक ही पाटनरोधी शुल्क के लागू करने को प्रतिबंधित करता है। ऐसी स्थितियों में, घरेलू उद्योग सब्सिडीज के मार्जिन की सीमा तक सुरक्षा के लिए हकदार है, यदि यह पाया जाता है कि विदेशी उत्पादक प्रतिकारी सब्सिडीज प्राप्त कर रहे हैं। तथापि, जहां अधिनियम के तहत और नियमों की रोक को ध्यान में रखते हुए सी वी डी क्षति मार्जिन से ज्यादा नहीं हो सकती। यह भी वांछनीय समझा गया है कि पाटनरोधी शुल्क और सी वी डी का जोड़ अब स्थापित की गई क्षति मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता।
306. नीचे दी गई सारणी वर्तमान जांच में आकलित सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन और पिछली जांच में निर्धारित पाटन और क्षति मार्जिन को दर्शाती है। यह देखा गया है कि सी वी डी मार्जिन और पाटन मार्जिन वर्तमान सी वी डी जांचों में अब आकलित क्षति मार्जिन या कोरिया जनवादी गणराज्य से समान उत्पाद पर पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांचों के समय निर्धारित क्षति मार्जिन से कम है।

विवरण	पाटन मार्जिन (डीएम) (अमरीकी डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन (एसएम) (अमरीकी डॉलर/मी. टन)	सब्सिडी मार्जिन %	डीएम एवं एसएम मार्जिन (अमरीकी डॉलर/मी. टन)	डीएम% + एसएम%	एडी जांच में क्षति मार्जिन (अमरीकी डॉलर/मी. टन)	एडी जांच में क्षति मार्जिन %	सीवीडी जांच में क्षति मार्जिन (अमरीकी डॉलर/मी. टन)	सीवीडी जांच में क्षति मार्जिन %
कुम्हो	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
एलजी केम	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
अन्य	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

307. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि वर्तमान मामले में सी वी डी लागू करना उचित है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की विद्यमानता और सी वी डी लागू किये जाने के कारण दोहरा उपचार लागू नहीं होगा। लागू किया गया पाटनरोधी शुल्क और लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित सी वी डी भिन्न स्थितियों का समाधान करने के लिए अभिप्रेरित है। संरक्षण की कुल मात्रा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन से अधिक नहीं है।

क. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

308. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिकारी शुल्क को लागू करने का प्रयोजन, आमतौर पर, सब्सिडी प्रदान करने की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्रतिकारी शुल्क को लागू किया जाना किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए, देश में उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। यह माना गया है कि प्रतिकारी शुल्क को लागू करने से संबद्ध वस्तुओं की लागत प्रभावित हो सकती है। तथापि, प्रतिकारी उपायों को लागू किए जाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेषकर यदि, प्रतिकारी शुल्क की लेवी सब्सिडी प्राप्त संबद्ध वस्तुओं के आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को उत्पन्न क्षति का प्रतिकार करने के लिए जरूरी राशि तक प्रतिबंधित है। इसके विपरीत प्रतिकारी उपायों को लागू किया जाना सब्सिडी के द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभों को समाप्त करेगा और एक समान स्थिति का सृजन करेगा।

ख. निष्कर्ष और सिफारिशें

309. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

क. संबद्ध देश से भारत को निर्यात किया गया विचाराधीन उत्पाद सब्सिडी प्राप्त है।

ख. घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण क्षति का सामना किया है।

ग. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण उल्लेखनीय क्षति हुई है।

310. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितवद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था व घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों को सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित किए गए उपबंधों की शर्तों में सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की शुरुआत तथा उसे आयोजित करते हुए, प्राधिकारी का विचार है कि सब्सिडी और क्षति का प्रतिकार करने के लिए शुल्क को लागू किया जाना अनिवार्य है। इसलिए, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर सब्सिडीरोधी शुल्क को लागू करना जरूरी समझते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।

311. प्राधिकारी द्वारा अनुसरित लघु शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के समकक्ष प्रतिकारी/पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के समकक्ष, केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी/प्रतिकारी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं :-

शुल्क तालिका

क.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ के शुल्क राशि % के रूप में शुल्क राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	400219	एमल्शन स्टाइरिन बुटाडीन रबड़ (ई-एसबीआर) की 1500 श्रृंखला और 1700 श्रृंखला	कोरिया जन. गणराज्य	कोरिया जन. गणराज्य सहित कोई देश	कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कं० लि०	1.89
2	-वही-	-वही-	कोरिया जन.गणराज्य	कोरिया जन. गणराज्य सहित कोई देश	एलजी केम लि०	2.04
3	-वही-	-वही-	कोरिया जन. गणराज्य	कोरिया जन. गणराज्य सहित कोई देश	क्रम सं. 1 और 2 पर दिए गए उत्पादक के अतिरिक्त कोई अन्य	4.06
5	-वही-	-वही-	कोरिया जन. गणराज्य के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोरिया जन. गणराज्य	कोई भी	4.06

सीआईएफ मूल्य से तात्पर्य आकलन योग्य मूल्य से है, जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 (1962 का 52) के तहत यथा निर्धारित है।

312. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत यथानिर्धारित निर्धारणीय मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत आने वाले शुल्कों के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क शामिल होंगे।
313. इस अंतिम जांच परिणाम से उत्पन्न केंद्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

(Final Findings)

New Delhi, the 30th December, 2020

CASE No. CVD-07/2019

Subject: Anti-subsidy investigations concerning imports of “Styrene Butadiene Rubber” originating in or exported from Korea RP – Final Findings.

F. No. 6/21/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred as the “Anti-Subsidy Rules” or “Countervailing Rules” or “Rules”) as amended from time to time.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s Indian Synthetic Rubber Private Limited (ISRPL) and M/s Reliance Industries Limited (RIL) (hereinafter also referred to as the “Applicants”) filed an application before the Authority in accordance with the Act and the Rules for initiation of Anti-Subsidy investigation concerning imports of the Styrene Butadiene Rubber (hereinafter also referred to as the product under consideration or the subject goods) from Korea RP (hereinafter also referred to as the subject country).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicants, the Authority in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the Rules, initiated the anti-subsidy investigation vide Notification No. 6/21/2019-DGTR dated 29th October, 2019, published in the Gazette of India, to determine the existence, degree and effect of the alleged subsidization of the subject goods and to recommend the amount of anti-subsidy duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 6 supra.
 - b. The Authority sent invitation for consultations to the Government of Korea (“GOK”) on 09.10.2019 and thereafter on 15.10.2019 with the aim of allowing GOK to clarify the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. However, the Korean Government did not respond to the invitation for consultation.
 - c. The Authority issued a public notice dated 29th October 2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods from Korea RP.
 - d. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 29th October, 2019 to the embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers and other interested parties, as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - e. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of subject country in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra.
 - f. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
 - g. The Authority sent questionnaire to the Government of subject country in order to seek relevant facts/information with regard to various schemes/ programs where countervailable benefits might have

- been conferred by the Government. Governments of Korea RP has filed a questionnaire response, which has also been considered.
- h. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating anti-subsidy investigation to the following known producers/exporters in the subject country and provided opportunity to make their submissions known in writing within forty days in accordance with the Rules 6(2) and 6(4) of the Rules:
- iii. M/s Kumho Petrochemical Company Limited
 - iv. M/s LG Chem. Limited
- i. In response to the above notification, following exporters/producers have responded to or submitted exporter questionnaire responses:
- ix. M/s Kumho Petrochemical Company Limited
 - x. M/s Posco International Corporation Limited
 - xi. M/s LG Corporation Limited
 - xii. M/s Pantos Logistics Company Limited
 - xiii. M/s S&I Corporation Limited
 - xiv. M/s Seetec Company Limited
 - xv. M/s ServeOne Company Limited
 - xvi. M/s LG Chem. Limited
- j. The Authority sent Questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- xxv. M/s JK Tyres and Industries Limited
 - xxvi. M/s Birla Tyre Limited
 - xxvii. M/s Apollo Tyres Limited
 - xxviii. M/s CEAT Limited
 - xxix. M/s MRF Limited
 - xxx. M/s Ralson (India) Limited
 - xxxi. M/s Poddar Tyre Limited
 - xxxii. M/s Oriental Rubber Industries Private Limited
 - xxxiii. M/s Hindustan Rubber Industries Private Limited
 - xxxiv. M/s Agarwal Rubber Limited
 - xxxv. M/s Exel Rubber Private Limited
 - xxxvi. M/s Tega Industries Limited
 - xxxvii. M/s Phoenix Conveyor Belt India Private Limited
 - xxxviii. M/s Forech India Limited
 - xxxix. M/s Garware Bestrech Limited
 - xl. M/s Paragon Polymer Product Private Limited
 - xli. M/s Oriental Rubber Industries Limited
 - xlii. M/s Midas Rubber Private Limited
 - xliii. M/s Sempetrans Nirlon Private Limited
 - xliv. M/s Metro Tyres Ltd
 - xlvi. M/s Balakrishna Industries Limited
 - xlvi. M/s ATC Tires Private Limited
 - xlvi. M/s Goodyear India Limited

- xlvi. M/s Bridgestone India Private Limited
- k. In response to the above, following importers/users filed response: -:
- v. M/s CEAT Limited
- vi. M/s MRF Limited
- vii. M/s JK Tyre and Industries Limited
- viii. M/s Apollo Tyres Limited
- l. Additionally, the following interested parties filed submissions responding to the initiation notification:
- iii. M/s Kumho Petrochemical Company Limited
- iv. Automotive Tyre Manufacturers' Association
- m. Information provided by the Applicants and other interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the applicants or the other interested parties. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- n. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information in the form and manner prescribed during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative.
- o. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation, which has been received by the Authority. The Authority has relied upon DGCI&S transaction-wise data for the required analysis after due examination of the transactions.
- p. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1 April, 2018 to 31 March, 2019. The injury period includes 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the period of investigation.
- q. In accordance with Rule 7(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 9th September 2020. All the parties who had attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The parties were shared the nonconfidential submissions of the opposing parties and were given liberty to offer their rebuttals.
- r. Verification of the information provided by Applicants to the extent deemed necessary was carried out. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.
- s. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-subsidy duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- t. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed.
- u. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present disclosure statement on the basis of the facts available.
- v. In accordance with Rule 16 of the Rules, a Disclosure Statement containing all essential facts in this investigation which forms the basis of the present final finding was issued to the interested parties on 13th November 2020. The post disclosure statement submissions received from various interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Finding. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in this final finding.

- w. The Authority has considered arguments raised and information provided by the interested parties, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- x. ‘***’ in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= 70.82 Rs.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

“ Product under consideration in the present investigation is Emulsion Styrene Butadiene Rubber (hereafter referred to as “E-SBR”) limited to SBR 1500 and SBR 1700 series.

It is derived from two monomers namely styrene and butadiene. The polymerization of the two monomers is done through two processes namely, solution (S-SBR) and emulsion (ESBR). The product under consideration in the present investigation is limited to the SBR that comes out from emulsion process i.e. E-SBR.

The product finds its primary usage in the production of tires and tire retread compounds. The other areas of usage of E-SBR include house ware mats, drain board trays, shoe sole and heels, chewing gum, food container sealants, tires, conveyor belts, sponge articles, adhesives and caulks, automobiles mats, brake and clutch pads, hose, V-belts, flooring, military tank pads, hard rubber battery box cases, extruded gaskets, rubber toys, molded rubber goods, shoe soling, cable insulation and jacketing, pharmaceutical, surgical, and sanitary products, food packaging, etc.

The product under consideration is classified under Chapter 40 of Customs Tariff Act, 1975 under subheading 400219. The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the investigation.”

C.1 Submissions made by the Domestic Industry

5. The submissions made by the Domestic Industry with regard to product under consideration and like article are as follows:
- a. The product under consideration in the present investigation is Styrene Butadiene Rubber. Styrene Butadiene Rubber (SBR) describes family of synthetic rubbers derived from styrene and butadiene.
 - b. SBR is derived from two monomers, styrene, and butadiene. The mixture of these two monomers is polymerized by two processes – from solution (S-SBR) or as an emulsion (E-SBR).
 - c. E-SBR is produced by emulsion polymerization is initiated by free radicals. Reaction vessels are typically charged with the two monomers, a free radical generator, and a chain transfer agent, such as an alkyl mercaptan. The product under consideration is an E-SBR.
 - d. The majority of SBR is consumed in the manufacture of tyres. Thus, demand for SBR is quite dependent on the demand in the automotive sector.
 - e. Emulsion polymerized styrene-butadiene rubber (E-SBR) is one of the most widely used polymers of the world. There is a large variety of E-SBR types based on the styrene content, polymerization, temperature, staining or non-staining antioxidants, oil and carbon black content. Each of these basic classifications include a variety of SBR polymer variations with respect to Mooney viscosities, coagulation types, emulsifier type, oil levels, and carbon black types and level. The basic groups of E-SBR are 1000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900.
 - f. SBR 1500, 1700 and 1900 series are produced in India. The exporter/producers have the capacity to interchangeably produce SBR 1500, 1700 and 1900 series. However, the domestic industry is incapable of producing the 1900 series and hence 1900 series is not included in the scope of product under consideration.
 - g. The foreign products can possibly interchangeably produce SBR 1500, 1700 and 1900 series, the petitioners cannot produce SBR 1900 series. Neither Reliance nor ISRPL (the other producer of subject goods) can produce SBR 1900 series. The plant commissioned by them cannot produce SBR 1900 series. Further, consumers of SBR 1500 and 1700 series cannot consume SBR 1900 series product.
 - h. The interchangeability of various grades of SBR is possible between grades falling under two different series. For example, 1712 grade of SBR can be substituted with 1500 grade and many other grades of rubber falling under 1500 & 1700 series even in tyre tread application. Similarly, 1502 grade of SBR

can be substituted with 1500 grade and many other grades of rubber falling under 1500 and 1700 series in various applications.

- i. The present petition pertains to SBR 1500 series and SBR 1700 series. SBR 1900 series is specifically excluded from the scope of the product under consideration.
- j. The product under consideration is classified under Chapter 40 of Customs Tariff Act, 1975 under subheading 400219. The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the investigation. The product under consideration has been imported under 40021910, 40021990, 40021920, 40021930 & 40022000.
- k. There is no known difference in the product produced by the petitioner companies and exported from subject country.

C.2 Submissions made by Other Interested Parties

6. No submissions have been made by any other interested party with regard to product under consideration and like article

C.3 Examination by the Authority

7. The submissions made by the Domestic Industry with regard to the PUC related issues are examined and addressed hereunder.
8. The product under consideration in the present investigation is Emulsion Styrene Butadiene Rubber (hereafter referred to as “E-SBR”) limited to SBR 1500 and SBR 1700 series.
9. SBR is derived from two monomers – styrene and butadiene. Polymerization of these two monomers is done through two processes namely, solution (S-SBR) and emulsion (ESBR). The product under consideration in the present investigation is limited to emulsion SBR. Solution SBR is beyond the scope of the present investigation.
10. SBR finds its primary usage in the production of tires and tire retread compounds. The other usage of E-SBR include houseware mats, drain board trays, shoe sole and heels, chewing gum, food container sealants, tires, conveyor belts, sponge articles, adhesives & caulks, automobiles mats, brake & clutch pads, hose, V-belts, flooring, military tank pads, hard rubber battery box cases, extruded gaskets, rubber toys, molded rubber goods, shoe soling, cable insulation and jacketing, pharmaceutical, surgical, and sanitary products, food packaging, etc. However, the product is predominantly used in production of tires.
11. The product is classified under Chapter 40 of Customs Tariff Act, 1975 under subheading 400219. Imports of the product have however been reported under customs classification 400220. These imports have been included in determining volume and value of imports for the purpose of present determination. The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the present investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submissions of the Domestic industry

12. Following submissions have been made by the Applicants with regard to the domestic industry and standing:
 - i. The Applicants are the sole producers of the product under consideration and thus account for the entire Indian production.
 - ii. The Applicants have not imported the product under consideration from the subject country.
 - iii. The Applicants are neither related to the producers/exporters of the product under consideration in the subject country nor related to any of the importers of the product under consideration in India.
 - iv. The application satisfies the requirements of the rules.

D.2 Submissions of the other interested parties

13. The other interested parties have not made any submissions in regard to constitution of the domestic industry and its standing.

D.3 Examination by the Authority

14. Rule 2(b) of the Anti-subsidy Rules defines domestic industry as under:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total

domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or like article from other countries or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry”

15. The application has been filed jointly by both the producers of the subject goods in India namely, M/s Indian Synthetic Rubber Private Limited (ISRPL) and M/s Reliance Industries Limited (RIL). The Applicants declared that neither have they imported the subject goods from the subject country nor are they related to any importer/exporter of the subject product. There is no dispute to the claim made by the Applicants. The import data does not show any import of the product under consideration by the applicant companies from Korea RP. The Authority considers that the Applicants constitute domestic industry under Rule 2 (b) of the Rules and the application meets the criteria of standing under Rule 6 (3) of the Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1. Submissions of the Domestic Industry

16. Following miscellaneous submissions have been made by domestic industry:
- i. CVD margins do not materially change with the investigation period, unlike dumping margin. Most recent period is therefore not a need of an investigation in a CVD case and from CVD margin point of view.
 - ii. There was no law or rule governing the scope of period of investigation at the time of initiation of investigation. The manual only provides guidelines.
 - iii. Dumping margin determined for the responding producers in the anti-dumping investigation was lower as compared to the injury margin determined by the Authority.
 - iv. Neither of the applicants are engaged in the business of manufacturing tyre where SBR finds usage therefore there can be no captive consumption.
 - v. Trade notice referred by interested parties is applicable to anti-dumping investigations. Reference of the same to the countervailing duty is inappropriate .

E.2. Submissions of the other interested parties

17. Following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:
- i. There is a gap of 7 months between the initiation and the end of period of investigation. As per Manual and rule, period of investigation cannot be older than 6 months on the date of initiation.
 - ii. Anti-dumping duty and countervailing duty put-together cannot exceed the injury margin.
 - iii. The applicants have claimed excessive confidentiality with regards to Formats A to L, data on grades of SBR-1500 and SBR-1700, report mentioned for subsidy, manufacturing process, name of raw material, captive consumption, inventory as number of days of sale or production, NIP and R&D expense.
 - iv. No justification table, as required under the Trade Notice indicating reasons for confidentiality, has been provided as part of the petition.
 - v. Domestic industry is required to provide a nonconfidential copy of its secondary source of import data.
 - vi. The petitioner has been approaching different forums and seeking undue protection by way of Anti-Dumping and CVD measures through Ministry of Commerce.
 - vii. Domestic industry is getting protection since 2001 in the form of levy of Anti-dumping duty which is still on-going and is applicable till 2022.

E.3. Examination by the Authority

18. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows:

“Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information. (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a

statement of reasons why summarization is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

19. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing nonconfidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection.
20. The Authority considers a party is not obliged to disclose such information, confidentiality of which is protected under the law. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
21. As regards the submission that there is a gap of 7 months between the initiation of the investigation and the period of investigation, the Authority notes that there was no bar or rule proscribing initiation of investigations if the gap is more than six months. The only time limits were with regard to filing of application and the same have been complied with. Further, since the present investigation is a CVD investigation, the Govt. of Korea was afforded opportunity for consultation. The GOK was sent invitation for consultation on 09.10.2019 and again on 15.10.2019. However, GOK did not respond on two invitations. Therefore, the POI considered by the Authority is appropriate in the facts and circumstances of the case. Therefore, the Authority considers that the period of investigation in the present investigation is appropriate.
22. As regards to imposition of both anti-dumping and countervailing duty on the import of a product from specific countries, the Authority notes that Section 9B(a) provides that no article shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization. The Authority therefore considers that there is no bar either under Indian laws or WTO Agreements to impose both dumping and countervailing duty on the product imported from subject countries. The only bar is that no article shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping and export subsidization.
23. Export subsidies received by the exporter enables the exporter to lower the export price. Thus, export subsidies increase the difference between normal value and export price and results in higher dumping margin. Anti-dumping duty, which can be imposed to the full extent of dumping margin, remedies the distortion in the export price caused by export subsidies. In such a case, there is no further requirement to remedy this distortion caused by export subsidies by imposition of countervailing duties.
24. Anti-dumping duty was imposed on Styrene Butadiene Rubber to the full extent of dumping margin and therefore there is no requirement to recommend imposition of countervailing duty on export subsidization. The Authority has analyzed the nature of each subsidy programs. The Authority has segregated subsidies into subsidies contingent on export performance i.e. export subsidies and subsidies that are not contingent on export performance i.e. domestic subsidies. To ensure that there is no double remedy in the instant case while determining total countervailing duty, the Authority should not add subsidy margin for countervailable subsidy programs that are contingent on export performance. However, there are no countervailable export subsidies in the present investigation. Authority has accordingly determined subsidy margin for domestic subsidies for the purpose of determining countervailing duty.
25. Moreover, both dumping and countervailing duty law provides that the Designated Authority shall recommend the amount of duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. The Authority is required to ensure that total quantum of anti-dumping duty and countervailing duty should not exceed injury margin.
26. Therefore, the Authority has ensured that anti-dumping duty determined in the previous AD investigations and countervailing margin determined in this Anti subsidy/CVD investigations do not exceed injury margin determined by the Authority in the previous AD investigations as well as present Anti Subsidy investigations.
27. As regards both anti-dumping and countervailing duty, the Authority notes that Section 9B(a) provides that no article shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization. Further, since both dumping and countervailing duty law provides that the Designated Authority shall recommend the amount of duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. The product is attracting anti-dumping duty and it is

noted that the quantum of anti-dumping duty is upto the extent of dumping margin. The Designated Authority has also considered the injury margin determined in the previous investigation and present investigation while evaluating the quantum of countervailing duty (CVD).

28. As regards duties in force since 2001, it is noted that the duties levied on imports of Styrene Butadiene Rubber originating in, or exported from Japan, Taiwan, Turkey, France, U.S.A., Germany and Korea RP vide customs notification number 107/99 - Customs, dated the 24th August, 1999. Duties on imports of SBR of 1500 and 1700 series were removed with the final finding of the mid-term review investigation concluded vide DGTR notification dated 3rd July 2001 and customs notification no. 56/2002 dated 31st May 2002. Therefore, there were no duties on the imports of subject goods thereafter and prior to the anti-dumping duty imposed in 2017.

F. SUBSIDY AND DETERMINATION OF SUBSIDY MARGIN

29. The petition filed by Domestic Industry provided prima facie evidence of existence of countervailable subsidies in the subject country to initiate the instant investigation prior to initiation of investigation. The Government of Korea RP (GOK) was invited for consultation; however, they chose not to respond to the invitation sent by the Authority. The producers and exporters of the subject goods in the subject country as well as GOK was advised to file response to the questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.
30. Kumho Petrochemicals Co., Ltd. (hereinafter “KKPC” or “Kumho”) is a limited liability company established under the Commercial Laws of Republic of Korea. KKPC is engaged in the production and sale of synthetic rubbers, synthetic resins, specialty chemicals, electronic chemicals, energy, building materials and advanced materials as its core business. Kumho is a producer and exporter of subject goods from Republic of Korea. Subject Goods produced by Kumho are exported to India directly by Kumho to Indian customers, and also through, POSCO. KKPC has direct/indirectly exported 29,622 MT of the PUC to India in the POI. Both these companies filed questionnaire response and provided information regarding the benefits availed by them.
31. Authority has considered the information provided by Kumho and POSCO to the extent possible based on desk study, and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. The Authority determined that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of loans, grants and revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to Kumho and POSCO as a recipient of these grants. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including Kumho and POSCO, Korea RP.
32. It is noted that the LG Chem. Limited (herein after also referred to as LG), has filed questionnaire response. M/s LG Chem Ltd., is a producer/exporter of the subject goods who has exported subject goods to India directly during Period of Investigation. Further, it is noted that the following related parties of LG have also filed their questionnaire response: -

- vi. LG Corporation
- vii. Pantos Logistics Company Limited
- viii. S&I Corporation
- ix. Seetec Co., Ltd.
- x. Serve One Co. Ltd.

33. The questionnaire response has also been received from Government of Korea.

General overview of the alleged Subsidy Programs

F.1. Submissions of the Domestic industry

34. The submissions made by the domestic industry with regard to subsidies are as follows:
- a. Under Program 1, entity which undergoes process of corporate restructuring is eligible for extension of repayment of loans, reduction or discharge of debtor obligation for the principal and interest, or conversion of loans into investment.
 - b. Under Program 2, the exporter is allowed duty drawback on duty paid on an imported input that is consumed in the production of the exported product.
 - c. Under Program 3, the Government of Korea provides various subsidies in form of grants to the producers and exporters in Korea RP.

- d. Under Program 4, an enterprise engaged in renewable energy sector is provided with tax benefits and loans.
- e. Under Program 5, an eligible entity gets benefit in the form of tax deductions and grants.
- f. Under Program 6, enterprises are eligible for loans at low rate of interest and various other export benefits such as export financing, guarantee and bill discounting.
- g. There is sufficient evidence which shows that exporters in the subject country received subsidies in the form of grants, loans, tax incentives, equity infusion, export credits at concessional rates, goods & services at less than adequate remuneration which confer benefits to the recipients and such benefits are generally not granted to all the companies in Korea.
- h. These programs constitute actionable subsidies as per ASCM and the Rules.
- i. Kumho Polychem, Kumho Mitsui Chemicals, Kumho Trading, Kumho T&L and Korea Energy Power Plant are related to Kumho International and thereby related to Kumho but have not filed response.
- j. Whether a particular company has not provided services or inputs or funds is a matter of fact and can be investigated only when complete information about each and every affiliated company is provided by the exporter.
- k. All the affiliates of LG as reported in their Annual Report have not filed the response.
- l. The response filed does not provide any information which establishes how a producer of goods in the subject country is entitled to a duty drawback when it itself has not exported the product.
- m. The fact that out of the 13 banks that provided loans to Kumho in the Arrangement, 3 banks named KDB, KEBIK and IBK are government banks, which shows that the scheme is operated by entities which constitute public body.
- n. LG has filed incomplete response and has not provided information whether it has received corporate debt restructuring (CDR) benefit as alleged. The CDR scheme is not granted to a particular product. Therefore, the response filed by LG is required to be rejected on the ground that they merely stated that the company has not availed CDR for subject goods during the POI or Average Useful life (AUL).
- o. Since both the government and the exporters who have filed the response have not provided information required to establish that the conditions laid down under the ASCM for refund of duty paid on inputs are met, the claim that the drawback system allows rebate of only customs duty paid on inputs is required to be rejected.
- p. Any grant that is given by the government to the company has effect on all the products produced by the company. Therefore, a responding exporter is required to establish that benefit of various grants received is not linked at all to the product under consideration.
- q. Korea Energy Power Plant, one of the affiliates of the Kumho, must have availed benefit under Program 4 but has not filed the questionnaire response.
- r. Both LG and Kumho have admitted receiving benefits under the Program 5.
- s. GOK has not provided any information with regard to Reduction in local tax for real estate in industrial complex
- t. Kumho has received conditional loan and the loan received by them for any product or operations are required to be considered for the present purposes as well.
- u. Kumho and GOK have failed to report various local tax reduction under RSLTA in their responses making their response liable to be rejected.
- v. Both LG and Kumho have failed to report the benefits given by local government on exports made through Pohang Yeongil and Gwangvang ports.
- w. GOK has failed to report subsidies in relation to labor cost assistances in the submission making it countervailable subsidy. Further, Kumho and LG have not reported this scheme in their response making it liable to be rejected.

F.2. Submissions of other interested parties

35. The submissions made by the other interested parties with regard to subsidies are as follows:

- i. Benefits received by related entities not involved in the production and export of PUC and have not supplied raw material to the respondents are irrelevant and therefore are not required to file a response.
- ii. The AUL should be based on the response filed by the GOK and the respondents and not as claimed by domestic industry of 18 years.

- iii. The CVD duties cannot be recommended on the exports as the lower export price has been remedied by the imposition of ADD. Any price difference between the Korean producers' normal value and export price, arising out of export subsidies has already been addressed by the Authority by way of anti-dumping duty. Recommendation of duties arising out of Program 2 and Program 6 will result in double remedy.
- iv. As per SCM Agreement, the remission of such taxes in amounts not in excess of those which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy. As per the Refund of Customs Duties Act, if goods have been used for export, the custom officer shall refund the customs duties, etc. on the raw materials for export, which are used for such goods.
- v. In case of drawback is alleged to be in excess of import charges, the Authority is required to consider Para 1 of Part -2 (II) of Annexure II of CVD.
- vi. Remission in the Duty Drawback scheme is by way of two methods: simplified fixed amount refund method and individual method. The respondent cannot avail the remission under the simplified fixed amount method as it is only available to small to medium size enterprise whose duty drawback amount is less than 600 million KRW. However, the respondent is eligible under individual method which as determined by USDOC in Coated Free Sheet Paper from Korea that individual method of duty drawback does not provide countervailable subsidy.
- vii. The restructuring process carried out as per the terms of 'Company creditor voluntary agreement' CVA does not result in financial contribution by the govt.
- viii. Domestic industry has not specifically identified the impugned program/scheme which are conferring countervailable subsidies to the PUC nor has provided evidence of the impugned programs/ scheme which is conferring a benefit to the product under consideration but has made mere assertions without any positive evidence. Further, the subsidy margin has not been quantified in the petition.
- ix. Corporate Restructuring Promotion:
 - a. The present legislation for Corporate Restructuring Promotion does not confer a countervailable subsidy.
 - b. Financial institutions like KEXIM, KDB, KoFC are not public bodies – Appellate body in US- Carbon Steel (India) has been referred.
 - c. Contrary to the allegations made, CPRA does not classify the companies into any category.
 - d. Requirement of Article 2.1(b) have been specified for CPRA and thus does not amount to subsidy.
- x. Duty Drawback
 - a. ASCM only prohibits drawback of import charges in excess of the amount levied/ accrued.
 - b. The DDB legislation of Korea mandates the collection of excess rebates, in case any excess rebates of duty and it also provides a process in this regard. Since, the scheme fulfils the requirements of validity under the ASCM, the same cannot be countervailed.
 - c. The report (Study for Improving the Duty Drawback System) given by the domestic industry does not give any information about the excess refund received by Kumho and LG.
 - d. The Decision Memorandum of Coated Free Sheet Paper from Korea RP is for another product and hence cannot be relied upon as evidence of duty drawback scheme of Korea RP.
- xi. Renewable Energy Set-up Policy
 - a. Since a tax deduction is not a direct transfer of funds, the question of benefit being conferred by the government in this manner does not arise.
 - b. The concerned legislation (Section 25(1) (2) of RSTA 2018 and 25-2 of RSTA 2017) are not enterprise or sector specific as it includes SMEs and MSEs as a large number of enterprises panning across multiple sectors.
 - c. Article 10-2 of RSTA – tax deductions under this program are applicable to all companies who have kept R&D assets in separate accounts, and present program cannot be construed to confer a countervailable subsidy to PUC.

- d. Article 11 of RSTA - tax deductions under this program are applicable to all companies which have invested in expansion of infrastructure, and present program cannot be construed to confer a countervailable subsidy to PUC.
- e. Article 12 of RSTA - tax deductions under this program are applicable to all SMEs and individuals who transferred patent rights and knowhow. Therefore, present program cannot be construed to confer a countervailable subsidy to PUC
- f. Article 12-2 of RSTA - tax deductions under this program are applicable to all companies in the Special Research and Development Zone.
- g. Article 18 of RST A - tax deductions under this program are applicable to foreign nationals working in Korea RP and does not relate to PUC.
- h. Article 26 of RSTA - tax deductions under this program are applicable to all SMEs, 'transitioning companies' and any other company fulfilling the abovementioned criteria. present program cannot be construed to confer a countervailable subsidy to PUC.
- i. With regard to transactions with related companies reported in Annual Report of LG Chem, it has been submitted that M/s LG Chem Ltd., has procured services from its service providers namely M/s LG Corporation (Related Investment Company), M/s Pantos Logistics Company Limited (Logistic Service Provider Company), M/s S&I Corporation (Procurement Service Provider Company), M/s Serveone Company Limited (Procurement Service Provider Company) and M/s Seetec Company Limited (Utility Supplier Company) from Korea RP.

Examination by the Authority

F.3. Calculation Methodology

36. Article 14 of Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (hereinafter referred to as the "SCM"), provides guidelines and methodology for calculating the benefit to the recipient conferred pursuant to paragraph 1 of Article 1 of the SCM and further provides that any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be transparent and adequately explained. Further, any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be provided for in their national legislation or implementing regulations of the Member concerned and its application to each particular case shall be transparent and adequately explained. In accordance with the requirement, the Rules lay down the methodology of determination of quantum of subsidization. The determination in this investigation is in accordance with these guidelines.

SUBSIDY PROGRAMS ALLEGED IN THE PETITION

Following six subsidy programs have been specifically alleged in the petition and are mentioned in the notice of initiation.

Program No. 1- Corporate Restructuring/ Debt Restructuring

Submissions by Petitioners

37. The Petitioners have alleged this subsidy program under corporate restructuring / debt restructuring. As per Article 4 of Corporate Restructuring Promotion Act (CRPA) 2014 and Article 2(6) of 2016 "defines the term "enterprise" means an enterprise which has obtained credit from a creditor financial institution and the total amount of credit reaches or exceeds 50 billion won (hereafter referred to as "reference amount" in this subparagraph). In such cases, if an enterprise showing signs of insolvency has reduced the total amount of credit below the reference amount through readjustment of claims, repayment of debts, etc., such enterprise shall also be deemed an enterprise." Under article 2(7) of CRPA 2016, the term "enterprise with a sign of insolvency" means an enterprise that its principal creditor bank discovers, based on credit risk assessment having difficulties to perform its obligations in the normal course of business, such as repayment of a loan borrowed from a financial creditor (hereinafter referred to as 'a sign of insolvency'), without an additional cash inflow from outside in addition to ordinary borrowings". As per the scheme there are 4 types of Debt restructuring
 - a. Creditors - company voluntary agreement
 - b. Workout- (restructuring led by creditors)
 - a. Court - led insolvency proceedings
 - d. Special act on Corporate revitalization

Companies are eligible as per the financial risk and type of seriousness in which they are categories.

38. Corporate restructuring is carried out as per Corporate Restructuring Promotion Act (CRPA) for enterprise showing signs of insolvency. Government of Korea controlled banks namely Korea Development Bank, Korea Financial Corporation (KoFC), KEXIM, Industrial Bank of Korea (IBK), participated as creditors in corporate restructuring.. Kumho was eligible for the benefit under this program under one of the types of debt restructuring i.e. creditors-company voluntary agreement 2010-2012 (CVA) for a period of 3 years. LG group is also eligible for benefit under this program.
39. Non-recurring benefit was granted to the enterprise under corporate restructuring program in the form of postponed payments of debts, stable interest rates from 2010 to 2015, purchase of Convertible bonds etc.

Submissions by Government of Korea/Other interested parties

40. Companies under investigation, including Kumho & LG Chem, did not undergo the workout proceedings under the CRPA. Instead, Kumho underwent workout proceedings pursuant to a private agreement entered into by and among them and its creditors. Workout proceeding is intended to allow creditors to maximize debt recovery by stabilizing the company. It is voluntarily undertaken by the company and its creditors. The creditors led workout proceedings are not administered by any governmental agencies or authorities. The creditors will form a committee of creditor banks that will administer the restructuring procedures. The restructuring proceedings pursuant to the workout proceedings are not administered by any governmental agency or authority. The procedures are led by the creditors of the company.
41. CVA is not governed by CRPA or any other law in Korea. Therefore, there is no direct or indirect involvement of government in the restructuring process. The decision to extend support by creditors was a commercial decision and was an action to protect creditors' own interest. There was no role or direction by the government of Korea in this entire restructuring process.
42. In their response, M/s Kumho has explicitly given out all the differences between CVA & the restructuring program under CRPA in the questionnaire response to show absence of any direct or indirect involvement of the Government of Korea. The exporter further clarified that insolvency has been resolved and at the 7th Council of Financial Creditors, CVA was terminated on 28/12/2012 i.e. before the POI. Upon termination, Creditor banks allowed to distribute repayment of loan over a period of three years till end of 2015. Thus, there is no receipt or accrual of financial contribution by the Government during the POI. Restructuring process under the CVAs is independently determined by creditor's resolution, which requires involvement of all creditors' and 100% consensus. Therefore, there is no question of receipt of any benefit from the Government under any applicable law or regulation.
43. It has been submitted that under the program, LG Chem did not carry out any type of Corporate restructuring / Debt restructuring. Since establishment, LG Chem has been running its business without any crisis. LG Chem is excellent in its financial stability and there are no bank loans existing other than some of outstanding corporate bonds. Considering the situation, there was no corporate restructuring that has been carried out for company as a whole, and the same can be verified from LG Chem's Audit Report. The Audit Report does not mention any facts about corporate restructuring.

Examination by the Authority

44. The Authority notes that the program was governed under Article 6 of the Corporate Restructuring Promotion Act 2007 and Article 2(8) of the Corporate Restructuring Promotion Act 2016.
45. The Authority notes that the program has been earlier examined by other investigating authorities in the past, which also proves its existence. For example, countervailability of this program has been established by the US authorities in US- Certain Corrosion Resistant Steel Products.
46. The program provides financial contribution in the form of revenue forgone and hereby confers benefit to the recipient of such financial contribution. The program is specific because it is limited to enterprise that undertake corporate and debt restructuring.

Kumho:

47. Information provided in the questionnaire response of Kumho shows that Kumho has undertaken corporate restructuring under this program.
48. Under this program, restructuring is carried out for enterprise showing signs of insolvency. Under this program, resolutions are agreed by Council of Financial Creditors and enterprise undergoing restructuring process. The restructuring process under this program was through Creditors-Company Voluntary Agreement and was not governed by CRPA. Resolutions passed by financial creditors provided for different types of measure namely, i) grace period for repayment of outstanding loan (ii) Increase in limit of USANCE L/C (iii) Lending new loan and (iv) Purchase of convertible bond.

49. Creditor banks involved in the restructuring process involve three government owned banks namely, Korea Development Bank, Export-Import Bank of Korea & Industrial Bank of Korea.
50. Article 1 of Export-Import Bank of Korea Act provides that the purpose of bank is to promote the sound development of the national economy by providing finance required for the overseas economic cooperation, such as export and import, overseas investment and exploitation of overseas resources or through the incorporation of the Export-Import Bank of Korea. Article 18 of the Act provides that bank shall provide funds for (i) promotion of export, (ii) imports important to national economy (iii) export and importation by small and medium enterprises (iv) promotion of foreign investment (v) duties deemed to be necessary by the Government (vi) industrial development of specific region. The Act also requires approval of Minister of Strategy and Finance while performing these functions. Operation plan, business manual of bank is also to be approved by Ministry of Strategy and Finance. Article 39 of the Act provides that Ministry of Strategy and Finance shall supervise the operation of the Bank.
51. Article 1 of the Korea Development Bank Act provides that the purpose the Bank is to contribute to sound development of the financial industry and national economy, by establishing the Korea Development Bank which supplies and manages funds necessary for the development and fostering of industries, expansion of infrastructure, regional development, stabilization of the financial market, facilitation of sustainable growth, etc. Article 18 of the Act provides that KDB shall provide funds for development of industries, infrastructure, energy, small and medium enterprises and any other sector which the government deems necessary. Article 22 of the Act provides that Financial Services Commission grants approval for business plan, where priority consideration shall be given to the provision of funds to a sector for small and medium enterprises. The Financial Services Commission shall supervise the function of bank. The Financial Services Commission is a Government of Korea agency with the statutory authority over financial policy and regulatory supervision.
52. Article 1 of the Industrial Bank of Korea Act also provides for promotion of independent economic activities of small and medium proprietors to enhance their economic status which contributes to the establishment of an efficient credit system for the small and medium proprietors. Industrial Bank of Korea also functions under the supervision of Financial Services Commission in terms of Article 46 of the Act. Article 33 of the Act provides that it shall provide loans to SMEs and shall perform other functions entrusted by Government.
53. The Authority determines that government owned banks are public bodies because they are owned by Government and are vested with the Governmental Authority to carry out governmental functions. Measures regarding i) grace period for repayment of outstanding loan (ii) increase in limit of USANCE L/C (iii) lending new loan and (iv) purchase of convertible bond by these government owned banks are acts of public body.
54. The Authority also notes that all banks were acting under common CVA and acts of privately-owned banks in terms of (i) granting grace period for repayment of outstanding loan (ii) increase in limit of USANCE L/C (iii) lending new loan and (iv) purchase of convertible bond is not distinguishable from the acts of government owned banks. Analysis of loans, USANCE and purchase of convertible bonds shows that there is no essential difference between the practice followed by government owned banks and other creditor banks that are not owned by government. There is no information or evidence to support that the decisions regarding loans, increase in limit of USANCE and purchase of convertible bonds by creditor banks that were not government owned were based on market principles. Therefore, the Authority determines that all other privately-owned banks involved in restructuring process were entrusted or directed to adopt measures regarding i) grace period for repayment of outstanding loan (ii) increase in limit of USANCE L/C (iii) lending new loan and (iv) purchase of convertible bond.
55. Restructuring under CVA for Kumho took place between 2010 to 2012 i.e. within the AUL period of 10 years. Most of loans under CVA were repaid and terminated by 2015 and few loans graced by CVA were extended and repaid until 2017.
56. The amount of benefit in case of new and extended loans and loans through USANCE credit facility under CVA is determined by calculating the difference between the interest charged by these banks and the interest rate charged on a comparable commercial loan. The benchmark-interest rate charged on corporate bond of companies with equivalent credit rating at that time is considered for this purpose. The difference between the amount of interest paid on all these loans under CVA and the total interest amount payable as per benchmark interest rate was treated as one-time non-recurring benefit. The benefit amount was allocated over the AUL period to determine benefit accrued for the POI.
57. In case of convertible bond, convertible bonds of Kumho were purchased by banks under CVA restructuring process. Interest was payable to banks as per specified interest rates. The convertible bonds were converted into shares and were sold at market price in 2015 i.e. prior to the POI.

58. For determining the benefit in case of convertible bond, the Authority considered the credit rating of Kumho at the time of sales of corporate bonds. The Authority also considered the fact that the purchase of bond of Kumho by banks was part of the corporate restructuring process. Moreover, unlike loans and USANCE credit facility, purchase of convertible bonds of Kumho by banks cannot be considered as normal commercial function of banks.
59. Conversion of convertible bonds into share and resale of shares by banks subsequently after the end of restructuring process is also not relevant for determining the amount of benefit received by Kumho. The Authority determines that these convertible bonds of Kumho would not have been purchased by other private banks/entities based on market principles and as part of their normal commercial operations during restructuring process. Thus, the total benefit in case of purchase of convertible bond by banks is equal to the price paid by banks to Kumho for purchasing these convertible bonds. This total benefit amount was allocated over the AUL period to determine benefit accrued for the POI.
60. Questionnaire response filed by Kumho provides information regarding the amount of new loans, extended loans, loans through USANCE and the issuance of convertible bonds under this program. The Authority has determined that countervailing duty should be imposed against this program based on the information provided in the questionnaire response.
61. The Authority determines that provision of loans, increase in limit of USANCE by these banks in the restructuring process amounts to financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The subsidy is also specific because it is limited to the enterprise undergoing restructuring process. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program

LG Chem, Ltd.

62. However, LG Chem, has not received benefit under this subsidy program. Petitioners have also not provided any evidence to show that benefit was received under this program by LG Chem, Ltd. who exported ESBR to India during the POI.
63. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

Program No 2: Duty draw back –Refund of customs duties on raw materials for exports/ Duty Drawback on Non-Physically Incorporated Items and Excess Loss Rate

Submissions by the Petitioners

64. Exporting companies obtain a refund of Customs duty paid on imported raw material when the export is made within two years of import declaration. The program is governed as per Act on *Special Cases Concerning the refund of Customs Duties*. Refund is granted as per (i) simplified fixed amount refund method or as per (ii) individual refund method. The benefit under this program exists to the extent the amount of drawback exceeds the amount of import charges on the imported inputs which have been consumed in the production of the exported product after making normal allowances for wastes.

Submissions by Government of Korea/Other Interested parties

65. The duty drawback program does not allow for remission or drawback of custom duties in excess of those actually levied on inputs that are consumed in the production of exported goods. The governing act provides two methods for determining the refund amount of custom duties: i) the individual refund method & ii) the simplified fixed amount refund method. The individual refund method of the duty drawback program is the only method that is applicable to the companies under investigation. There is no benefit conferred under the impugned scheme because refund amount is calculated as per actual use of raw material in the exported product. In the absence of 'excess' refund, the refund of tax accrued on imported material used in exported product cannot be considered as 'subsidy' in terms of the Customs Tariff Act & the SCM Agreement.
66. Anti-dumping duty is already imposed on the import of subject goods from Korea RP. Duty drawback program is contingent on export and results in export subsidization. Article VI (5) of GATT & Section 9B(1)(a) of Customs Tariff Act provides that a product shall not be subject to both anti-dumping and countervailing duties to compensate for the same situation of dumping or export subsidization.
67. It has been submitted by the cooperating producers/exporters that there was no refund of custom duties in excess of those levied on imported inputs that are consumed in the production of the exported product, such as "Non-Physically Incorporated Items" and "Excess Loss Rate" received.

Examination by the Authority

68. The Authority notes that the program was governed under Act on Special Cases Concerning the refund of Customs Duties - Article 12 of Act 10817, Jul. 14, 2011 (Certificate of Tax Payment on Basic Raw Materials,

etc.) and Article 9 of Presidential Decree on Special Cases Concerning the refund of Customs Duties, <Amended by Act No. 13559, Dec. 15, 2015>

69. Authority notes that the alleged subsidy program provides for refund of import duty paid on raw materials used in exported product. There are two methods of duty drawback under this program namely, (i) the individual refund method & ii) the simplified fixed amount refund method. Participating producers/exporters are not eligible for simplified fixed amount refund method and therefore have received duty drawback as per individual refund method.
70. Under the individual refund method, Special Cases Concerning the Refund of Customs Duties levied on Raw Materials for Export Act ("The Act") provides that imported raw material must be used in exported product (Article 3). Export of the product using the imported raw material should occur within a period of 2 years (Article 9). The producer/exporter is required to apply for refund within 2 years from the date of filing a declaration for export.
71. Participating producers/exporters have submitted that the Act requires that "imported raw material has to be physically or chemically combined with relevant export goods". Producers/exporters have also submitted usage report and raw material matching table to show that producers/exporters availing duty drawback have to link their raw material and export by using "usage report".
72. The assessment by the Authority with regard to both the participating/cooperating producers/exporters show that there is no excess remission of import duty, and that amount of duty drawback will not exceed the amount of duty paid on raw materials used in production of exported goods.
73. The Authority determines that countervailing duty should not be imposed against remission of import duty on raw materials and therefore no countervailing duty is required to be imposed against this subsidy program.

Program No 3: Various government grants as per the Annual report of SBR producers or manufacturers Ad-hoc Subsidies

Submission by the Petitioners

74. The petitioner submitted that under this subsidy program, various government grants as per the Annual report of SBR producers or manufactures Ad-hoc Subsidies. General strategic policies to advance the industries by providing grants and other tax exemptions or reductions in order to encourage certain projects. Grants are provided by Korean government to its enterprises. Grants may be either related to assets or income which are provided at subsidized price as per the annual report of LG Company Ltd. Petitioners understands that Kumho Petrochemical Co., Ltd and LG group are eligible for the said benefit.

Submissions by Government of Korea/Other interested parties

75. Petitioners have failed to provide any meaningful explanation regarding the program and therefore it is not possible to identify the relevant program. There are no grant programs except for grant programs prescribed under Article 11 of Industrial Technology Innovation Promotion Act.
76. Under the program, LG Chem received small amount of R&D related government grants during the POI. However, the grants received are not related to production nor sales of PUC. In addition, other grant reported in consolidated cash flow statement of LG Chem, belong to its subsidiary company (LG Chem Nanjing, LG CNJ) located in Nanjing, China. It has been submitted that the grant is received from Chinese government, not Korean government, and the subsidiary company is not in any form or manner involved in production or sales of PUC. Therefore, there is no grant received by the respondent with relation to production or sale of PUC under the program.

Examination by the Authority

77. Authority notes that the Government supported R&D projects are prescribed in Article 11 of Industrial Technology Innovation Promotion Act. Based on this Act, government plans and specifies industries and R&D activities to be supported annually and issue public announcement.
78. A company may submit the application for R&D project and once the company's R&D project gets selected under the government review and approval, it will conduct R&D project based on agreed project plan with the government.
79. Grant is provided by the Government for approved R&D projects. Companies and government manage bank account for the R&D project which is earmarked for that project. Business plan specifies the amount of government and corporate contribution for the project. Companies and government transfer assigned amount to bank account. When the company makes a certain amount of expense for R&D projects during R&D period, government grant is transferred to the company's bank account.

80. The program provides financial contribution in the form of direct transfer of funds and hereby confers benefit to the recipient of such financial contribution. The program is also specific because it is available to selected enterprises and activities.
81. Questionnaire response filed by Kumho shows that benefit is received by them under this subsidy program. The Authority determines that countervailing duty should be imposed against this subsidy program. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program on Kumho.
82. LG Chem, Ltd. however have not received benefit under this subsidy program. Petitioners have also not provided any evidence to show that benefit was received under this program by LG Chem, Ltd. who exported ESBR to India during the POI. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program on LG Chem..

Program No. 4- Renewable Energy Projects Set-Up Policy

Submissions by the Petitioners

83. Petitioner submits that under this subsidy program, i.e. renewable energy projects set-up policy, in form of fund, Korean government through its Renewable Energy Center of Korea Energy Agency provides incentives in form of funds for installation, and production of renewable energy sector, Operation fund are mainly provided to small-sized companies in order to promote business operation of renewable energy facility. Tax reduction, as per Article 25-2 and Article 118 of Restriction of Special Taxation Act provides benefits in form of tax reduction for energy sector.
84. Petitioner understands that Enterprises which are engaged in renewable energy sector such as wind power generation facility, solar heat energy, geothermal facility, bio facility, photovoltaic module production line, wind power turbine production line are eligible for the said benefit.

Submissions by Government of Korea/Other Interested Parties

85. GOK provides long-term loans for investments in energy saving facilities in order to rationalize energy use and to reduce greenhouse gas emissions. This program was established in 1997 and the Korea Energy Agency administers this program according to the Guidelines for the Financing of Energy Use Rationalization Projects.
86. Under the program, LG Chem did not receive any subsidies (or grants) in forms of fund from Korean government nor through Renewable Energy Center of Korea Energy Agency during the POI (including AUL period). And, there was no tax reduction received under Article 25-2 and Article 118 of RSTA during the POI regarding Renewable Energy Projects Set-up Policy. Only a small amount (6.5 million KRW / 0.000028% of total company revenue) of tax reduction was made under Article 25-2, but the tax reduction is related to Energy Use Rationalization, not Renewable Energy Projects Set-up Policy.
87. GOK confirmed that LG Chem only received small amount of tax reduction under Article 25-2, but the tax reduction under the Energy Use Rationalization program, not Renewable Energy Projects Set-up Policy was among the following 4 types of assistance under the program
 - i. Financial Support for Energy Saving Facilities,
 - ii. Subsidization, etc. for Invested Expenses Regarding the Creation and Facilitation of Use of Smart Grids
 - iii. Tax Credits for Investment in Energy-Saving Facilities
 - iv. Restriction of Special Taxation Act Article 118: Reduction of Customs Duties
88. GOK clarified that the Guidelines for the Financing of Energy Use Rationalization Projects do not limit the eligibility of this program to certain sectors, regions, enterprises, industries, or group of enterprises or industries. Any enterprise investing in energy saving facilities is allowed to apply for long-term loans under this program. Therefore, this program lacks the specificity that is required to be considered a subsidy program

Examination by the Authority

89. The program provides long-term loans and grants to enterprises that install energy saving facilities to rationalize energy use and promote efforts to reduce greenhouse gas emissions. The program is extended only to enterprises which install energy saving facilities as defined in Article 14 of Energy Use Rationalization Act and Article 27 of Enforcement Decree of Energy Use Rationalization Act.
90. The Authority notes that the program provides for financial contribution in the form of preferential loans and grants (direct transfer of funds). The amount of benefit in case of loan is equal to the difference between the amount of interest payment to be made on loans granted pursuant to this subsidy program and the amount of

interest payment to be made on any other comparable commercial loan. The amount of benefit in case of grant is equal to the amount of grant attributable to the POI. The program is also specific because it is limited to companies investing in energy saving facilities. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

91. Questionnaire response filed by Kumho shows that benefit is received by them under this subsidy program. Therefore, the Authority determines that countervailing duty should be imposed against this program.
92. Questionnaire response filed by LG Chem, Ltd. Shows that it has received benefit under this subsidy program but covered under Energy Use Rationisation Program. Therefore, the Authority determines that countervailing duty should be imposed against this program.

Program No. 5: Research & Development Projects Support Policy / Corporate Tax Exemption/Reduction for Companies within Special R&D Zones

Submissions by the Petitioners

93. Petitioner submitted that under this program, Research & Development Projects Support Policy / Corporate Tax Exemption/Reduction for Companies within Special R&D Zones. The said program aims to facilitate Korean corporate investment in research and development activities through a reduction of taxes payable for eligible expenditures. As per (Article 10 to 12, 1B), the Restriction of Special Local Taxation Act (Article 26), and the Enforcement Decree of the Income Tax Act (Article 12) provides various tax credits for R&D investment such as:
 - (1) Reduction in local tax for real estate used for corporate research centers
 - (2) Tax credit for transfer, acquisition, and licensing of technology
 - (3) Income tax reduction for foreign engineers
 - (4) Special taxation on contributions related to research and development
 - (5) Corporate tax exemption/reduction for companies within special research and development zones
 - (6) Tariff reduction
94. The Korean company who performs its own R&D project, are eligible for the said benefits. It has been submitted that Enterprises which are engaged in Autonomous vehicles, electric vehicles, Artificial intelligence, internet of things, cloud, big data, wearable smart devices, IT convergence, Advanced software, security, Experiential contents, Advanced semi-conductors/sensors, OLED, 3D printing, 5G communication, ultra-high definition (UHD), Bio/health are eligible for the said benefit.

Submissions by Government of Korea/Other interested parties

95. Korean taxation system is broadly classified in two types of taxes namely, i) National & ii) Local Tax. The National Tax consists of i) Corporate tax for enterprise, ii) income tax for individuals & iii) value added tax. Local tax includes taxes imposed by local government.

There are six types of tax credits under Restriction of Special Taxation Act:

1. Tax Credits for Research & Human Resources Development Expenses (Article 10)
 2. Tax Credits for Investment in Facilities for Research & Human Resources Development Expenses (Article 11)
 3. Tax Credits for Investment in Energy – Saving Facilities (Article 25-2)
 4. Tax Credit for Investment etc. in Facilities for Environmental Conservation (Article 25-3)
 5. Tax Credits for Investment, etc. in Safety Facilities (Article 25)
 6. Tax Credits for Investment, etc. in Facilities for Improving Productivity (Article 24)
96. Under the program, LG Chem received small portion of Research & Development related corporate tax exemption/reduction (hereafter, Corporate Tax Credit) under the RESTRICTION OF SPECIAL TAXATION ACT (hereafter, RSTA) during the POI. LG Chem also reported total amount of corporate tax credit received during the POI with details of tax credit amount in its tax return. However, total amount of corporate tax credit (including R&D related corporate tax credit) is relatively small in total company revenue. Furthermore, most of the tax exemption/reduction is not related to production nor sales of PUC.
 97. LG Chem also received R&D related local tax reduction under the article 46 of RESTRICTION OF SPECIAL LOCAL TAXATION ACT (hereafter, RSLTA) during the POI, and AUL with related to non-recurring

program. However, like corporate tax credit under the RSTA, total amount of local tax reduction is relatively small in total company revenue. Furthermore, only a small portion of the local tax reduction is related to production and sales of PUC.

98. GOK has provided various information related to the R&D support policy program including corporate tax reduction under RSTA and local tax reduction under RSLTA.

Examination by the Authority

99. The Authority notes that under this program, when an enterprise incurs R&D, Human Resources Development, Environment Conservation, Energy Saving, Safety & Productivity expenses as defined in Restriction of Special Taxation Act, the enterprise can apply tax credit at specified rate. Enterprise is entitled to deduct tax credit amount from the Corporate Tax for the taxable year in which such expenses are incurred.
100. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The benefit is the difference between the corporate tax paid and the corporate tax payable in absence of these tax credits. The program is also specific because it provides benefit to specific enterprises incurring expenses for specified purposes.
101. Questionnaire response filed by Kumho and LG Chem. shows that benefit is received by them under this subsidy program. The Authority determines that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

Program No. 6- Preferential Lending by Industrial Bank of Korea

Submissions by the Petitioners

102. The Petitioner submitted that under this program, preferential lending by Industrial Bank of Korea. Industrial Bank of Korea has provided loans at low interest rate which are slightly lower than commercial banks irrespective of government's economic and industrial policy. In order to encourage SMEs (small and medium enterprise) are eligible for the said benefit. Interest rate has ranged from 1.75% to 3.7% under straight line method. Korea EXIM Bank has provided financial guarantee support for exports. On default of the company KEXIM repays entire credit amount with principal and interest. Industrial Bank of Korea or Korea EXIM Bank has provided Export& Import Factoring, Overseas Investment Credit Program and Trade Bill Discounting with low rate of interest. Petitioner understands that that Kumho Petrochemical Co., Ltd and LG group are eligible for the said benefit.

Submissions by Government of Korea/Other interested parties

103. Loans and loan guarantees are provided by banks as per commercial terms. Banks are operating as independent entities. There is no government involvement or direction to these banks. Submission by the participating exporters provides complete details of all loans received from government owned banks. Participating exporters have not received any loans at lower interest rates from the government and there is no benefit accruing to them from such loans.
104. LG Chem did not take any loan, nor utilize any financial services from the bank mentioned in the petition, such as the Korea Development Bank (KDB), Industrial Bank of Korea (IBK), and The Export-Import Bank of Korea (KEXIM). GOK confirmed that LG Chem did not take any loan, nor utilize any financial services from the bank mentioned in the petition, such as the Korea Development Bank (KDB), Industrial Bank of Korea (IBK), and The Export-Import Bank of Korea (KEXIM).
105. GOK submitted that LG Chem did not take any loan, nor utilize any financial services from the bank mentioned in the petition, such as the Korea Development Bank (KDB), Industrial Bank of Korea (IBK), and The Export-Import Bank of Korea (KEXIM).

Examination by the Authority

106. Authority notes that Government owned banks provide different types of loans under this program such as (i) operating loans (ii) long term loans for energy usage rationalisation (iii) short term limit loan etc. to meet varying financial needs of enterprises.
107. Korea Development Bank and Export-Import Bank of Korea are government owned banks and have provided loans to participating producers/exporters from Korea RP.
108. Authority has already determined that these government owned banks are public bodies. Accordingly, the loans provided by government owned banks are financial contribution in the form of direct transfer of funds by a public body. The benefit conferred on the recipient is in the form of difference between the amount of interest charged by these banks and the amount of interest charged on a comparable commercial loan. The program is

also specific because it is either contingent on export or is limited to enterprise that meets the other specified criteria for loan.

Kumho

109. Questionnaire response filed by Kumho shows that benefit is received by them under this subsidy program. The Authority determines that countervailing duty should be imposed against this subsidy program to Kumho.

L G Chem

110. LG Chem did not take any loan, nor utilize any financial services from the bank mentioned in the petition, such as the Korea Development Bank (KDB), Industrial Bank of Korea (IBK), and The Export-Import Bank of Korea (KEXIM). Therefore, neither any financial contribution nor any benefit was conferred to LG Chem during the POI. The Authority determines that countervailing duty should not be imposed against this subsidy program to LG Chem.

Program No. 7: Other Subsidy

Other programmes availed by cooperating producers and exporters

111. Following subsidies are identified as 'other subsidy program' because these subsidies have not been specifically claimed by the domestic industry in its petition and are not mentioned in the notice of initiation but information about these subsidies have been provided by participating companies in their questionnaire response, and also upon queries raised by the Authority to cooperating /participating producers and exporters.

Other Subsidy : Kumho

112. The Petitioner has not submitted any program other than above Program No. 1 ~ No. 6.

Program 7.1.1 – Reduction in Local Tax for Real Estate in Industrial Complexes

Submissions by Government of Korea/Other Interested Parties

113. Participating producers/exporters have received tax reduction for acquisition tax on real estate acquired by construction or expansion of an industrial building under Article 78(4) (Reduction for Industrial Complexes, etc.) for factories located in industrial complexes.

Examination by the Authority

114. When an enterprise acquires real estate, it is obligated to pay acquisition tax. Acquisition tax is imposed on a corporate who has acquired real estate defined in Article 7 of Special Local Tax Act. Under this program, an enterprise is entitled to get a certain amount of tax reduction for acquisition tax when it acquires real estate located in industrial complexes. When the enterprise acquires real estate located in industrial complexes which are defined under Article 78(4) of Special Local Taxation Act, it could avail tax reduction.
115. The Authority notes that the program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. Amount of benefit is equal to the tax payable under Act and the tax paid after deduction. The program is also specific because it is limited to enterprises who acquire specified real estate.
116. Questionnaire response filed by Kumho shows that benefit is received by them under this subsidy program. The Authority determines that countervailing duty should be imposed for this program.

Program 7.1.2 – Conditional Loans/Loans by Korea Energy Agency

Submissions by Government of Korea/Other Interested Parties

117. Conditional loans are granted by Korea Energy Agency for the overseas exploration business project.

Examination by the Authority

118. Authority notes that the Korea Energy Agency (KEA) is a governmental agency that carries out national energy policies for energy efficiency.
119. Relevant laws governing the programs are Overseas Resources Development Business Act & Energy and Resources Special Account Act. Article 10 of the Overseas Resources Development Business Act provides that for promotion of the development of overseas resources, the Government may help with expenses as prescribed. Article 11 of the Overseas Resources Development Business Act provides that the Government may furnish funds to an overseas resources developer to facilitate the overseas resources development. Energy and Resources Special Accounts Act provides for special accounts for funds established for projects related to energy and resources including overseas resources.

120. Under this program, loans are granted to enterprises by Korea Energy Agency for Overseas Exploration business project. Enterprise must correspond to the Overseas Financing Standard of Resources Development Business Fund from Ministry of Trade Industry and Energy. Approval, Issuance and repayment of loans are governed by this announcement by Ministry of Trade, Industry and Energy. Under this program, repayment of loan obligation arises if overseas exploration business project begins to run commercially.
121. Accordingly, Authority determines that the loan provided by Korea Energy Agency is a financial contribution in the form of direct transfer of funds by a public body.
122. The benefit conferred on the recipient is in the form of the amount of loan waived and in case of repayment of loan, the difference between the amount of interest charged by these banks and the amount of interest charged on comparable commercial loan. The program is also specific because it is either contingent on export or is limited to enterprises that meet the other specified criteria for loan. Questionnaire response filed by Kumho shows that benefit is received by them under this subsidy program. The Authority determines that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

Program 7.1.3 - Establishing and expanding a workplace infant care centre

Submissions by Government of Korea/Other interested parties

123. Grant was received in 2015 for a workplace infant care center and was paid to POSCO International by the Korea Workers' Compensation & Welfare Service. The amount of the original grant is being depreciated over four (4) years.
124. It has been claimed by LG Chem that it received *** KRW amount of Labor cost assistances during POI for operating a workplace, infant care center. However, all the amount received is directly transferred to infant care center that the respondent believes there is no benefit received from the labor cost assistances program for operating a workplace infant care center. It has been claimed that there is no subsidy available for construction of workplace and nursery. Establishment/Construction of Workplace Child-Care Centers is regulation on duty for the business owner who operates a workplace in a size larger than that prescribed by Presidential Decree. Only the benefit received from construction of workplace and nursery is property tax reduction and acquisition tax reduction for Child Care Center under "RSLTA-Article 19 (Reduction or Exemption for Child Care Centers and Kindergartens)". Details of the tax reduction received have already been provided as response to "Other Program:

Examination by the Authority

125. The Authority notes that under this program grant is provided by Korea Workers' Compensation and Welfare Services, which is being depreciated every four years.
126. The Authority determines that the grant provided by the government is a financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is specific to certain enterprises having an infant care center.
127. Questionnaire response filed by POSCO shows that benefit is received by them under this subsidy program during the AUL period. The Authority determines that countervailing duty should be imposed against this program.

Program 7.1.4 – Grant for R&D Assets

Submissions by Government of Korea/Other interested parties

128. Certain one-time grants received from different government agencies were recorded in the financial statements of companies.

Examination by the Authority

129. Authority notes that under this program, grants were received for R&D Assets such as tools and moulds and for steel processing machinery as part of the grants received towards property, plant and machinery.
130. The Authority determines that the grant provided by the government is a financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is specific to certain enterprises engaged in R&D activity. Questionnaire response filed by POSCO shows that benefit is received by them under this subsidy program during the AUL period. However, the Authority notes that the benefit is tied to non-PUC. Therefore, the Authority determines that no countervailing duty should be imposed against this program.

Program 7.1.5 – Corporate Tax exemption***Submission by Government of Korea/Other interested parties***

131. Tax credit obtained by companies pursuant to various investment expenses and other expenses can be identified from the annual tax return filed by the company.

Examination by the Authority

132. Authority notes that under this program, company can claim tax credit for investment and other such expenses incurred by it at the time filing annual tax return.
133. The Authority notes that the program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The benefit is equal to the difference between corporate tax paid and the corporate tax payable in absence of the tax credits obtained under this program. Questionnaire response filed by POSCO shows that benefit is received by them under this subsidy program. The Authority determines that countervailing duty should be imposed against this program.

Program 7.1.6 - Labor cost assistances for operating a workplace infant care center***Submissions by Government of Korea/Other Interested Parties***

134. Government encourages companies to have a workplace infant care center for its employees' welfare and assists them by arranging labor costs of kindergarten teachers. Such assistances are recurring because the benefits must be given on a monthly and regular basis considering the number of kindergarten teachers hired by the workplace infant care center. Also, such benefits are directly transferred to the banking account of the workplace infant care center and are restricted to be spent only for the labor cost.

Examination by the Authority

135. The Authority notes that under this program grant is provided to an enterprise by the government for labor cost expenses of infant care center at workplace.
136. The Authority determines that the grant provided by the government is a financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is specific to certain enterprises having an infant care center.
137. Questionnaire response filed by POSCO shows that benefit is received by them under this subsidy program. The Authority determines that countervailing duty should be imposed against this program.

Program 7.1.7-Loans from government invested banks other than International Bank of Korea (“IBK”)***Submissions by Government of Korea/Other Interested Parties***

138. Companies undertake loans from government invested banks such as Korea Energy Agency, Korea Development Bank, Korea, The Export-Import Bank of Korea (KEXIM), Korea Rural Community Corporation (KRC) which are not only utilized for PUC related business but may also be used for their general operation cash flow or non-PUC businesses such as petroleum and natural mineral, and food resource development project.

Examination by the Authority

139. Under this program, loans are provided by government owned banks in Korea to enterprises for conducting general operations and for operations not relating to the production of subject product.
140. Authority has already determined that these government owned banks are public bodies. Accordingly, the loans provided by government owned banks are financial contribution in the form of direct transfer of funds by a public body. The benefit conferred on the recipient is in the form of difference between the amount of interest charged by these banks and the amount of interest charged on comparable commercial loan. The program is also specific because it is limited to enterprise that meets the specified criteria for loan. Questionnaire response filed by POSCO shows that benefit is received by them under this subsidy program. The Authority determines that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

Program 7.1.8-Usage incentives received for using Port facilities***Submissions by Government of Korea/Other Interested Parties***

141. Companies receive Port Usage Incentives from Pohang Yeongil Port Authority in order to boost the Port's utilization. The local government provides incentives to consignors or forwarders who handle shipping container cargo at the Port. This incentive is provided based on the cargo volume of containers using the Port.

142. Such incentives are recurring because they are regularly measured by the local government after every half year. The incentive amount is so small that it provides a negligible benefit.

Examination by the Authority

143. The Authority notes that under this program grant is provided by the local government to consignors, forwarders and others handling shipping cargo at the port.
144. The Authority determines that the program provides for direct transfer of funds by the local government in the form of grant which results in financial contribution and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific to enterprises that use port facilities. Questionnaire response filed by POSCO shows that benefit is received by them under this subsidy program. The Authority determines that countervailing duty should be imposed against this program.

Program No. 7.1.9 – Assistance received for R&D on Electric Vehicles

Submissions by Government of Korea/Other Interested Parties

145. Grant received by company for electrical vehicles and module commercialisation technology before the POI.

Examination by the Authority

146. Authority notes that the grant is provided for research and development of (i) module commercialization technology & (ii) for small and medium commercial electric vehicles based on IoT Technology.

The Authority determines that the program provides for direct transfer of funds by the government in the form of grant which results in financial contribution and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific to certain enterprises. Questionnaire response filed by POSCO shows that benefit is received by them under this subsidy program. However, the Authority notes that the benefit is tied to non-PUC. Therefore, the Authority determines that no countervailing duty should be imposed against this program.

Program 7.1.10-Assistance for an overseas research project in food & agriculture industry

Submissions by Government of Korea/Other Interested Parties

147. Companies can avail assistances for their research projects in the food and agriculture industry. This program is unrelated to the production or export of PUC and is thus not countervailable.

Examination by the Authority

148. The Authority notes that under this program grant is provided for overseas research projects in the food and agricultural sector.
149. The Authority determines that the program provides for direct transfer of funds by the government in the form of grant which results in financial contribution and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific to certain enterprises. Questionnaire response filed by POSCO shows that benefit is received by them under this subsidy program. However, the Authority notes that the benefit is tied to non-PUC. Therefore, the Authority determines that no countervailing duty should be imposed against this program.

Program 7.1.11- Assistance for a research project in copper mine development in Australia

Submissions by Government of Korea/Other Interested Parties

150. Grant received for conducting feasibility study about acquisition of shares of a copper mine in Australia. This program is unrelated to the production or export of PUC and is thus not countervailable.

Examination by the Authority

151. The Authority notes that under this program grant is provided by the government for overseas mining project.
152. The Authority determines that the program provides for direct transfer of funds by the government in the form of grant which results in financial contribution and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific to certain enterprises. Questionnaire response filed by POSCO shows that benefit is received by them under this subsidy program. However, the Authority notes that the benefit is tied to non-PUC. Therefore, the Authority determines that no countervailing duty should be imposed against this program.

Kumho and Posco (Producer/Exporter)

153. Kumho is a producer and exporter of subject goods from Republic of Korea. Subject Goods produced by Kumho are exported to India directly by Kumho to Indian customers, and also through, POSCO. Both these companies filed questionnaire response and provided information regarding the benefits availed by them.

154. Authority has verified the information provided by Kumho and POSCO to the extent possible based on desk study, and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. The Authority determined that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of loans, grants and revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to Kumho and POSCO as a recipient of these grants. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including Kumho and POSCO.

155. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

Subsidy Margin Summary Table : Kumho Petrochemical Co. Ltd. And Posco

Program No.	Name of the Program	Subsidy margin as % of CIF	Brief description	Subsidy Margin Range
Programs alleged in the Petition				
Kumho				
(1)	Corporate Restructuring (Loans, Grace Period on Loans, USANCE)	***	Loan/grant	0-5%
1(2)	Corporate Restructuring (Convertible Bond)	***	Loan/grant	0-5%
3	Government Grant for R&D Projects	***	Loan/grant	0-5%
4(1)	Renewable Energy Project Setup Policy (Loans)	***	Loans	0-5%
4(2)	Renewable Energy Project Setup Policy (Grants)	***	Grant	0-5%
5	Research & Development Project Support Policy (Tax Credit /Revenue foregone) under Restriction of Special Taxation Act	***	Tax credits/Revenue foregone	0-5%
6	Preferential lending by Industrial Bank of Korea	***	Loans	0-5%
7.1.1	Reduction of local tax for real estate in industrial complexes	***	Tax credits/Revenue foregone	0-5%
7.1.2	Conditional loans	***	Loan/grant	0-5%
Total for Kumho		***	***	0-5%
Total for Kumho		1.775		0-5%
POSCO				
7.1.3	Grant for establishing and operating a workplace infant care center	***	Grant	0-5%
7.1.5	Corporate Tax Exemption, Tax credit for investment and other expenses	***	Tax credits/Revenue foregone	0-5%
7.1.6	Labour cost assistance for operating a workplace infant care center	***	Grant	0-5%
7.1.7	Loans from government invested banks other than IBK	***	Loans	0-5%

7.1.8	Usage incentive received for Pohang Yeongil and Gwangyang Port	***	Grant	0-5%
Total for POSCO		***		0-5%

Weighted average for Kumho and POSCO		***		0-5%

156. The Authority notes that subsidy margin for Kumho and Posco is more than de-minimis.

Other Subsidy:

157. Petitioners did not submit any subsidy program other than above Program No. 1 to 6 as mentioned above. However, the responding producers/exporters from Korea RP have submitted during the investigations that they have availed following benefits/subsidies under other programs.

LG Chem Ltd

158. The following are other subsidies which have been submitted by the producer/exporter during the process of investigations.

LG Chem Ltd

Program No. 7.2.1: Other Subsidy – Reduction for Industrial complexes, etc.

a. Submission by the Government of Republic of Korea/other interested parties

159. With regard to **Reduction in Local Tax for Real Estate in Industrial Complexes**, it has been submitted that while preparing the questionnaire responses, LG Chem found that various local tax reductions had been received under RSLTA during the POI. It has also been submitted that LG Chem received other various local tax reduction under the article 19, 47(2), and 78 of RESTRICTION OF SPECIAL LOCAL TAXATION ACT (hereafter, RSLTA) during the POI, and AUL with related to non-recurring program.
160. Under the article 78 of RSLTA - Reduction for Industrial Complexes, etc., LG Chem received small amount of local tax reductions. As a recurring program, LG Chem received 68.8 million KRW of property tax reduction during the POI. And, as a non-recurring program, LG Chem received 15,668 million KRW of acquisition tax reduction during the AUL.
161. However, just same as corporate tax credit under the RSTA, total amount of local tax reduction is relatively small in total company revenue. Furthermore, only a small portion of the local tax reduction is related to production and sales of PUC.
162. GOK provided information with related to other Subsidy – property tax reduction for Industrial complexes, etc. including several local tax reductions under RSLTA during the on-line verification.

b. Examination by Authority

163. The program provides financial contribution in the form of revenue forgone and direct transfer of funds and hereby confers benefit to the recipient of such financial contribution. The program is specific because it is limited to certain enterprise. LG Chem, Ltd. have received benefit under this subsidy program. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(i) Program No. 7.2.2 Other Subsidy – Acquisition Tax Reduction for Industrial Complexes, etc. from Seosan City

a. Submission by the Government of Republic of Korea/other interested parties

164. Under the article 78 of RSLTA - Reduction for Industrial Complexes, etc., LG Chem received small amount of acquisition tax reductions. As a non-recurring program, LG Chem received 3,045 million KRW of acquisition tax reduction during the AUL.
165. However, just same as corporate tax credit under the RSTA, total amount of local tax reduction is relatively small in total company revenue. Furthermore, only a small portion of the local tax reduction is related to production and sales of PUC.
166. GOK provided information related to other Subsidy – Acquisition Tax Reduction for Industrial Complexes, etc. from Seosan City during the on-line verification.

b. Examination by Authority

167. The program provides financial contribution in the form of revenue forgone and direct transfer of funds and hereby confers benefit to the recipient of such financial contribution. The program is specific because it is limited to certain enterprise.
168. LG Chem, Ltd. have received benefit under this subsidy program. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(i) Program No. 7-3: Other Subsidy – Property Tax Reduction for Buildings Certified as Green Architecture**a. Submission by the Government of Republic of Korea/other interested parties**

169. Under the article 47(2) of RSLTA - Reduction for Buildings Certified as Green Architecture, LG Chem received small amount of property tax reductions. As a recurring program, LG Chem received 4.5 million KRW of property tax reduction during the POI.
170. However, just same as corporate tax credit under the RSTA, total amount of local tax reduction is relatively small in total company revenue. Furthermore, only a small portion of the local tax reduction is related to production and sales of PUC.
171. GOK provided information related to other Subsidy – Property Tax Reduction for Buildings Certified as Green Architecture during the on-line verification.

b. Examination by Authority

172. The program provides financial contribution in the form of revenue forgone and direct transfer of funds and hereby confers benefit to the recipient of such financial contribution. The program is specific because it is limited to certain enterprise.
173. LG Chem, Ltd. have received benefit under this subsidy program. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(ii) Program No. 7-4: Other Subsidy – Acquisition Tax Reduction for Buildings Certified as Green Architecture from Seoul City**a. Submission by the Government of Republic of Korea/other interested parties**

174. Under the article 47(2) of RSLTA - Reduction for Buildings Certified as Green Architecture, LG Chem received small amount of acquisition tax reductions. As a non-recurring program, LG Chem received 240.0 million KRW of acquisition tax reduction during the AUL.
175. However, just same as corporate tax credit under the RSTA, total amount of local tax reduction is relatively small in total company revenue. Furthermore, only a small portion of the local tax reduction is related to production and sales of PUC.
176. GOK provided information related to other Subsidy – Acquisition Tax Reduction for Buildings Certified as Green Architecture from Seoul City during the on-line verification.

b. Examination by Authority

177. The program provides financial contribution in the form of revenue forgone and direct transfer of funds and hereby confers benefit to the recipient of such financial contribution. The program is specific because it is limited to certain enterprise.
178. LG Chem, Ltd. have received benefit under this subsidy program. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(iii) Program No. 7-5-1: Other Subsidy – Property Tax Reduction for Child Care Centers and Kindergartens from Daejeon City**a. Submission by the Government of Republic of Korea/other interested parties**

179. Under the article 19 of RSLTA - Reduction or Exemption for Child Care Centers and Kindergartens, LG Chem received small amount of property tax reductions. As a recurring program, LG Chem received 1.0 million KRW of property tax reduction during the POI.

180. However, just same as corporate tax credit under the RSTA, total amount of local tax reduction is relatively small in total company revenue. Furthermore, only a small portion of the local tax reduction is related to production and sales of PUC.

181. GOK provided information related to other Subsidy – Property Tax Reduction for Child Care Centers and Kindergartens from Daejeon City during the on-line verification.

b. Examination by Authority

182. The program provides financial contribution in the form of revenue forgone and direct transfer of funds and hereby confers benefit to the recipient of such financial contribution. The program is specific because it is limited to certain enterprise.

183. LG Chem., Ltd. have received benefit under this subsidy program. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(iv) Program No. 7-5-2: Other Subsidy – Property Tax Reduction for Child Care Centers and Kindergartens from Seoul City

a. Submission by the Government of Republic of Korea/other interested parties

184. Under the article 19 of RSLTA - Reduction or Exemption for Child Care Centers and Kindergartens, LG Chem received small amount of property tax reductions. As a recurring program, LG Chem received 2.0 million KRW of property tax reduction during the POI.

185. However, just same as corporate tax credit under the RSTA, total amount of local tax reduction is relatively small in total company revenue. Furthermore, only a small portion of the local tax reduction is related to production and sales of PUC.

186. GOK provided information related to other Subsidy – Property Tax Reduction for Child Care Centers and Kindergartens from Seoul City during the on-line verification.

b. Examination by Authority

187. The program provides financial contribution in the form of revenue forgone and direct transfer of funds and hereby confers benefit to the recipient of such financial contribution. The program is specific because it is limited to certain enterprise.

188. LG Chem, Ltd. have received benefit under this subsidy program. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(v) Program No. 7-6-1: Other Subsidy – Acquisition Tax Reduction for Child Care Centers and Kindergartens from Seoul City

a. Submission by the Government of Republic of Korea/other interested parties

189. Under the article 19 of RSLTA - Reduction or Exemption for Child Care Centers and Kindergartens, LG Chem received small amount of acquisition tax reductions. As a non-recurring program, LG Chem received 89.5 million KRW of acquisition tax reduction during the AUL.

190. However, just same as corporate tax credit under the RSTA, total amount of local tax reduction is relatively small in total company revenue. Furthermore, only a small portion of the local tax reduction is related to production and sales of PUC.

191. GOK provided information related to other Subsidy – Acquisition Tax Reduction for Child Care Centers and Kindergartens from Seoul City during the on-line verification.

b. Examination by Authority

192. The program provides financial contribution in the form of revenue forgone and direct transfer of funds and hereby confers benefit to the recipient of such financial contribution. The program is specific because it is limited to certain enterprise.

193. LG Chem, Ltd. have received benefit under this subsidy program. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(vi) Program No. 7-6-2: Other Subsidy – Acquisition Tax Reduction for Child Care Centers and Kindergartens from Daejeon City

a. Submission by the Government of Republic of Korea/other interested parties

194. Under the article 19 of RSLTA - Reduction or Exemption for Child Care Centers and Kindergartens, LG Chem received small amount of acquisition tax reductions. As a non-recurring program, LG Chem received 36.5 million KRW of acquisition tax reduction during the AUL.
195. However, just same as corporate tax credit under the RSTA, total amount of local tax reduction is relatively small in total company revenue. Furthermore, only a small portion of the local tax reduction is related to production and sales of PUC.
196. GOK provided information related to other Subsidy – Acquisition Tax Reduction for Child Care Centers and Kindergartens for Daejeon City during the on-line verification.

b. Examination by Authority

197. The program provides financial contribution in the form of revenue forgone and direct transfer of funds and hereby confers benefit to the recipient of such financial contribution. The program is specific because it is limited to certain enterprise.
198. LG Chem, Ltd. have received benefit under this subsidy program.
199. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(vii) Program No. 7-7: Other Subsidy – Labor cost assistances for operating a workplace infant care center**a. Submission by the Government of Republic of Korea/other interested parties**

200. LG Chem also received Labor cost assistances for operating a workplace infant care center. However, all the amount received was directly transferred to infant care center. It was submitted that the respondent believes there is no benefit received from the labor cost assistances program for operating a workplace infant care center.
201. GOK provided information related to other Subsidy – Labor cost assistances for operating a workplace infant care center including relevant regulations during the on-line verification.

b. Examination by Authority

202. The program provides financial contribution in the form of direct transfer of funds however, it does not confer benefit to the recipient of any financial contribution.
203. LG Chem, Ltd. have not received benefit under this subsidy program. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(viii) Program No. 7-8: Other Subsidy – K-Sure Export related credit guarantee**a. Submission by the Government of Republic of Korea/other interested parties**

204. It was submitted that LG Chem utilizes the K-SURE credit guarantee for its export sales. LG Chem bears additional expenses for the same. Expenses incurred for utilizing the K-SURE credit guarantee in total company-wide and in export sales of PUC to India market are provided as part of verification package. It was further submitted that there was no default of trade receivables regarding export sales of PUC to India market. Hence, no financial contribution was received under the export related credit guarantee of K-SURE.
205. GOK provided information related to other Subsidy – K-Sure Export related credit guarantee including relevant regulations during the on-line verification.

b. Examination by Authority

206. LG Chem, Ltd. have not received benefit under this subsidy program. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.
207. The table below provides details of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin in respect of LG Chem, Ltd. Korea RP.

Program No.	Name of the grant program	Brief Description/ Comment	Subsidy margin as % of CIF	Subsidy Margin Range %
			%	
Program No. 4	Renewable Energy Projects Set-up Policy	Loan/Grant	***	0-5%
Program No. 5	Research & Development Projects Support Policy / Corporate Tax Exemption/Reduction for Companies within Special R&D Zones	Tax credits/Revenue forgone	***	0-5%
Program No. 7-1	Property Tax Reduction for Industrial Complexes, etc	Tax credits/Revenue forgone	***	0-5%
Program No. 7-2-1	Acquisition Tax Reduction for Industrial Complexes, etc. from Seosan City	Tax credits/Revenue forgone	***	0-5%
Program No. 7-2-2	Acquisition Tax Reduction for Industrial Complexes, etc. from Seoul City	Tax credits/Revenue forgone	***	0-5%
Program No. 7-3	Property Tax Reduction for Buildings Certified as Green Architecture	Tax credits/Revenue forgone	***	0-5%
Program No. 7-4	Acquisition Tax Reduction for Buildings Certified as Green Architecture from Seoul City	Tax credits/Revenue forgone	***	0-5%
Program No. 7-5-1	Property Tax Reduction for Child Care Centers and Kindergartens from Daejeon City	Tax credits/Revenue forgone	***	0-5%
Program No. 7-5-2	Property Tax Reduction for Child Care Centers and Kindergartens from Seoul City	Tax credits/Revenue forgone	***	0-5%
Program No. 7-6-1	Acquisition Tax Reduction for Child Care Centers and Kindergartens from Seoul City	Tax credits/Revenue forgone	***	0-5%
Program No. 7-6-2	Acquisition Tax Reduction for Child Care Centers and Kindergartens for Daejeon City	Tax credits/Revenue forgone	***	0-5%
Total			***	0-5%

208. The Authority notes that subsidy margin for LG Chem, Ltd. is more than de-minimis.

Other producers and Exporters from Korea RP

209. Countervailing duty for all other producers/exporters from Korea RP has been determined based on the highest of the subsidy margins for the cooperating parties.

Descriptions	Subsidy Margin % of CIF	Subsidy Margin Range
Program No 1-6 as alleged by the domestic industry	***	0-5%
Other subsidies availed by the cooperating producers and exporters	***	0-5%
Total Subsidies	***	0-5%

The Authority notes that subsidy margin for LG Chem, Ltd. is more than de-minimis.

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions of the Domestic Industry

210. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- i. ISRPL had commenced its trial production in November 2013 and declared the commercial production in February 2014.
- ii. RIL had commenced trial production in October 2014 and declared the commercial production in October 2016.
- iii. Since the industry has established manufacturing in the recent period, its production and sales show a natural improvement over the injury period.
- iv. Partial improvement in performance of the domestic industry is additionally because of dumping duties imposed by the Govt. earlier.
- v. There is a difference in the delivery time for the Indian and the foreign producers which impacts the price comparability.
- vi. The profits of the domestic industry may be calculated after adjusting for underutilization of the production capacities because of new plant operations.
- vii. With fresh capacities in the country getting commercialized and optimized, imports show a natural decline in relation to the production and consumption in India. However, the Korean imports continue to lead the prices in the market.
- viii. The subject imports have prevented the domestic industry from charging reasonable price.
- ix. The landed price of imports is below the cost of sales of the domestic industry.
- x. The production, sales and the capacity utilization of the domestic industry have improved because of multiple facts – (a) the domestic industry was in nascent stage in the earlier years, (b) production process is such that the industry optimizes the production.
- xi. The capacity with the domestic industry is significant enough to force the domestic industry to sell the product in competition to the imported product.
- xii. The domestic sales have increased only because the industry has sold the product in competition to imports.
- xiii. The domestic industry has been forced to sell at a price much below its cost of production thereby significantly impacting long-term financial viability of its operations.
- xiv. The domestic industry was earning profits in 2016-17 but has started to suffer financial losses in 2017-18 which further deteriorated significantly in the period of investigation.
- xv. The cash profits and profit before interest earned by the domestic industry were positive in 2016-17 and 2017-18 but have turned negative in the period of investigation.
- xvi. In spite of the domestic industry selling at losses, the level of inventories with the domestic industry is significant.
- xvii. The domestic industry recorded a positive growth in terms of production, sales, capacity utilization and market share whereas a negative growth in respect of price parameters.
- xviii. Imports have impacted the ability of the domestic industry to raise capital as the domestic industry is operating in losses.
- xix. Applicants have made investments of more than Rs 3000 cr to set up capacities in the country.
- xx. Anti-dumping duties imposed have not been able to address the injurious effect of low-priced imports.
- xxi. Imports were necessary earlier but since the domestic industry has established itself, now the imports are unnecessary.
- xxii. The list of injury parameters provided in the CVD Rules is not exhaustive which is also accepted in the Manual. If the domestic industry has identified some other parameter showing injury to the domestic industry, the Authority should consider the same while assessing injury to the domestic industry.

- xxiii. Domestic industry has been forced to export at adverse prices which shows that it is suffering in the domestic market. The Authority should consider less remunerative exports by the domestic industry as a parameter showing injury.
- xxiv. Unremunerative prices in the export market has been noted as a sign of injury by Authority in the past investigation.
- xxv. Authority is required to consider all other actual or potential economic parameters which have an impact on the performance of the domestic industry.
- xxvi. The fact that the domestic industry is in the process of recovering from the past ill effect of dumping should be considered as a relevant injury parameter in the present case.
- xxvii. Even the European Union Law specifically require considering whether an industry is in process of recovering from the past effects of dumping or subsidization. Considering the non-exhaustive nature of various injury parameter, the Authority should consider all such other injury parameters, as were brought before the Authority.
- xxviii. The price undercutting should be determined by considering the import price and domestic price at the same point of time. Since there is significant difference in the prices within the investigation period, an average basis comparison is highly flawed. The Authority should consider monthly comparison. Further, while considering import price and selling price in a particular month, it must be ensured that the import represents those sales which were made in that month. The comparison would be highly misleading if selling price of the domestic industry in a particular month is compared with the import price which does not correspond to same month. Further, month of sale is required to be considered on the basis of date when material terms were frozen. Mere consideration of month of invoice is inappropriate. Further, merely undertaking monthly analysis is not sufficient unless both the domestic sale and export price pertain to the sale made in the same month.
- xxix. Imports have declined from all the sources. Imports from subject country are still significant in volume.
- xxx. Price suppression analysis is required to be undertaken from 2016-17 as the production in the previous years was quite low due to which the costs were high.
- xxxi. Domestic industry was forced to match the import prices in order to establish itself in the market. Negative price undercutting is due to price suppression which has been accepted by the Authority in the various investigation.
- xxxii. Domestic industry is still operating with idle capacities and is forced to undertake unviable exports and is faced with rising inventories.
- xxxiii. There is a significant gap between the targeted production and sales and the actual production and sales.
- xxxiv. The domestic industry is suffering loss before interest. Therefore, there is no reason to attribute injury to high interest cost of the domestic industry.
- xxxv. Cash profits are not adequate to ensure that business operations pertaining to the product under consideration can function smoothly.
- xxxvi. The increase in depreciation is due to reason that RIL capitalized its plant on 30th September 2016 and there was no depreciation till September 2016 in case of RIL.
- xxxvii. Domestic industry does not keep record of expenditure incurred by it on research and development at product level, nor the domestic industry has claimed any injury on this account, nor this is a prescribed injury parameter.
- xxxviii. The slowdown referred in the annual reports is in terms of volume and not prices and implies that automobile sector has not increased, as projected.
- xxxix. While injury to the domestic industry is being attributed to slowdown, the users of the subject goods are enjoying profits.
- xl. Applicants have submitted sufficient evidence why date of sale as per DGCI&S data cannot be relied upon in the present investigation. However, other interested parties have not made any claims, besides mere conjecture.
- xli. Even as per Manual, reliance can be placed on secondary source of data in exceptional cases.
- xl.ii. The raw material prices of the applicants are in line with international prices and therefore there is no reason why losses suffered can be due to transfer pricing.

- xliii. The other interested parties have not been able to bring forward any substantive evidence for any other reason of injury being suffered by the domestic industry. Therefore, there is no requirement to conduct any attributive analysis.
- xliv. Responding to argument of public interest, the domestic industry has submitted that while the domestic industry is suffering financial losses, the users of the subject goods are in profits. There is no adverse public interest involved in the present case. While referring to the public interest, the consumers are in fact talking about consumer interest. Consumers interest cannot be protected at the cost of the domestic industry suffering. Further, the impact of duties on eventual tyre would be highly insignificant.
- xliv. Anti-dumping or anti subsidy duties are not protectionist measure but are levied to check unfair trade practice.
- xlvi. Injury examination is required to be conducted for the domestic industry as a whole, and not selectively for a producer.
- xlvi. The profits earned by ISRPL are insignificant considering the capital investment made by it.
- xlvi. The other interested parties have not been able to bring forward any substantive evidence for any other reason of injury being suffered by the domestic industry.
- xlix. Responding to the submissions with regard to selling price of the domestic producers, the domestic industry has submitted that price offered by the domestic industry is provided by it in the costing formats. The same may be verified and relied upon instead of some unauthenticated source of information provided by the respondents.

G.2 Submissions of other interested parties

211. The submissions made by the interested parties with regard to injury are as follows:

- i. There is no special consideration required for time lag in imports for the purpose of undercutting. All the import transactions in the international trade require time for opening of LC, issuing of BoL, etc. The Authority in the past ADD investigations of PBR and SBR had also not considered it.
- ii. The domestic industry has not claimed material retardation because it is already established. Authority is required to evaluate only material injury.
- iii. As per Para (2) of Annexure 1, the Authority is required to consider if there has been a significant increase in the subsidized imports. However, the imports have declined in absolute terms and in relation to production and consumption.
- iv. In the CVD investigations of New Pneumatic Tyres and Castings, even when there was AD duties imposed, there was an increase in the imports. The domestic industry cannot claim that the requirements of increase in imports must be disregarded as there was ADD in force.
- v. There is no price impact on the domestic industry due to the imports. Price of subject imports are higher than the prices of the domestic industry. The import prices should be compared after addition of ADD. There is no price suppression or depression based on comparison of trends. Price of imports has increased in line with the increase in cost of sales of the domestic industry.
- vi. The loss incurred by the domestic industry for domestic sales has declined significantly over the period of injury.
- vii. Despite no increase in capacity, the interest and depreciation costs of the domestic industry have increased.
- viii. The petitioners have failed to provide data pertaining to R&D costs. However, the Annual Report of RIL for 2018-19 show that significant innovation has been undertaken pertaining to the subject goods.
- ix. The petitioners have failed to account for the injury caused due to the slowdown in the automotive industry whereas the same has been recorded in the Annual Report of RIL.
- x. Domestic industry has admitted that imports of the product from Korea has been declining due to increase in the domestic production thus clearly evidencing that domestic industry has been able to sell its production. Imports from Korea have fallen in absolute terms and in relation to production.
- xi. Import price has significantly increased in the period of investigation.

- xii. The domestic cost of sales of PUC has increased by only 21 indexed points in POI when compared to the base year (2015-16) whereas the domestic selling price of the PUC has increased by 41 indexed points during the same period. There is no price suppression.
- xiii. The selective manual approach used by the domestic industry to segregate the product into different grades is liable to falsification and is required to be revisited by the Authority.
- xiv. There is no price undercutting in the period of investigation.
- xv. The actual domestic prices of the product would be lower than the prices considered for analysis of price undercutting.
- xvi. The Authority had concluded that there is no positive evidence of lag in exports in the earlier anti-dumping investigation.
- xvii. The production, capacity utilization and the domestic sales have significantly increased.
- xviii. The domestic industry is also planning to expand their installed capacity with respect to the product by 0.15 million ton per annum. If a producer is suffering losses, it won't go for expansion.
- xix. The total sales value has increased significantly during the injury period and the period of investigation, which clearly implies that the domestic industry prices have increased.
- xx. Usual practice of RIL to use predatory pricing to enter the market, gain dominance and consequently eliminate competition.
- xxi. When compared in relation to the DI's production level of the PUC, the average inventory level has in fact declined from 12% in 2015-16 to 6% during the POI.
- xxii. The inventory-turnover ratio increased from 19 times in the base year (2015-16) to 32 times in the POI.
- xxiii. From the date of commencement of the plant, domestic industry has been able to capture a significant share of the demand.
- xxiv. The losses suffered by the domestic industry is attributable to increase in raw material cost, depreciation and finance cost payment.
- xxv. The increase in cost of raw material may also be attributable to the transfer pricing adopted by the domestic industry.
- xxvi. The annual report of the domestic industry states that the performance of the petrochemical sector has improved.
- xxvii. Economic data shared by the domestic industry pertains to the petrochemical products manufactured by it and not SBR alone.
- xxviii. Domestic industry is suffering from internal issues such as losses due to fluctuation of raw material prices, increase in depreciation of capital investments, high loan balances and the balance sheet being skewed due to heavy capital investments made by the domestic industry in the petrochemical sector, stray incidents like a major fire at the domestic industry's production facility in Vadodara, Gujarat could have also resulted in loss to the domestic industry.
- xxix. Continued loss incurred in the export market further evidence that imports from Korea RP have no impact on the loss caused to the domestic industry in the domestic operations.
- xxx. Prices of SBR are also affected by continued slump in auto sector industry.
- xxxi. Levy of duties will be contrary to the public interest.
- xxxii. Domestic industry had admitted in the oral hearing that its performance in volume and price trends is desirable.
- xxxiii. Import price has significantly increased which implies that there is no price effect. No price suppression or depression.
- xxxiv. Prices offered by domestic industry are available in the public domain for March 15. Considering them along with indexation shows that there is no price undercutting.

- xxxv. The domestic industry has provided no evidence of lag of data. Reliance cannot be placed on secondary source data as per the Manual.
- xxxvi. Authority is required to perform non attributive analysis for injury suffered by the domestic industry due to other factors.
- xxxvii. The figures as presented in the petition have no co-relation with ISRPL's Annual reports and the financial statements uploaded on the website of Ministry of Company affairs.
- xxxviii. The domestic industry cannot rely on data from 2016-17 to claim existence of injury in the period of investigation and argue that anti-dumping duty levied in past are not sufficient to address the injurious affect.

G.3 Examination by Authority

- 212. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
- 213. Rule 13 of Anti-Subsidy Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... involve an objective examination of both (a) the volume of the subsidized imports and the effect of the subsidized imports on prices in the domestic market for like products and (b) the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products. ...". With regard to the volume of the subsidized imports, the designated authority shall inter alia consider whether there has been a significant increase in subsidized imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the subsidized import on prices, the designated authority shall, consider whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of a like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of subsidy, etc. have been considered in accordance with Annexure I of the Anti-Subsidy Rules.
- 214. As regards the submission that the domestic industry is suffering due to high transfer pricing of the raw material, it is clarified that the Authority has examined the data provided by the domestic industry. It is seen that the consumption price considered for the present purposes is as per the financial records maintained by the two petitioning companies.
- 215. As regards the claim of the domestic industry and other interested parties that the domestic industry is suffering in export sales as well, it is noted that it exported at unremunerative prices due to its inability to sell in the domestic market which reflects the injury suffered by the domestic industry due to the imports.
- 216. As regards the submission that the domestic industry is affected by the slump in the automobile sector, it is noted that the demand of the subject goods has increased across the injury period.
- 217. As regards the claim that it is usual practice of Reliance Industries Limited to charge predatory pricing in order to enter market, gain dominance and consequently eliminate competition, the Authority considers that the imposition of duties will not lead to elimination of competition in the market. Rather, it will ensure fair competition in the market.
- 218. As regards the claim that the ISRPL is in profits, it is noted that injury analysis is required to be done for both the applicants constituting the domestic industry.
- 219. The Authority has taken note of various submissions made by the Domestic Industry and other Interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis undertaken ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.

G.3.1. Volume Effect of Subsidized Imports on Domestic Industry

a. Assessment of Demand / Apparent Consumption

- 220. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources.

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Sales of Domestic Industry	MT	102,155	134,936	173,699	191,325
2	Trend	Indexed	100	132	170	187
3	Other Indian Producers	MT	-	-	-	-
4	Trend	Indexed	-	-	-	-
5	Subject Imports	MT	83,358	61,549	50,843	45,914
6	Trend	Indexed	100	74	61	55
7	Imports from countries attracting ADD other than Korea	MT	38,471	37,468	27,016	23,963
8	Trend	Indexed	100	97	70	62
9	Import from Other Countries	MT	5,986	4,248	6,314	4,566
10	Trend	Indexed	100	71	105	76
11	Demand/ Consumption	MT	229,970	238,202	257,872	265,768
12	Trend	Indexed	100	104	112	116

221. It is seen that the demand for the product has increased consistently during the injury period.

b. Imports in absolute and relative term

222. With regard to the volume of the subsidized imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the subsidized imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied upon the transaction wise import data procured from DGCI&S.

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Imports from Korea	MT	83,358	61,549	50,843	45,914
2	Other imports	MT	44,457	41,716	33,330	28,529
3	Total Imports	MT	1,27,816	1,03,265	84,173	74,443
4	Subject Imports in relation to					
A	Total Imports	%	65	60	60	62
B	Trend	Indexed	100	92	92	95
C	Indian Production	%	74	38	27	21
D	Trend	Indexed	100	52	37	28
E	Indian Demand	%	36	26	20	17
F	Trend	Indexed	100	71	54	48

223. It is seen that:

- The imports from Korea in absolute terms have declined over the injury period. The domestic industry submitted that the same was because of addition of significant fresh green field production facilities in the Country.
- The subject imports have declined in relation to production and consumption in India.

224. The Authority notes that the decline in imports is attributable to the facts that the domestic industry began production in the recent period (base year was the second year of production) and the Designated Authority had earlier recommended anti-dumping duty which was imposed on 30th August, 2017. The domestic industry further explained that the production process is such that the efforts have to be made to optimize the

production. As the domestic industry kept increasing its production, the imports kept declining from Korea and other countries.

G.3.2 Price Effect of the Subsidized Imports on the Domestic Industry

225. With regard to the effect of the subject goods on the prices of the domestic industry, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price Undercutting

226. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports of subject goods from the subject country. The comparison has been done separately for 1500 series and 1700 series.

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
A			SBR-Total			
1	Landed Price	₹/MT	88,032	1,04,786	1,15,631	1,17,548
2	Trend	Indexed	100	119	131	134
3	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	***	***	***	***
5	Price Undercutting	%	***	***	***	***
6	Price Undercutting	Range	(0-10)%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%
B			SBR-1500			
1	Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	136	133	141
3	Landed Price	₹/MT	86,591	1,05,358	1,17,651	1,20,095
4	Trend	Indexed	100	122	136	139
5	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	***	***	***	***
7	Price Undercutting	%	***	***	***	***
8	Price Undercutting	Range	(0-10)%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%
C			SBR-1700			
1	Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	143	137	144
3	Landed Price	₹/MT	88,195	1,00,329	1,09,914	1,14,030
4	Trend	Indexed	100	114	125	129
5	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	***	***	***	***
7	Price Undercutting	%	***	***	***	***
8	Price Undercutting	Range	(10-20)%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%

227. It is seen that the price undercutting is negative in POI and over the injury period.

b. Price Suppression and Depression

228. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would

have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below. It is seen that the cost of sales considered for the present purposes is as per the financial records and certificate issued by the chartered accountant.

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	SBR 1500					
A	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
B	Trend	Indexed	100	117	115	120
C	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
D	Trend	Indexed	100	136	133	141
E	Landed Price	Rs/MT	86,591	105,358	117,651	120,095
F	Trend	Indexed	100	122	136	139
2	SBR 1700					
A	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
B	Trend	Indexed	100	114	113	127
C	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
D	Trend	Indexed	100	143	137	144
E	Landed Price	Rs/MT	88,195	100,329	109,914	114,030
F	Trend	Indexed	100	114	125	129
3	SBR-Total					
A	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
B	Trend	Indexed	100	115	114	121
C	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
D	Trend	Indexed	100	137	134	141
E	Landed Price	Rs/MT	88,032	104,786	115,631	117,548
F	Trend	Indexed	100	119	131	134

229. It is noted that selling price has not declined during the injury period. Thus the domestic industry has not suffered price depression.

230. However, it is noted that the average landed price of the subsidized imports has remained lower than the cost of sales of the domestic industry across the injury period. As a result, the domestic industry has been unable to charge remunerative prices and is suffering losses in both the grades. The imports of subject goods from subject country has prevented price increases which otherwise would have occurred due to increase in cost of production.

Price underselling

231. The Authority has also examined price underselling if any, suffered by the domestic industry on account of dumped imports of subject goods from the subject countries. It is noted that the landed value of imports of subject goods from subject countries is significantly below the non-injurious price of the domestic industry resulting in price underselling: -

Particulars	Unit	
Import Volume	MT	45,914
Non-Injurious Price (NIP)	Rs/MT	***
Landed Value	Rs/MT	117548
Price Underselling/Injury Margin	Rs/MT	***

Price Underselling/Injury Margin	%	***
Price Underselling/Injury Margin	Range	0-10%

G.3.3. Economic Parameters of the Domestic Industry

232. Annexure I to the Anti-Subsidy Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-Subsidy Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, ; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, Capacity, Capacity utilization and Sales

233. The position of the domestic industry over the injury period with regard to production, capacity, capacity utilization, domestic sales and export is as under:

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	Capacity	MT	2,61,000	2,61,000	2,61,000	2,61,000
2	Trend	Indexed	100	100	100	100
3	Production	MT	1,13,317	1,61,581	1,88,344	2,23,343
4	Trend	Indexed	100	143	166	197
5	Capacity Utilization	%	43%	62%	72%	86%
6	Trend	Indexed	100	143	166	197
7	Domestic Sales	MT	1,02,155	1,34,936	1,73,699	1,91,325
8	Trend	Indexed	100	132	170	187

234. It is seen that-

- One of the constituents of domestic industry declared its commercial production in the beginning of the injury period.
- The domestic industry has capacity to cater a significant share of the demand of the subject goods in India. The domestic industry submitted that it can meet entire demand of the product in the Country, if demand being met through duty free imports is excluded.
- Production, sales and the capacity utilization of the domestic industry shows improvement over the period. The same is because of the fact that the petitioners were in nascent stage in the earlier years. Domestic industry submitted that given capacities created by the domestic industry and production compulsions, the domestic industry has no option but to benchmark its prices with imports and sell the product in the market.

b. Market Share

235. Market share of the domestic industry over the injury period is shown in table below-

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Subject Country	%	36%	26%	20%	17%
2	Trend	Indexed	100	71	54	48
3	Other Countries attracting ADD other than Korea	%	17%	16%	10%	9%

4	Trend	Indexed	100	94	63	54
5	Other Countries	%	3%	2%	2%	2%
6	Trend	Indexed	100	69	94	66
7	Domestic Industry	%	44%	57%	67%	72%
8	Trend	Indexed	100	128	152	162
9	Total	%	100%	100%	100%	100%

236. It is seen that the market share of the domestic industry has increased with the increase in production, sales and imposition of ADD. The share of subject imports in demand has reduced. However, share of Korea is significant, considering the share of various countries.

c. Profitability, return on investment and cash profits

237. Profitability return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below.

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	137	134	141
3	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	115	114	121
5	Profit/(Loss)	₹/MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	(100)	(21)	(27)	(31)
7	Profit/(Loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	(100)	(28)	(46)	(59)
9	Cash Profits	₹/MT	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	(100)	16	13	(1)
11	Cash Profits	₹ Lacs	***	***	***	***
12	Trend	Indexed	(100)	21	23	(2)
13	PBIT	₹/MT	***	***	***	***
14	Trend	Indexed	(100)	2	(13)	(7)
15	PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
16	Trend	Indexed	(100)	3	(22)	(14)
17	ROCE	%	***	***	***	***
18	Trend	Indexed	(100)	3	(23)	(14)

238. It is seen that-

- The domestic industry has been suffering financial losses over the injury period.
- Loss per unit of the domestic industry decreased in the year 2016-17 but increased in the following year and in POI.
- The losses of the domestic industry have increased by 26% in the period of investigation as compared to the losses of previous year.
- The domestic industry suffered cash losses in the beginning. It started earning cash profits from 2016-17. The domestic industry once again suffered cash loss in the POI.

- e. The domestic industry had negative return on capital employed in the base year. Its ROI improved thereafter, and the domestic industry earned positive ROI in 2016-17. The domestic industry however suffered negative ROI in 2017-18 and POI.
- f. As regards the argument that injury to the domestic industry is due to high interest and depreciation cost, it is seen that noted that domestic industry has recorded cash loss as well as a loss before interest. Therefore, the decline in the profits in the POI cannot be due to increase in the interest and depreciation cost. Further, it is also seen that one of applicant companies commenced commercial production in the beginning of the injury period, leading to increase in the depreciation costs.

d. Employment, Wages and Productivity

239. The information relating to employment, wages and productivity is as per below table-

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	No of Employees	Nos	320	329	339	338
2	Trend	Indexed	100	103	106	106
3	Productivity per day	MT/DAY	324	462	538	638
4	Trend	Indexed	100	143	166	197
5	Productivity per Employee	MT/Nos	354	491	556	661
6	Trend	Indexed	100	139	157	187
7	Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	103	112	124
9	Salary & Wages	₹/MT	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	72	67	63

240. It is seen that: -

- a. Number of employees with the domestic industry has marginally increased over the injury period.
- b. Productivity per day and per employee has increased over the injury period.
- c. Salary and wages have also increased over the injury period but as the production of the domestic industry increased, per unit cost on this account declined. Therefore, wages could have not impacted the profitability of the domestic industry.

e. Inventories

241. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Opening Stock	MT	18,869	7,632	16,587	9,808
2	Closing Stock	MT	7,632	16,587	9,808	16,871
3	Average Inventory	MT	13,251	12,110	13,198	13,340
4	Trend	Indexed	100	91	100	101

242. It is seen that the average inventories with the domestic industry declined in 2016-17 but have increased towards the end of period of investigation. It is seen that the domestic industry undertook significant exports at losses in order to prevent pile up of inventories. Despite this, the closing inventories in the POI increased once again. Further, had the domestic industry not undertaken additional exports, the inventories with the domestic industry would have been higher.

f. Growth

243. The trend of volume and profit parameters of the is as per table below-

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19
1	Production	Y/Y	43%	17%	19%
2	Domestic Sales	Y/Y	32%	29%	10%
3	Market Share	Y/Y	28%	19%	7%
4	Profit/(Loss)	Y/Y	72%	-68%	-26%
5	Cash Profits	Y/Y	121%	8%	-110%
6	PBIT	Y/Y	103%	-831%	39%
7	ROCE	Y/Y	103%	-848%	41%

244. It is seen the domestic industry's growth in terms of production, sales and market share was positive over the injury period. However, whereas growth in profits, cash profits and ROI was largely positive in 2016-17, the same became negative in the POI. The domestic industry continued to suffer financial losses and negative ROI, even after establishing itself fully in the market in respect of product and volumes.

g. Ability to Raise Capital Investment

245. The domestic industry has been suffering financial losses across the injury period. With the competition being faced by the domestic industry because of the subsidized imports, the operations of the product has impacted affecting product's ability to raise capital investment.

h. Injury margin for cooperative producers/exporters

246. The injury margin for cooperative producers/exporters are evaluated as under:

Producer/Exporter	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
	US \$/MT	US \$/MT	US \$/MT	%	Range
LG Chem. Ltd.	***	***	***	***	0-10
Kumho Petrochemicals Ltd	***	***	***	***	0-10
Others	***	***	***	***	30-40

i. Conclusion on Injury

247. On the basis of information on record, the Authority concludes on the injury to the domestic industry as mentioned below.

- Imports of the product under consideration have declined over the period, in both absolute terms and in relation to production and consumption in India.
- The industry commenced commercial production recently (ISRPL in February 2014 and RIL in October 2016). As the domestic industry increased production (and resultantly, domestic sales), the subject imports declined. However, the volume of imports is significant enough to cause adverse effect on the prices of the product in the market and consequently the domestic industry.
- Korean imports command largest share in imports in India.
- The price undercutting on the basis of methodology followed by the domestic industry is negative.
- The landed price of imports is below cost of production of the domestic industry.
- The subject imports have suppressed the prices of the domestic industry. The domestic industry has not been able to increase its prices in proportion to increase in the costs.
- The domestic industry suffered financial losses over the entire injury period. The financial losses suffered by the domestic industry declined in 2016-17 and increased thereafter significantly upto POI.

- h. Performance of the domestic industry improved in 2016-17 and deteriorated thereafter upto POI in respect of cash profits and ROI.
- i. While the petitioning domestic industry has been able to achieve a positive growth in volume parameters, the growth was negative in respect of price parameters.
- j. Inventories with the domestic industry fluctuated over the injury period and increased once again towards end of the POI.

G. CAUSAL LINK

248. The Authority has examined whether other know factors could have caused injury to the domestic industry as follows-

a. Volume and prices of imports from third countries

b. Imports from other major countries are already subject to anti-dumping duties. Landed price of imports from Korea is lowest as compared to imports from rest of world, after adding prevailing customs duty and anti-dumping duty.

c. Changes in the pattern of consumption

249. There have been no material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices

250. The Authority notes that there is no trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry.

e. Change in technology

251. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a possible factor of injury.

f. Export performance

252. The Authority has considered data for the domestic operations only. Any possible deterioration in the export performance of the domestic industry, therefore, cannot be a cause for the injury to the domestic industry.

g. Performance of other products

253. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, performance of other products produced and sold by the petitioners are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

H. Conclusion on Causal Link

254. The Authority concludes as below.

- a. Subsidized imports from subject country are entering into India in substantial volumes.
- b. The imports have decreased both in relative and absolute terms. However, imports occupy a significant share in the market to cause adverse price effect.
- c. The landed value of subject goods from subject country is not only below the NIP but also the cost of sales of the domestic industry during the injury period.
- d. Landed price of imports from various countries shows that the selling price of the domestic industry are impacted by the landed price of Korean imports.
- e. Performance of the domestic industry deteriorated once again in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

I. POST DISCLOSURE COMMENTS

Comments by Domestic industry

255. Following submissions have been made by domestic industry on the disclosure statement issued by the Authority.

- a. Domestic industry has not filed comments on the disclosure, requesting disclosure of following information
 - i. Format-B, Format-D normation;

- ii. Calculations of capital employed.
- iii. Details of expenses allowed & disallowed.
- iv. The linked files have not been given and the NIP given is a paste special. With this information and disclosure, it is not possible for the domestic industry to understand what the Designated Authority has accepted/rejected out of the various information provided by the domestic industry.
- b. Disclosure of NIP requires disclosing complete files of the domestic industry.
- c. Butadiene consumption price of RIL was accepted by Authority in Anti-dumping investigation concerning imports of PBR and Anti-dumping investigation concerning imports of SBR and in all PTA cases.
- d. It is inconsistent and discriminatory approach to allow consumption price in one case and reject in other case.

Comments by Other interested parties

256. Following submissions have been made by the other interested parties on the disclosure statement issued by the Authority.

Product under consideration

257. Solution SBR is beyond the scope of the present investigation.

Miscellaneous

258. It is an established principle that the period of investigation cannot be older than 6 months on the date of initiation

Subsidy Programme

General

259. The extant laws and regulations concerning Countervailing Duty ('CVD') investigations along with the relevant jurisprudence aptly provide that a DS should contain the findings of the DGTR on the essential facts which would form the basis for the decision whether or not to apply definitive measures (*see*, Rule 18 of Indian CVD Rules). However, The Authority has given its conclusion in the subsidy margin determination.
- Program 1
260. Merely because banks involved in the corporate restructuring are government- owned, these banks do not become "public bodies". No evidence has been provided to show that banks are under effective control, regulation and supervision of the Government of Korea.
261. Government owned banks acted in same way as private commercial banks. Terms of participation are on commercial basis determined by market forces and required agreement of 100% creditors. Therefore, the decision was purely commercial.
262. Authority has not supported examination to show that these banks have participated in the corporate restructuring process on the basis of government instruction. KDB participated only as an ordinary creditor.
263. USANCE L/C limit was increased in proportion to Kumho's existing bond ratio for each creditor bank. Actual applied interest rate of KDB's USANCE interest rate was higher than other commercial banks. There is no benefit.
264. Additional issuance of short-term loans is a common practice followed by all commercial banks and not typical a measure taken by a public body. Further, the applied interest rates at which second creditor's agreement was entered into is for all commercial banks.
265. Purchase of convertible bond was not mandatory but optional to creditors and IBK and KEXIM did not purchase any convertible bond. Entitlement to purchase convertible bond was either relinquished in favour of other creditors or foregone.
266. Purchase of convertible bonds is a commonly resorted business decision made in the ordinary course of trade by commercial banks as part of the restructuring process.
267. Financial support was provided only as necessary to reasonably recover from bankruptcy. Banks decision was purely commercial decision supported by due diligence report issued by independent consultancy M/s PricewaterhouseCoopers.
268. Kumho underwent restructuring much before period of investigation, and all repayment obligations arising out of restructuring process were also resolved prior to period of investigation. Therefore, any benefit to the Respondent cannot be countervailed in the present investigation.

269. CRPA 2016 had not even been enacted when Kumho initiated and completed corporate restructuring. Therefore, Authority's stand that program was governed by Corporate Promotion Act 2016 is a complete misstatement.
270. Authority has failed to prove that terms of financing offered were based on a non-commercial basis. Terms of financing provided to Kumho by its creditors indicate that corporate restructuring was on commercially reasonable basis.
271. Program includes large number of enterprises spreading across multiple sectors and is not limited to certain enterprises or sectors.
Program 3
272. Funding program under Industrial Technology Innovation Promotion Act ('ITIPA') includes a large number of Research institutions, universities, institutions, organizations, enterprises, etc that are spread across multiple sectors and is thus not limited to certain enterprises or sectors.
Program 4
273. Under program 4, tax benefits and long-term loan program are spread across multiple sectors and available to all companies and individuals who meet eligibility criteria. There is no specificity.
Program 5
274. Program No. 5 includes a large number of enterprises that spread across multiple sectors and is thus not limited to certain enterprises or sectors.
Program 6
275. Program – 6 is in nature of export subsidy and Authority has countervailed the same. This is in direct contradiction to its stand that that no article shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization.
Program 7
276. Benefit under Program 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.8 and 7.3 is available to all enterprises irrespective of sector, region or industry and is thus not countervailable.
277. Program No. 7.1.2 is an investment decision in consistent with usual investment practice in resource development sector. If the business succeeds, a portion of the profit (based on the loan) should be returned to the GOK.
278. Government of India maintains programs which mandates workplaces having 50 employees or more to establish a crèche and provides contribution. If Authority finds Program No. 7.1.3 to be countervailable, similar schemes run by Government of India may also be countervailed before other trade remedial forums abroad.
279. Grant given to under Program No. 7.1.4 has not been found countervailable for LG Chem and Kumho as it is directly transferred to account maintained for the infant care center. Mechanism is mandated under law and applies to all beneficiaries under. Thus, program should not be countervailable against POSCO or any other exporters/ producers from GOK.
280. There is no benefit under Program No. 7.1.5 as it only provides relief to Korean corporate taxpayer from incidence of double taxation on corporate tax paid on income earned in foreign jurisdictions.
281. Authority has only calculated subsidy margin in Program 7.1.5 at the overall level, however, subsidy margin must be attributed to exports of the product by POSCO to India. The resulting subsidy margin for POSCO would be negligible.
282. Loans under Program No. 7.1.7 are provided for conducting general operations and are not related to production of subject goods.
283. Authority has erred in calculation of subsidy margin under the Program No. 7.1.7 for POSCO.
284. Programs no. 7.5 are social welfare measures pursued by government and there is no benefit accruing to the business, industry, or entity with regard to its business activities.
Misc.
285. Entire subsidy margin determined cannot be attributed to entire export volume produced by KKPC and exported to India during the period of investigation. Subsidy margin for both export channels needs to be separately determined and allocated over the export volumes through each channel and the weighted average subsidy margin must be awarded by the Authority to KKPC.
286. The disclosure statement is silent on how domestic industry has satisfied minimum evidentiary standard prescribed under Article 11.2 of the ASCM reflected in in Rule 6(3)(b) of the Indian CVD Rules, 1995.

287. Impugned programs/ schemes lack relevant and sufficient evidence and should not be found to be countervailable. Programs fail to meet the requirements under the relevant laws to constitute countervailable subsidies. None of the programs/schemes meet the said standards of specificity.
288. There is an obligation to consider comments of the responding interested parties to the disclosure statement. In the present case, Authority has skipped essential requirement and has concluded on countervailability without giving an opportunity to the respondents to comment on the facts being considered.
289. DGTR has acknowledged that existing ADD on PUC remedies distortion in the export price caused by export subsidies.

Injury and causal link

290. There is no merit in the observation that the imports of the PUC from Korea RP remain significant.
291. Applicants being in nascent stage in earlier years is irrelevant to the examination of the domestic industry's operational performance.
292. All injury indicators except profitability in disclosure statement itself establish that domestic industry has not suffered any injury. As held by CESTAT's in Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) v. Designated Authority, mere impact on profitability is insufficient to make conclusion regarding material injury.
293. Examination done by Authority to establish absence of inflated transfer pricing is insufficient. Authority in calculation of NIP should compare raw material prices claimed by domestic industry with raw material prices prevalent in market.
294. Injury on account of export sales is not subject to determination in a domestic trade remedial investigation. Scope of examination of trade restrictive effects is restricted within domestic market.
295. In Indian Spinners Association v. Designated Authority, CESTAT and Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) v. Designated Authority held that a 22% return cannot be uniformly applied across sectors and is subject to variation. Return of 22% is common in synthetic rubber manufacturing industry

Examination by Authority

296. On the submission made by the domestic industry on computation of non-injurious price and disclosure thereof, non-injurious price has been determined **and disclosed** in accordance with Annexure III of the Rules and the consistent practice of the Authority.
297. It has been contended that the determination lacks sufficient evidence. It is noted that the applicant had provided sufficient and adequate evidence of subsidies to justify initiation. The Authority provided ample opportunity to the Government of Korea for consultation. However, the Government of Korea did not respond to the same. The claims of the respondent were therefore left undisputed. The Authority initiated the investigation only after being satisfied about the minimum evidentiary standards. The questionnaire response filed by the participating producers and the Government of Korea too shows existence of subsidies. Specificity and countervailability of the program has already been disclosed in the disclosure statement and the present findings. It may also be added that after the issuance of disclosure statement, confidential copy of methodologies of determination of subsidies margin proposed in the disclosure statement, along with subsidy margins were disclosed to both the producers and exporters from subject country, and comments received from them are examined in this finding.
298. With regard to the argument pertaining to the use of the word 'determined' by the Authority in the disclosure statement, the Authority notes that the usage of the phrase "determine" does not mean that it is a final determination. When read with Rule 16, the Authority has only disclosed the essential facts and proposed determinations and has invited comments from all interested parties on all aspects of a disclosure statement. Therefore, "determination" in its true sense shall be final only when the final findings are issued and not at the stage of disclosure statement.
299. As regards the submission that the banks are not public bodies, it is noted that the banks are acting at the direction or superintendence of agency who are government owned or controlled. With regard to the argument pertaining to KKPC not availing a benefit under the Corporate Restructuring Program, the Authority has provided the calculation of benefit availed by KKPC in detail in the relevant paragraphs of the final findings.
300. As regards specificity of corporate restructuring program, it has been admitted that the sole purpose of the program was to provide financial support to reasonably recover from bankruptcy. The benefit was not available to everyone but only limited to certain specific entities thus making the program specific in nature.
301. With regard to the argument pertaining to KKPC not availing a benefit under the Corporate Restructuring Program, the Authority has provided the calculation of benefit availed by KKPC in detail in the relevant paragraphs of the final findings.

302. With regard to argument that subsidy margin for both export channels needs to be separately determined and allocated over the export volumes through each channel and the weighted average subsidy margin must be awarded by the Authority to KKPC, it is noted that the Authority has determined weighted average subsidy margin after allocating subsidy margin through each channel.
303. With respect to claims that some of the subsidies taken into account by the Authority are export subsidies, and thus they could not be countervailed, it is noted that all subsidies taken into account for the purpose of determining the subsidy margins are production subsidies only, and no export subsidies have been taken into account by the Authority.
304. It is noted that under the Program 7.1.5 corporate tax exemption program, an eligible enterprise gets tax credit on various investment expenses incurred by it. The information with respect to this program has been taken from the response filed by the Government of Korea RP and POSCO. The response filed by POSCO shows that benefit is received by them under this subsidy program.
305. The present investigation has not shown any export subsidies received by the Korean producers. The CVD margins determined by the Authority does not contain any margin on account of possible export subsidies. The Authority has taken note of existence of anti-dumping duty on the product under consideration. It is noted in this regard that the existing anti-dumping duty is at the level of margin of dumping. The injury margin determined in the anti-dumping investigation was significantly higher than the dumping margin determined, and anti-dumping duty imposed. Since the injury margin determined was higher, the domestic industry was not protected to the extent of injury suffered by the domestic industry from imports, as the law restricts imposition of anti-dumping duty only to the extent of dumping. In such situations, the domestic industry is entitled to protection to the extent of margin of subsidies, in case it is found that the foreign producers are getting countervailable subsidies. However, while the CVD cannot exceed the margin of injury in view of the bar under the Act and of the Rules. It is also considered desirable that the sum of anti-dumping duty and CVD does not exceed the margin of injury now established.
306. The table below shows the subsidy margin & injury margin assessed in the present investigation and dumping & injury margin determined in the previous investigation. It is seen that the sum of CVD margin and dumping margin is lower than the injury margin assessed now in the present CVD investigations or determined at the time of earlier Anti-dumping investigations on the same product from Korea RP.

Particulars	Dumping margin (DM) (US\$/MT)	Dumping margin %	Subsidy margin (SM) (US\$/MT)	Subsidy margin%	DM and SM margin (US\$/MT)	D.M% + SM%	Injury Margin AD investigations (US\$/MT)	Injury margin AD investigation %	Injury margin Subsidy investigation (US\$ MT)	Injury margin Subsidy investigation %
Kumho	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
LG Chem	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Others	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

307. In view of the above, the Authority concludes that it is appropriate to impose CVD in the present case. Further, existence of anti-dumping duty on the product and imposition of CVD would not lead to dual remedy. The anti-dumping duty imposed and CVD proposed to be imposed are intended to address different situations. The total quantum of protection does not exceed the injury margin determined by the Authority.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

308. The Authority notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of countervailing duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. It is recognized that the imposition of countervailing duty might affect the cost of the subject goods. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the countervailing measures, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry by the imports of subsidized subject goods. On the contrary, imposition of countervailing measures would remove the unfair advantages gained by subsidization and create level playing field.

K. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

309. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- a. The product under consideration that has been exported to India from the subject country is subsidized.

b. The domestic industry has suffered material injury.

c. Material injury has been caused by the subsidized imports of the subject goods from the subject country.

310. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of subsidy, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into subsidy, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Subsidy Rules, the Authority is of the view that imposition of duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-subsidy duty on imports of subject goods from the subject country.

311. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of countervailing/anti-subsidy duty equal to the lesser of margin of subsidy and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-subsidy/countervailing duty on imports of subject goods, originating in or exported from subject country, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

DUTY TABLE

SN	Heading/ Sub heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount as a % of CIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	400219	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Korea RP	Any Country including Korea RP	Kumho Petrochemical Co., Ltd	1.89
2	-do-	-do-	Korea RP	Any Country including Korea RP	LG Chem, Ltd.	2.04
3	-do-	-do-	Korea RP	Any Country including Korea RP	Any producer other than SN 1 and 2 above	4.06
5	-do-	-do-	Any country other than Korea RP	Korea RP	Any	4.06

CIF value means the assessable value as determined under section 14 of Customs Act, 1962 (52 of 1962).

312. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

313. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. & Director General